S.O. No. 69(E)
28.9.1983

रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1983/आश्विन 6, 1905
No. 428] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 1983/ASVINA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1983

का. आ. 691(अ).—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या-61) की धारा 5 की उपधारा (2) (डी) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने हेतु दिल्ली नगर निगम के पार्षदों तथा नगर प्रमुखों द्वारा अपने में से सर्वश्री बलवान सिंह सोलंकी, हरिचन्द वर्मा, मुकुन्द लाल विन्द्रा तथा श्री आर. के. त्यागी को चुन लिया है ।

[सं. 5(1)/79-एम. सी.]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

ADV. COUNCIL

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Delh, the 28th September, 1983

S.O. 691(E).—It is hereby notified that in pursuance of Clause (d) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957(61 of 1957), the councillors and aldermen of the Municipal Corporation of Delhi have, from among themselves, elected S|Shri Balwan Singh Solanki, Hari Chand Verma, Mukand Lal Bindra and R. K. Tyagi to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 5(1)|79-M.C.]
NATHU RAM, Secy.
Delhi Development Authority

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA.

No.18011(28)/67-UD
Government of India
Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Department of Health & U.D.)

New Delhi, dated the 14th Feb.'69

_N_O_T_I_F_I_C_A_T_I_O_N_

In exercise of the powers conferred by sub-Section 2 of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) and in supersession of Government of India, in the Ministry of Works, Housing and Supply Notification No.18011(10)/66-UD (Vol.II) dated the 1st May, 1967, the Central Government hereby directs that the powers of that Government under the provisions of the Act, mentioned in the schedule hereto annexed, shall, subject to the control of the Central Government and until further orders, also be exercised by the Administrator of the Union Territory of Delhi, provided that the powers mentioned in item 2 of the Schedule shall be exercised in each case with the prior approval of the Central Government.

_S_C_H_E_D_U_L_E_

1. Clause (a) of Section 2.
2. Sub-Sections 3(e), 3 (d) and (9) of Section 3.
3. Sub-Section (1) of Section 4.
4. Sub-Section (2) of Section 5, except Clause (g).
5. Sub-Section (1) of Section 12.
6. Section 15.
7. Sub-Section (3) of Section 35.
8. Section 36.
9. Section 39.
10. Sub-Section (2) of Section 42.
11. Section 57.

Sd/-
(K.M.L.GUPTA)
Under Secretary to the Govt.of India.

To

The General Manager,
Government of India Press,
New Delhi.

(Land & Building Department)

Vikas Bhawan,
New Delhi.

No. F.5/1/79/I&B/ Dated the 21st August,79

N O T I F I C A T I O N.

In exercise of the powers of the Central Government vested in it under clause(b) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957,(No.61 of 1957) and delegated to him under sub-section(2) of Section 52 of the said Act by that Government vide Notification No.18011(28)'67-UD dt. 14.2.69, the Administrator/ Lt.Governor of the Union Territory of Delhi is pleased to nominate Shri M.N.Buch, Vice-Chairman, Delhi Development Authority, in place of Shri M.S.Mehta, Architect, Municipal Corporation of Delhi, on the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

(Dharam Dutt)
Deputy Secretary (I&B)
21.8.79

Copy sent for information to :

1. Secretary to Lt.Governor, Rajniwas, Delhi.
2. Sh.M.N.Buch,Vice-Chairman,DDA,18 Teen Murti Lane,New Delhi.
3. Sh.M.M.Rana, Chief Architect, CPWD., 151, Chanakyapuri, New Delhi.
4. Sh.S.I.Chadha,Municipal Health Officer, M.C.D. Delhi.
5. Sh.Baksi Ram, Councillor, M.C.D. 433/1,Vir Savarkar Block,Shakarpur Extn.Delhi-51.
6. Sh.Mehar Chand,Councillor, MCD.,116,Haiderpur,Delhi.
7. Sh.J.N.Bhandari, Councillor,MCD.,B-13,Kirti Nagar, New Delhi.
8. Sh.Dayal Singh,Councillor,MCD., 1403,Gali No.13, Govindpuri,New Delhi.
9. Sh. Hari Kishan Pathak, 23 Mithal Bhai Patel House,New Delhi-1.
10. Smt.Sumitra Charat Ram, 26 Sardar Patel Marg, New Delhi
11. Shri R.L.Sahdev, A-203,Defence Colony,New Delhi.
12. Shri J.S.Marya, Dir-General (R&D),M/o Transport, and Shipping,NewDelhi.
13. Sh.R.K.Dhingra, Addl.General Manager (Telephone),Eastern Courts,Inspection Qurts,New Delhi.
14. Sh.A.N.Singh,Member(Hydro-Elect)Central power Commission,West Block,2-R.K.Puram,New Delhi.

contd.....2/-

15. Shri J.S.Menavalan, Director General, Roads & Cantt. M/O Defence, New Delhi.

16. Shri Kishore Lal, Member of Parliament, 34-35, Mukherji Nagar, Delhi-9.

17. Shri Shiv Narain Sarsoni, Member of Parliament 18, Feroz Shah Road, New Delhi.

18. Sh. Khurshid Alam Khan, Member of Rajya Sabha, 2, Moti Lal Marg, New Delhi.

(Dharam Dutt)
Deputy Secretary (L&B)
21.8.79.

S.O. No. 404 (E)
20.5.1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245] नई दिल्ली, सोमवार, मई, 20, 1985/वैशाख 30, 1907
No. 245] NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 1985/VAISAKHA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1985

का. आ. 404(अ) :—दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन विनियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (सचिव और मुख्य लेखा अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम 1984 कहा जाए।

2. परिभाषाएं :—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में—

(1) "अधिनियम" से अभिप्राय है—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61)

(2) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है—अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण।

(3) "सलाहकार परिषद्" से अभिप्राय है—अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित परिषद्।

(4) "मुख्य लेखा अधिकारी" से अभिप्राय है—अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य लेखा अधिकारी।

(5) "सचिव" से अभिप्राय है—अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सचिव।

(6) इन विनियमों में जो शब्द और पद परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनसे वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने नियमों या विनियमों में है।

3. सचिव की शक्तियां :—सचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, यथा :—

(1) कार्यालय के प्रधान के रूप में कार्य करना और उन शक्तियों का प्रयोग करना जो सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के प्रधान द्वारा प्रयोक्तव्य हों;

(2) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्य-विधि या अनुदेशों के अनुसार ग एवं घ समूहों के पदों पर नियुक्तियां करना;

(3) समूह ग एवं घ के कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करना;

(4) ऐसे निर्बन्धनों और परिसीमाओं के अध्यधीन, जो प्राधिकरण सामान्य आदेश द्वारा लगाए, स्टेशनरी की वस्तुओं, फार्मों, फर्नीचर, बिजली के सामान, उपकरण, यंत्र और कार्यालय-उपस्कर की अन्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति या खरीद के व्यय की स्वीकृति देना ;

(5) प्राधिकरण की ओर से प्राधिकरण या किसी उस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए लेन-देन के संबंध में करार, पट्टा-विलेख, विक्रय-विलेख और अन्य दस्तावेज निष्पादित करना, जिसे वे लेन-देन स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों; और

(6) वाद या विधि कार्यवाही संस्थित करना और प्राधिकरण या उसके पूर्ववर्ती निकायों द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए गए वाद या संस्थित की गई विधि कार्यवाही की प्रतिरक्षा करना और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित शर्तों पर उन्हें वापस लेना या उनके संबंध में समझौता करना।

4. सचिव के कर्त्तव्य :—सचिव निम्नलिखित सभी कर्त्तव्यों या किसी भी कर्त्तव्य के लिए उत्तरदायी होगा, यथा :—

(1) प्राधिकरण और सलाहकार परिषद् तथा उन समितियों की बैठकें निश्चित करना, जो प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए की उप-धारा (1) के अन्तर्गत समय-समय पर गठित की जाएंगी, और उक्त निकायों की बैठकों की कार्यवाही की कार्यावलियों और कार्यवृत्तों को तैयार करना तथा उन्हें जारी करना;

(2) केन्द्रीय सरकार; प्राधिकरण, सलाहकार परिषद् या उप नियम (1) में उल्लिखित समितियों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा मांगे गए कागज-पत्रों या सूचना को अधिप्राप्त करना और निर्धारित अवधि, यदि कोई हो, के अन्दर उन्हें भेजना;

(3) अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन सुनिश्चित करना;

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विविध) नियम, 1951 के अनुसार प्राधिकरण के कार्यकलापों पर रिपोर्ट तैयार करना और प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना;

(5) उपाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए सामान्य या विशेष अनुदेशों के अध्यधीन निर्धारित विधि से और निर्धारित सीमा तक प्राधिकरण के कार्य-कलापों का प्रचार करना;

(6) प्राधिकरण में पदों के सृजन के प्रस्ताव और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सूचना देना;

(7) पदों के सृजन या उन्हें जारी रखने और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में मुख्य लेखा अधिकारी को सूचना भेजना और अन्यथा स्टॉफ की मांग पर निगरानी रखना;

(8) प्राधिकरण के कार्यालय के विभिन्न विभागों, शाखाओं और अनुभागों के साथ सम्पर्क बनाए रखना और उनके बीच समन्वय सुनिश्चित

(9) पदों के सृजन और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों पर और सामान्यतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनकी सेवा-शर्तों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में परामर्श देना ;

(10) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने से संबंधित सभी मामलों और उनके कल्याण से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना;

(11) इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उचित अनुशासन बनाए रखा जाता है और कार्य विधिवत् और कुशलतापूर्वक किया जाता है, प्राधिकरण के स्टाफ का सामान्य पर्यवेक्षण करना;

(12) अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव रखने संबंधी कार्रवाई आरम्भ करना;

(13) कार्यालय के कुशल संचालन के लिए अपेक्षित मूल्य और मात्रा में स्टेशनरी की वस्तुओं, फर्नीचर, फार्म, बिजली के सामान, उपस्कर, यन्त्रों और अन्य कार्यालय उपस्कर की समय पर अधिप्राप्ति और सप्लाई की व्यवस्था करना और दैनिक कार्यालय प्रबन्ध से संबंधित सभी मामलों का प्रभावी पर्यवेक्षण करना।

5. मुख्य लेखा अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, यथा : —

(1) प्रस्तावित या निष्पादित किसी वित्तीय लेन-देन से संबंधित किसी मामले या उन मामलों के संबंध में, जिन पर वह स्वयं कुछ समय के लिए कार्यवाई कर रहा हो, प्राधिकरण के विभागों, शाखाओं या अनुभागों से आवश्यकतानुसार रिकार्ड या सूचना मंगवाना और उनकी जांच करना या किसी निरीक्षण-दल द्वारा उसकी जांच करवाना;

(2) प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी की अभिरक्षा में रखी हुई प्राधिकरण की नकदी का प्रत्यक्ष सत्यापन करना या इस मामले में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से उसका प्रत्यक्ष सत्यापन करवाना,

(3) सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि जैसी भी स्थिति हो, से प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस किए जाने वाले और वापस न किए जाने वाले अग्रिम स्वीकृत करना;

(4) लेखे रखने और उसे सौंपे गए अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त स्टाफ प्राप्त करना और लेखा विभाग या उन अन्य विभागों, शाखाओं या अनुभागों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक पदों को भरने के लिए उपाध्यक्ष के निदेशों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर उचित कार्मिक प्राप्त करना, जिन्हें रुपए-पैसे का हिसाब रखने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कार्य सौंपा गया हो; और

(5) प्राधिकरण अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की जाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

6. मुख्य लेखा अधिकारी के कर्त्तव्य वह निम्नलिखित [illegible] पालन करेगा, यथा : —

[illegible] प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों व [illegible] को [illegible] वित्त वर्ष के संबंध में नियमों [illegible] और अवधि के अन्दर [illegible] को तैयार करना [illegible];

[illegible] लेन-देन सहित प्राधिकरण के लेखों और अन्य सम्बद्ध रिकॉर्ड तथा मासिक लेखों एवं वार्षिक लेखा विवरण का उचित रख-रखाव उस रूप में सुनिश्चित करना, जिसमें केन्द्रीय सरकार भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के परामर्श से नियमों द्वारा निर्धारित करेगी;

(3) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त या लिए गए ऋणों के रजिस्टर का रख-रखाव निश्चित करना और निक्षेप निधि, यदि चालू हो, के लिए इन ऋणों का रजिस्टर रखना;

(4) बजट अनुमान के अनुसार व्यय की प्रगति पर नजर रखना और अर्थोपाय स्थिति पर नियंत्रण रखना;

(5) लेखा और बजट से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना और सामान्यतः वित्तीय नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(6) उसके पास भेजे गए व्यय के सभी प्रस्तावों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देना और प्राधिकरण की देयताओं पर नजर रखना तथा इस बात को देखना कि प्राधिकरण के वित्तीय लेन-देन के संबंध में लागू नियमों और आदेशों का पालन किया जाता है;

(7) प्राधिकरण की अधिशेष निधि को लाभकारी ढंग से लगाने के लिए सलाह देना और लगाई गई पूंजी का लेखा रखना और निवेशों की परिपक्वता पर नजर रखना;

(8) प्राधिकरण के लेखा विभाग और प्राधिकरण की उन अन्य शाखाओं या अनुभागों के स्टाफ की मांग के बारे में सलाह देना, जिन्हें वित्तीय लेन-देन का हिसाब रखने का कार्य पूर्ण या आंशिक रूप से सौंपा गया हो;

(9) प्राधिकरण के [illegible] और कर्मचारियों की छुट्टी, वेतन [illegible] सेवा शर्तों को प्रभावित [illegible] की स्वीकार्यता [illegible]

(10) इस [illegible] समय-[illegible] वार्षिक [illegible] किया [illegible] उसकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट [illegible] का प्रस्तुत किया जाता है।

[illegible] (149)/[illegible]

[illegible] बी. सी. [illegible]

[illegible] प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 20th May, 1985

NOTIFICATION

S.O. 404(E) :—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 57, read with sub-section (1) of section 4 of the Delhi Development Act, the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations namely :—

1. Short Title.—These regulations may be called the Delhi Development Authority (Powers and Duties of the Secretary and the Chief Accounts Officer) Regulations, 1984.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires—

1. "Act" means the Delhi Development Act 1957 (61 of 1957).

2. "Authority" means the Delhi Development Authority, constituted under sub-section (1) of section 3 of the Act.

3. "Advisory Council" means the council constituted under sub-section (1) of section 5 of the Act.

4. "Chief Accounts Officer" means the Chief Accounts Officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of the section 4 of the Act.

5. "Secretary" means the Secretary appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 4 of the Act.

6. Words and expressions not defined in these regulations shall have the same meaning as in the Act or rules or regulations framed the rounder.

3. Powers of the Secretary.—The Secretary shall exercise the following powers, namely :—

1. To act as Head of the Office and to exercise such powers as are normally exercisable by the Head of Offices of the Central Government ;

2. to make appointments to posts in C&D groups in accordance with such procedure or instructions as the Authority may from time to time lay down,

3. to sanction leave to employees in groups C&D

4. Subject to such restrictions and limits as the Authority may by general order imposes, to sanction expenditure on the procurement or purchase of stationery articles, forms, furniture, electrical goods, tools, instruments and other articles of office equipment ;

5. to execute on behalf of the Authority agreements, lease deeds, sale deeds and such other documents in respect of transactions sanctioned by it or any officer to whom power to sanction such transactions may have been delegated and

6. to institute or defend suits or legal proceedings instituted by or against the Authority or its predecessor bodies and to withdraw or to compromise the same on such terms and conditions as may be approved by the Vice Chairman of the Authority.

4. Duties of the secretary.—The Secretary shall be responsible for performing all or any of the following duties, namely :—

1. To fix meetings of the Authority, and the Advisory Council and of such committees as the Authority may from time to time constitute under sub-section (1) of section 5A of the Act, and prepare and issue agenda and minutes of proceedings of meetings of the said bodies ;

2. to procure and supply within such time, if any, as may be specified, to the Central Government, the Authority, the Advisory Council or Committees mentioned in sub-rule (1) as the case may be, such papers or information as may be asked for ;

3. to ensure that such directions as the Central Government may issue under sub section (1) of section 41 of the Act are carried out;

4. to compile a report on the activities of the Authority in accordance with the Delhi Development Authority (Miscellaneous) Rules, 1959, and, after approval by the Authority, to submit it to the Central Government in accordance with the prescribed time schedule ;

5. Subject to such general or specific instruction as the Vice Chairman may issue, to publicise the activities of the Authority in such manner and to such extent as may be laid down ;

6. to intimate proposals for the creation of posts and the appointment of officers and employees in the Authority.

7. to send intimation to the Chief Accounts Officer about the creation or continuance of posts and appointment of officers and employees, and otherwise to keep watch over the requirement of staff ;

8. to maintain liaison with and ensure coordination between the various departments branches and sections of the office of the Authority ;

9. to advise on all matters concerning creation of posts, appointment of officers and employees and generally about other matters concerning officers and employees and their service conditions ;

10. to deal with all matters relating to the redressal of grievances of officers and employees and matters connected with their welfare;

11. to exercise general superintendence over the staff of the Authority, with a view to ensuring that proper discipline is maintained and work is carried on in an orderly and business like manner ;

12. to initiate proposals for the provision of residential housing facilitating for officers and employees; and

13. to arrange for the timely procurement and supply of articles of stationery, furniture, forms, electrical goods, tools, instruments and other office equipment of such value and in such quantities as may be required for the efficient functioning of the office and to keep effective supervision overall matters connected with day-to-day office management.

5. The Chief Accounts Officer shall exercise the following powers, namely :

1. To check and call for records or information whatever necessary, from the departments, branches or sections of the Authority in respect of any matter relating to a monetary transaction, proposed or executed or relating to the matters being dealt with by him for the time being or get it done by an inspection party;

2. to conduct or to get conducted through any person authorised by him in this behalf, physical verificatios of cash of the Authority in the custody of any officer or employee of the Authority;

3. to sanction refundable and non refundable advances to officers and employees of the Authority from the general provident fund or the costributory provident fund, as the case may be;

4. to have adequate staff for the maintenance of accounts and other functions assigned to him and to obtain suitable personnel on deputation under the directions of the Vice Chairman to fill posts as may be necessary for the efficient functioning of the Accounts Department or such other departments, branches or sections, as may be charged wholly or in part with the accounting of moneys; and

5. to exercise such other powers as may be delegated by the Authority or the Vice Chairman.

6. Duties of the CAO.—He shall perform the following duties, namely:

1. to ensure timely preparation of a budget, in such form and at such time every year as may be prescribed by rules, in respect of mated receipt and expenditure of the mated requips and expenditure of the Authority;

2. to ensure proper maintenance of accounts and other relevant record and monthly accounts and annual statement of accounts of the Authority including balance sheet in such form as the Central Govt. may in consultation with the Comptroller & Auditor General of India, by rules prescribe;

3. to ensure maintenance of a register of loans received or raised by the Authority and to maintain in respect of such loans an account of the sinking fund, if operated;

4. to watch progress of expenditure aginst budget estimates and to keep in check the ways and means position;

5. to advise in all matters relating to accounts and budget and to ensure proper operation of financial rules generally;

6. to advise on the financial aspects of all proposals for expenditure referred to him and to keep a watch over liabilities against the Authority and to see that and orders in force in respect of monetary transactions of the Authority are observed;

7. to advise on the profitable manner of investement of the surplus funds of the Authority and to maintain account of and to keep a watch over the maturity of investments;

8. to advise about the requirement of staff on the Accounts Department of the Authority and other branches or sections of the Authority as may be charged wholly or in part with the accounting of monetary transactions;

See S.O. No. 548(E) dt. 26.7.85

9. to report on the admissibility of leave, pension gratuity and other matters affecting the service conditions of officers and employees of the Authority; and

10. to ensure that the annual Accounts are compiled and submitted to the Central Government together with the Audit Report thereon is accordance with the prescribed time schedule.

[F. 1(148)/70-GA]
M. P. JAIN, Secy.
Delhi Development Authority.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985

F1(148)70.9A

The powers and duties of Secretary as also of the Chief Accounts Officer have become a matter of Regulations framed under Section 57(b) of Delhi Development Act. The Regulations have been notified in Gazette Extraordinatry of May 20, 1985. The Regulations have been laid on the table of both the Houses of Parliament. Thus they have come to have a mandatory character.

Before the Regulations came into force, V.C. was pleased to entrust some of the duties/functions of the Secretary as given in the Regulations to Commissioner(A). In the interest of general administrative and legal propriety, V.C. might like to order the exercise of powers and discharge of duties as laid down in the Regulations by the Secretary henceforth.

[M.P. Jain]
Secretary
16.1.86

Vice-Chairman.

20/1/86

S.O. No. 421(E)
28-5.1985

रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०एन०)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, मंगलवार, 28 मई, 1985/ ज्येष्ठ 7, 1907

No. 259] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1985/JYAISTHA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(स्लम विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1985

अधिसूचना

का.आ. 421(अ) :—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 52 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण स्लम विभाग के मामले में अपने शक्तियां अपने उन सदस्यों/अधिकारियों को एतद्द्वारा प्रत्यायोजित करता है, जो संलग्न अनुसूची में उल्लिखित हैं।

एम. पी. जैन, सचिव

अनुसूची

सेवा का नाम	पदों का सृजन करने वाला सक्षम प्राधिकारी	नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	दण्ड देने वाला प्राधिकारी (अनुशासनिक प्राधिकारी) और वे दण्ड, जो दिए जा सकते हैं		अपील प्राधिकारी
			प्राधिकारी	दण्ड समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 का नियम-II	
ग्रुप "सी" पद स्लम एवं जे.जे. विभाग	उपाध्यक्ष	निदेशक (स्लम)	निदेशक (स्लम)	—सभी—	उपाध्यक्ष
ग्रुप "डी" पद स्लम एवं जे.जे. विभाग	उपाध्यक्ष	निदेशक (स्लम)	निदेशक (स्लम)	—सभी—	उपाध्यक्ष

247 GI/85

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Slum Department)

New Delhi, the 27th May, 1985

NOTIFICATION

S.O. 421 (E):— In exercise of the powers vested in it under sub-section (1) of section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby delegates such of its powers in respect of slum Department to such of its members officers as mentioned in the schedule attached.

M. P. JAIN, Secy.

SCHEDULE

Title of Service	Authority competent to create posts	Authority empowered to appoint	Authority (Disciplinary Authority) empowered to impose penanties & penalties if may impose		Appellate Authority
			Authority	Penalities (Rules II of CCS (CCA) Rules 1965 as amended from time to time.	
Group 'C' Posts Slum & JJ Deptt.	Vice Chairman	Director (s)	Director (s)	All	Vice-Chairman
Group 'D' Posts Slum & JJ Deptt.	Vice Chairman	Director (s)	Director (s)	All	Vice-Chairman

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

S.O. No. 546 (E)
26.7.1985

रजि.सं. डी. (डी. एन.)-7 REGISTERED No. D. (D.N.)-7

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1985/श्रावण 4, 1907
No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1985/SRAVANA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 22nd July, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 546(E).—In partial modification of notification published on 20-5-1985 in part II section 3(ii) vide S.O. No. 404(E) in the Extraordinary Gazette of India, para 1 at page 5 regarding the Duties of the Chief Accounts Officer, D.D.A. may be read as under :—

"to ensure timely preparation of a budget, in such form and at such time every year as may be prescribed.

by rules, in respect of the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Authority".

[F. 1(148)/GA]

M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

S.O. No. 547 (E)
26.7.1985

रजिस्ट्री सं: डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1985/श्रावण 4, 1907
No. 360] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1985/SRAVANA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1985

अधिसूचना

का. आ. 547(अ) :—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ई) के अन्तर्गत जल प्रदाय एवं मल व्ययन समिति और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सदस्य क्रमशः श्री अबजीत सिंह गुलाटी और श्री

नारायण सिंह दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित किए गए हैं।

[सं. एफ. 5(1)/79-एम. सी. पार्ट]

एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 26th July, 1985

NOTIFICATION

S.O. 547(E).—It is hereby notified that under clause (e) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) Shri Abjit Singh Gulati and Sh. Narain Singh representatives from Water Supply and Sewage Disposal Committee and Delhi Electric Supply Undertaking respectively have been elected to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. 5(1)|79-MC-PT]

M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

S.O. No. 548(E)
26.7.1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1985/श्रावण 4, 1907

No. 361] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1985/SRAVANA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1985

का.आ. 548(अ):--दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना सं० एफ. 5(1)/79 एम.सी० दिनांक 17 मार्च, 1981 का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (एच) के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य श्री भरतसिंह और श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर, प्रोफेसर नारायण चन्द पराशर और श्री राम विलास पासवान जिनकी सदस्यता सातवीं लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो गयी, के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की "सलाहकार परिषद" के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए लोकसभा द्वारा निर्वाचित किये गए हैं।

[एफ० 5(1)/79 एम.सी./पार्ट]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th July, 1985

S.O. 548(E).—In partial modification of notification No. F. 5(1)79-MC dated 17th March, 1981, of Delhi Development Authority, it is hereby notified that under clause (h) of sub-section (2) of section 5 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957). Sh. Bharat Singh and Smt. Sunderwati Naval Prabhakar both members of the House of the People (Lok Sabha) have been elected by the House of People (Lok Sabha) to serve as members of the 'Advisory Council' of the Delhi Development Authority in place of Professor Narain Chand Parasher and Sh. Ram Vilas Paswan who ceased to be members of the 7th Lok Sabha on its dissolution.

[F. 5(1)79-MC-PT]

का. आ. 549 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (एच) के अन्तर्गत श्री शमीम अहमद सिद्दिकी, संसद सदस्य राज्यसभा के सदस्य श्री हरविन्दर सिंह हंसपाल के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 19-3-85 को राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए गए हैं।

[एफ 5(1)/79 एम. सी. पार्ट]
एम. पी. जैन, सचिव

S.O. 549(E).—It is hereby notified that under clause (h) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Sh. Shamim Ahmed Siddiqi, M.P. has been elected by the Rajya Sabha on 19-3-85 to serve as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority in place of Sh. Harvinder Singh Hanspal member of Rajya Sabha.

[F. 5(1)79-MC|PT]
M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

S.O. No. 637(E)
30.8.1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 415] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 1985/भाद्र 8, 1907
No. 415] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 1985/BHADRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1985

का०आ० 637(अ) :—दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं के प्रबन्ध एवं निष्टान) विनियमन, 1968 के विनियम 3 के अन्तर्गत उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा उक्त विनियमन, 1968 के विनियम 38 से 49 तथा 51 से 58 तक के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी शक्तियां, अधिसूचना सं० 1(1)79/समन्वय, दिनांक 28-9-79 द्वारा निदेशक (आवास) को पहले प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, आयुक्त (आवास), दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रदान करते हैं।

[सं० 3(20)/79/एच/एजेंसी]

एम० पी० जैन, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1985

S.O. 637(E).---In exercise of the powers vested in him under Regulation 3 of the Delhi Development Authority (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, the Vice Chairman, Delhi Development Authority hereby delegates all powers exerciseable by him under Regulations 38 to 49 and 51 to 58 of the said Regulations to the Commissioner (Housing), DDA, in addition to the powers already delegated to Director (Housing), vide Notification No. 1(1)|79-Coordn. dated 28-9-79.

[No. 3(20)|79|H|Agency]

M. P. JAIN, Secy., DDA

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

S.O. No. 638(E)
30.8.1985

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 1985/भाद्र 8, 1907
No. 416] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 1985/BHADRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1985

अधिसूचना

का०आ० 638(अ) :—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957(1957 का 61) की धारा 52 की उपधारा (1) के आधार पर उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12(3) और निम्नलिखित के अनुसार उससे सम्बन्धित मामलों के अतिक्रमण के लिए अभियोजन करने संबंधी उसकी

शक्तियों का प्रयोग उन अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा जिनका नीचे की अनुसूची में प्रत्येक के सम्मुख उल्लेख किया गया है :—

अनुसूची

क्रम सं०	शक्तियां	प्राधिकृत/प्रत्यायोजित अधिकारी
1.	दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रवेश की शक्तियां ।	उन अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त अपर आयुक्त (भूमि) जिन्हें पहले से शक्तियां दी हुई हैं ।
2.	धारा 49 के अन्तर्गत पिछली स्वीकृति देने की शक्तियां ।	उन अधिकारियों/कर्मचारियो के अतिरिक्त अपर आयुक्त (भूमि) जिन्हें पहले से शक्तियां दी हुई हैं ।
3.	धारा 29(1) के साथ पठित 12(3) के अतिक्रमण के लिए परिवाद फाइल करने और उसके लिए काउन्सेल नियुक्त करने की शक्तियां ।	उन अधिकारियो/कर्मचारियों के अतिरिक्त अपर आयुक्त (भूमि) जिन्हें पहले से शक्तियां दी हुई हैं ।

[संख्या डी०ए० मिसिलेनियस(48)/84]

एम०पी० जैन, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 28 August, 1985

NOTIFICATION

S.O. 638(E).—In exercise of powers vested in it by virtue of sub-section (1) of section 52 of the Delhi Development Act, 1957(61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby directs that its powers in respect of prosecution for violation of section 12(3) ibid and matters connected therewith as mentioned below may also be excersied by such officers as are mentioned against each in the schedule below :

SCHEDULE

Sl. No.	Powers	Officers Authorised/Delegated
1	Powers of entry under section 28 of the Delhi Development Act, 1957	In addition to the Officers/ officials already empowered, the Additional Commissioner (Lands).

1	2	3
2.	Powers to grant previous sanction under section 49 of the Delhi Development Act, 1957	In addition to the officers already empowered, the Additional Commissioner (Lands).
3.	Powers to file complaint for violation of section 12(3) read with section 29(1) of the Delhi Development Act, 1957 and to engage counsel therefor.	In addition to the Officer already empowered the Additional Commissioner (Lands).

[No. DDA/Misc. (48)/84]
M.P. JAIN, Secy. (DDA)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

S. O. No. 161
18.1.1986

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II SEC. 3 SUB. SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 16 176
Dated 18-1-1986

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1986

का.आ. 161:--दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-57 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतदद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से उक्त धारा के अनुच्छेद (एफ) के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम बनाता है :--

अध्याय 1—सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक लागू होना व समारम्भ (1) इन विनियमों को दिल्ली विकास प्राधिकारण (क्षेत्रीय) विनियम, 1983 कहा जाए।

(2) ये विनियम समस्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू हो जाएंगे।

2. परिभाषाएं (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय न हो :--

(ए) "अधिनियम" से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है;

(बी) "प्राधिकरण" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है;

(सी) "पूंजीगत मूल्य" से अभिप्राय भूमि, संरचना एवं मशीनरी के मूल्य से है जिस पर संस्वीकृत मुख्य योजना की तिथि से ह्रास अनुमेय है।

(डी) "वाणिज्यिक" से अभिप्राय है जो वाणिज्य से संबंधित हो।

(ई) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

(एफ) "जिला केन्द्र" से अभिप्राय किसी नक्शे में दर्शाये गये जिला केन्द्र से है और जिसमें उप-जिला केन्द्र भी सम्मिलित है।

(जी) "प्रति कामगार फर्श क्षेत्र" से अभिप्राय वर्ग मीटरों में मापित उस भागफल से है कुल उपलब्ध फर्श को कुल पंजीकृत औद्योगिक श्रम संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।

(एच) "भवनों में सुधार" से अभिप्राय अनुसूची-3 में उल्लिखित सुधारों से है।

(आई) "औद्योगिक" से अभिप्राय है जो उद्योग से संबंधित है।

(जे) "अपुष्ट प्रयोग" से अभिप्राय किसी भूमि या भवन का प्रयोग किसी क्षेत्र की मुख्य योजना तथा अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार न होने से है।

(के) "हानिकारक उद्योग" से अभिप्राय ऐसे उद्योगों से है जिनसे जीवन को खतरा हो जो धूम उत्पन्न करके, बाहर की ओर प्रवाहित होकर स्वास्थ्य अथवा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हों या जहां ज्वलनशील सामग्री उत्पन्न की जाती हो अथवा भंडार के रूप में रखी जाती हो।

(एल) "शोर कारक उद्योग" से अभिप्राय ऐसे उद्योग से है जो देखने में या दिखावट में, सूंघने में या सुनने में किसी को नुकसान, खतरा पहुंचाये या उसे परेशान कर दे अथवा विश्राम या निद्रा में व्यवधान पहुंचाये।

(एम) "पंजीकृत रोजगार" से अभिप्राय अधिनियम जिसके अधीन कोई उद्योग चल रहा है; के अनुसार पंजीकृत कामगारों की संख्या से है।

(एन) "रिहायशी" से अभिप्राय है कि जो रिहायश से संबंधित हो।

(ओ) "प्रयोग क्षेत्र" से अभिप्राय अनुसूची-1 में उल्लिखित में विभिन्न उपयोगों की पद संज्ञाओं से है।

2. कोई भी शब्द जो यहां सुस्पष्टता से पारिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जैसा की मुख्य योजना में पारिभाषित या उल्लिखित किया गया है।

अध्याय 2

3. निर्मित क्षेत्रों में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुमत किये जाने वाले उपयोग: निर्मित क्षेत्रों में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी किसी प्रयोग क्षेत्र में, क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तैयार होने तक अनुमत प्रयोग की अनुमति दे सकता है।

4. स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा/अनुमत उपयोगों को क्षेत्रीय विकास योजना में समाविष्ट करना जब कभी किसी निर्मित क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाती है तो स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुमत उपयोगों को भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

अध्याय 3

अपुष्ट प्रयोगों को हटाना तथा कुछेक प्रयोगों का परिवर्तन :

5. औद्योगिक अपुष्ट प्रयोग ('खतरनाक उद्योग) :—कोई भी व्यक्ति चाहे वह योजना लागू होने के तुरन्त पहले से ही किसी भूमि या भवनों

को किसी हानिकारक उद्योग के चलाने के लिए प्रयोग कर रहा हो, उसे उस उद्योग को तीन वर्ष के भीतर किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा "हानिकारक उद्योग" हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु जितनी कि प्राधिकरण द्वारा अनुमत की जाए, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा;

(ए) पूंजीगत मूल्य एक लाख रुपए से अधिक होने पर अनुसूची-2 के अनुसार ;

(बी) किसी अन्य मामले में हानिकारक उद्योगों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निबन्धनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

6. हानि रहित उद्योग किन्तु शोरकारक : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन को शोरकारक उद्योग को चलाने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा हो तो उसे उस उद्योग को चार वर्ष के भीतर योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा "शोरकारक" उद्योग हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अवधि हेतु जितनी कि प्राधिकरण अनुमत करें, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा :--

(1) अनुसूची-2 के अनुसार परिकलन-पैमाने के आधार पर दस वर्ष की अवधि तक यदि--

(ए) विनियमों में उद्धृत उद्योग का पूंजीगत मूल्य उच्चतर है;

(बी) उद्योग का पंजीकृत श्रम अधिक है, तथा

(सी) विनियमों में उद्धत उद्योग का प्रति कामगार फर्श क्षेत्र अधिक हो।

(2) किसी अन्य मामले में शोरकारक उद्योगों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निबंधनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु उसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

7. शोर-रहित उद्योग : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने क तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन को शोर-रहित उद्योग को चलाने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसे उस उद्योग को छह वर्ष के भीतर योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बंद करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा 'शोर-रहित उद्योग' हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी कि प्राधिकरण अनुज्ञात करें, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा :--

(1) अनुसूची-2 के अनुसार परिकलन-पैमाने के आधार पर 20 वर्ष की अवधि तक, यदि :—

(ए) विनियमों में उद्धृत उद्योग का पूंजीगत मूल्य उच्चतर है;

(बी) उद्योग का पंजीकृत श्रम अधिक है; तथा

(सी) किसी अन्य मामले में उद्योग की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निबन्धनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

8. औद्योगिक क्षेत्र में रिहायशी प्रयोग : रिहायशी अपुष्ट प्रयोग तथा इसका परिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी औद्योगिक प्रयोग वाले जोन में रिहायशी उद्देश्यों हेतु किसी भूमि या भवन का अपुष्ट प्रयोग के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो वह उसको 10 वर्ष की अवधि तक जारी रख सकता है। परन्तु इस अवधि की समाप्ति पर उसे अपुष्ट प्रयोग को योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट में स्थानान्तरित करना होगा।

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी जोन में उक्त 10 वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी अपुष्ट प्रयोग जारी रखा जाना उस अवस्था में वैध माना जाएगा, यदि वह व्यक्ति ले-आउट प्लान तथा अपुष्ट रूप में प्रयोग की जा रही सुपर स्ट्रक्चर के संबंध में प्राधिकरण से अनुमोदन-प्राप्त कर लेता है।

9. वाणिज्यिक क्षेत्रों में रिहायशी प्रयोग : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी वाणिज्यिक जोन में रिहायशी उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन का अपुष्ट प्रयोग के रूप में उपयोग किया जा रहा हो तो वह उस प्रयोग को 10 वर्ष की अवधि तक जारी रख सकता है परन्तु इस अवधि की समाप्ति पर उसे अपुष्ट प्रयोग को योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी जोन में उक्त दस वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात भी उक्त अपुष्ट प्रयोग जारी रखा जाना उस अवस्था में वैध माना जाएगा, यदि (ए) उस व्यक्ति ने ले-आउट प्लान तथा अपुष्ट रूप में प्रयोग की जा रही सुपर स्ट्रक्चर के संबंध में प्राधिकरण से अनुमति प्राप्ति कर ली है।

(बी) प्राधिकरण लिखित रूप में दर्ज किये गये कारणों के आधार पर उस जोन में भवन की प्रथम तथा ऊपरी मंजिल को रिहायशी प्रयोग हेतु प्रयोग में लाये जाने हेतु अनुमति दे सकता है।

10. सार्वजनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्रों में रिहायशी प्रयोग : किसी भी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी सार्वजनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्र वाले जोन में स्थित किसी भूमि या भवन का रिहायशी उद्देश्य हेतु अपुष्ट प्रयोग किया जा रहा हो तो वह उस भूमि या भवन के प्रयोग को जारी रख सकेगा बशर्ते वह भूमि या भवन किसी गांव में स्थित हो जो 1 सितम्बर, 1962 को अस्तित्व में था तथा अन्य सभी मामलों में 10 वर्ष तक या ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक जो अनुमत मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा दी जाए।

11. औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रयोग : औद्योगिक प्रयोग के जोन में वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ए) 10 वर्ष की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है बशर्ते वह प्राधिकरण से ऐसी भूमि या भवन के प्रयोग को वाणिज्यिक प्रयोग को परिवर्तित कराने तथा ले-आउट प्लान और उस पर स्थित स्ट्रक्चर के संबंध में स्वीकृति प्राप्त कर लें; और

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसी प्राधिकरण तय करें।

12. रिहायशी क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रयोग :—रिहायशी प्रयोग के जोन में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन को किसी यक्ति द्वारा :—

(ए) 10 वर्ष का अवधि तक प्रयोग कर सकता है बशर्ते उस जोन की क्षेत्र य विकास योजना में वह भूमि स्थानीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट हो; तथा

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसा प्राधिकरण तय करें।

13. सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक क्षेत्रों में जिसमें मनोरंजनात्मक क्षेत्र भी शामिल हैं, में वाणिज्यिक प्रयोग :—सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रयोग के जोन में जिसमें मनोरंजनात्मक जोन भी सम्मिलित है, में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा :

(ए) 10 वर्ष तक की अवधि तक प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते उस जोन की क्षेत्रीय विकास योजना में वह भी स्थानीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट हो; तथा

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसा प्राधिकरण तय करें।

14. अपुष्ट क्षेत्रों में सुधार एवं परिवर्तन :—किसी व्यक्ति द्वारा यदि योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन का प्रयोग उस जोन की मुख्य या क्षेत्रीय विकास योजना के अनुरूप नहीं किया जा रहा हो और यदि वह उस भूमि या भवन पर संस्थापित मशीनरी में सुधार या बदलाव करना चाहे तो उसे इसकी इजाजत होगी बशर्ते ऐसे सुधार या बदलाव इन विनियमों की अनुसूची- 3 में उल्लिखित मदों के अंतर्गत आते हों।

15. अस्थायी परमिट :—कोई भी भूमि या भवन नक्शे में उसके निर्धारित प्रयोग से अन्यथा उद्देश्य हेतु अस्थायी रूप में एक सीमित अवधि हेतु आवेदन प्राप्ति पर कारणों को लिखित रूप में एक सीमित अवधि हेतु आवेदन प्राप्ति पर कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए प्रयोग में लाने हेतु अनुमत की जा सकती है जैसे किसी औद्योगिक स्टेट के निर्माण के समय मजदूरों के रहने के लिये टैन्टों हेतु अथवा यदि विकासाधीन क्षेत्र में सम्पत्ति मालिक की इच्छा पर कृषि के प्रयोग को जारी रखने हेतु या विकासाधीन क्षेत्रों में ही भूमि के नक्शे में निर्धारित प्रयोग से अन्यथा किसी उद्देश्य हेतु अस्थायी प्रयोग हेतु उपयोग में लाना।

16. अनुज्ञप्त प्रयोग :—किसी जोन में किसी भूमि या भवन के प्रयोग को वैध माना जाएगा यदि वह भूमि संलग्न अनुसूची - 4 में अपने जोन में अनुज्ञप्त प्रयोग से दर्शित प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग हेतु निर्दिष्ट की गई हो।

17. विशेष अपील पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि अनुमति दी जाए तो अनुज्ञप्त प्रयोग :—किसी जोन में किसी भूमि या भवन को यदि यहां अनुसूची -4 में उल्लिखित विशेष अपील के अन्तर्गत सक्षम प्राधकारी द्वारा किसी भी उद्देश्य हेतु प्रयोग करने के लिये स्पष्टतः अनुमत कर दिया जाए तो उसे प्रयोग में लाया जाना वैध माना जाएगा।

विनियम 1 (ओ) के अनुसार अनुसूची–1

प्रयोग क्षेत्र

1	2	3
1.	आर–25	रिहायशी
2.	आर–50	रिहायशी
3.	आर–60	रिहायशी
4.	आर–75	रिहायशी
5.	आर–100	रिहायशी
6.	आर–125	रिहायशी
7.	आर–150	रिहायशी
8.	आर–200	रिहायशी
9.	आर–250	रिहायशी
10.	ए–1	कृषि हरित पट्टी
11.	ए–2	ग्रामीण
12.	सी–1	खुदरा विपणन
13.	सी–2	सामान्य व्यापार तथा वाणिज्यिक (केन्द्रीय तथा उप-केन्द्रीय व्यापार जिले, जिला केन्द्र)
14.	सी–3	थोक
15.	एम–1	फ्लैटिड फैक्ट्री
16.	एम–2	कार्य व औद्योगिक केन्द्र
17.	एम–3	विशेष उद्योग
18.	एम–4	हल्के उद्योग तथा सर्विस इन्डस्ट्री
19.	एम–5	व्यापक विनिर्माण
20.	एम–6	निष्कर्षणात्मक उद्योग, उत्खनन ईंट-भट्टे, पत्थर-क्वैरी इत्यादि।
21.	डब्ल्यू.	गोदाम, भण्डारण तथा डिपो।
22.	सी	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय।
23.	पी	मनोरंजनात्मक।
24.	एफ	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं।

विनियम 5 से 7 के अनुसार अनुसूची–2

अपुष्ट प्रयोगों हेतु समय-सारिणी

औद्योगिक प्रयोग :

विलम्बन काल की स्थिति	हानिकारक उद्योग	शोरकारक उद्योग	शोररहित उद्योग
	वर्ष संख्या	वर्ष संख्या	वर्ष संख्या
1	2	3	4
वे उद्योग जहां पंजीकृत कर्मचारी संख्या 1 से 19 है और प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र 50 वर्ग फुट या उससे कम है और पूंजीगत मूल्य एक लाख से कम है।	3	4	6
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 20 से 99 के बीच है (अतिरिक्त वर्ष)	—	1	2
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 100 या उससे अधिक है (अतिरिक्त वर्ष)	—	1	2
प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र की उपलब्धता 51 से 100 वर्ग फुट है (अतिरिक्त वर्ष)	—	1	2
प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र की उपलब्धता 100 वर्ग फुट से ऊपर है (अतिरिक्त वर्ष)	—	1	2
पूंजीगत मूल्य यदि एक से पांच लाख के बीच है (अतिरिक्त वर्ष)	1	1	2

1	2	3	4
पूंजीगत मूल्य यदि पांच लाख से ऊपर है (अतिरिक्त वर्ष)	1	1	4
अधिकतम वर्ष संख्या	5	10	20

नोट :—1. सारिणी में दर्ज प्रत्येक संख्या पर समय दर्शाया गया है जो सारिणी में प्रस्तुत क्रम का समुच्चयबोधक है।

2. सारिणी में दर्ज रोजगार उस उद्योग हेतु है जो ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। जिन उद्योगों में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती वहां रोजगार की संख्या दुगनी मानी जाएंगी।

विनियम 14 के अनुसार अनुसूची-3 :

भवन तथा मशीनरी में अनुमति के अनुसार सुधार करना।

1. वर्तमान पावर प्लान्ट तथा वर्कशाप और अन्य अनुषांगिक विभाग जो मौजदा उपकर की क्रियाकलापों के चलते रहने से जुड़े हैं, की उत्पादकता, दक्षता तथा मितव्ययता में वृद्धि करने हेतु किसी भी प्रकार से मरम्मत, तबदीली, आधुनिकीकरण या सुधार करना।

2. उस भवन को किसी भी प्रकार से पुनर्गठित करना, उसमें परिवर्तन करना या उसकी मरम्मत करना, जिसमें उक्त संयंत्र एवं उपकरण स्थित हैं।

3. किसी भी वर्तमान कार्यालय भवन, रिहायशी, आवास, सुविधाओं द्वारों, टंकियों, प्लेटफार्मों, कूओं, सड़कों, नालियों तथा अन्य स्ट्रैक्चरों में वर्तमान उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं की दक्षता, उत्पादकता तथा मितव्ययता को बनाये रखने तथा उसमें सुधार करने के उद्देश्य से परिवर्तन, पुनर्गठन, बढ़ावा तथा परिवर्द्धन करना।

4. औद्योगिक भूखण्ड पर गोदाम का पुनर्निर्माण या मरम्मत, परिवर्तन करना, कच्चे माल, मशीनरी, कल-पुर्जों, परिष्कृत उत्पादों, भवन सामग्री इत्यादि को ढेर के रूप में रखना।

विनियम 16 के अनुसार अनुसूची-4

क्रम. सं.	प्रयोग क्षेत्र	अनुज्ञप्त प्रयोग
1	2	3
1.	1 से 3 आर.-25 आर.-50, आर.-60	रिहायशी मकान, बाल बाड़ियां, किन्डर गार्डन तथा स्कूल क्लिनिक्स, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं जिनमें पर्याप्त पार्किंग सुविधा हो; सर्विस व स्टोरेज यार्डस को छोड़कर जन सुविधाएं तथा इमारतें अवाणिज्यिक फार्मस, कृषि बागान, नर्सरियां और ग्रीन हाऊसिज तथा पड़ौसवर्ती, मनोरंजनात्मक प्रयोग जिनमें क्लब्स तथा अन्य अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग सम्मिलित है; सहप्रयोग जो रिहायशी प्रयोग पर स्पष्टतः अनुषांगिक है (खुदरा दुकानों व सेवा प्रयोगों को छोड़ कर) तथा वे शोर या खतरा उत्पन्न न करते हों।
2.	4 से 6 आर–75, आर–100, आर–125	आर–25 से आर–60 तक के प्रयोग क्षेत्रों में सभी उपयोगों का अनुमति है।
3.	7 से 8 आर–150, आर–200	आर–75 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं।
4.	9 : आर–250	आर–200 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं।
5.	10ए–1	कृषि, उद्यान, फल-वाटिका तथा सब्जी फार्म जिनके फार्म प्लाट का कम से कम आकार 1 हैक्ट. है, मुर्गी, डेरी तथा अन्य पशुधन फार्म और उनको सह इमारतें तथा 2 हैक्ट. की न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र सीमा में आने वाले प्रयोग ; भूमि प्रयोग नक्शे में दर्शित या वर्णित विशिष्ट प्रयोग जैसे शहरी गांव, ईंट भट्टे तथा 1981 की शहरीकृत सीमा से आधा मील से बाहर 8 फुट की गहराई तक मिट्टी निकालना।
6.	11ए–2	कृषि हरित पट्टी प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुज्ञप्त हैं।
7.	12सी–1	खुदरा दुकानें, व्यापार एवं व्यावसायिक कार्यालय, सर्विस यूज जैसे बारबर, टेलर, लांडरी तथा ड्राईक्लीनर्स की दुकानें इत्यादि, रेस्तरां तथा मनोविनोद स्थल, रिहायशी मकान, सामाजिक व कल्याण संस्था बशर्ते वे प्रथम तथा ऊपरी मंजिलों पर स्थित हों, क्लीनिक्स, मांस-मछली तथा फल बाजार, वैध खुदरा व्यापार हेतु छत वाले भण्डारगृह, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जन-सुविधाएं व इमारतें। सभी प्रयोगों हेतु अपेक्षित पार्किंग क्षेत्र अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए।
8.	13-सी–2	सी–1 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं, होस्टल व बोर्डिंग हाऊस, गेस्ट हाऊस तथा होटल्स, कालेज स्कूल, अनुसंधान संस्थान, सर्विस गैरेज, गोदाम और ढके भण्डार गृह, स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारी कार्यालय भी जिसमें शामिल हैं। सभी प्रयोगों हेतु अपेक्षित पार्किंग क्षेत्र अनुमोदित अवश्य किया जाना चाहिए।
9.	14सी–3	थोक व खुदरा दुकानें, विशिष्ट प्रतिबन्ध को छोड़कर थोक व्यापार हेतु भण्डार गृह, व्यापारिक कार्यालय, रेस्तरां तथा रिहायशी बशर्ते वे प्रथम एवं

1	2	3
		ऊपरी मंजिलों में स्थित हों, जनसुविधाएं एवं भवन पार्किंग सभी उद्देश्यों हेतु लोडिंग व अनलोडिंग आवश्यकताओं को अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए ।
10.	15एम-1	निदर्शी सूची में उल्लिखित कार्य-निष्पति मानदों से सदृश पुष्ट उद्योग जो अतिशय घातक न हों या घृणित शोर, कम्पन, धूआं, गैस-धूम, गन्ध, धूल, अपगामी रूप में या अन्य आपत्तिजनक रूप में उत्पन्न न करें और जहां ऊर्जा चालित दशा में 20 से अधिक और ऊर्जारहित संचालन की दशा में 40 व्यक्ति नियोजित हों, उद्योग हेतु भण्डार गृह हों । सभी प्रयोगों हेतु जन-सुविधाएं तथा इमारतें, पार्किंग, लोडिंग अनलोडिंग की अपेक्षाओं को अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए।
11.	16एम-2	एम-1 प्रयोग क्षेत्रानुसार
12.	17एम-3	एम-1 प्रयोग क्षेत्रानुसार
13.	18एम-4	एम-1, एम-2 तथा एम-3 प्रयोग क्षेत्रों में अनुमत सभी उद्योग तथा उद्योगों की सूची में उल्लिखित अन्य उद्योग जहां ऊर्जा चालित दशा में 50 से अनधिक तथा ऊर्जा रहित दशा में 100 व्यक्ति नियोजित हैं ; सर्विस उद्योग गोदाम, भण्डार गृह, जन सुविधाएं तथा इमारतें तथा किसी वर्तमान कृषि भूमि का जब तक कि विकास कार्य हेतु उसकी आवश्यकता न हो कृषि प्रयोग करना । पार्किंग, लोडिंग तथा अनलोडिंग क्षेत्र सम्बन्धी अपेक्षाएं सभी प्रयोगों हेतु अनुमोदित अवश्य की जानी चाहिएं ।
14.	19एम-5	एम-4 प्रयोग क्षेत्र में अनुज्ञप्त सभी प्रयोग ।
15.	20एम-6	कंकड़, मिट्टी, रेत इत्यादि हटाना, खनिज निकालना सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे इस सम्बन्ध में कैसी भी शर्तें लगाई गई हों, कृषि एवं कृषि के अनुषांगिक प्रयोग ।
16.	21डब्ल्यू.	अनश्वर तथा अज्वलनशील वस्तुओं हेतु गोदाम, भण्डार तथा डिपो और अनुषांगिक प्रयोग पार्किंग लोडिंग व अन-लोडिंग क्षेत्र सम्बन्धी अपेक्षाओं को सभी प्रयोगों हेतु अनुमोदित किया जाना चाहिए।
17.	22जी	स्थानीय, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कार्यालय तथा सुरक्षा उद्देश्यों हेतु प्रयोग, अनुसंधान संस्थान, सामाजिक एव सांस्कृतिक संस्थान, बस व रेल यात्री टर्मिनल्स, जन सुविधाएं व इमारतें, स्थानीय म्यूनिसिपल सुविधाएं, सरकारी कार्यालयों से अनुषांगिक प्रयोग तथा उनके प्रयोगार्थ पार्किंग अपेक्षाओं को अनुमोदित अवश्य किया जाना चाहिए ।
18.	23पी	समस्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जिसमें पार्क, खेल के मैदान, पार्क पगडन्डियां तथा मुख्य पथ विशेष मनोरंजनात्मक क्षेत्र व शैक्षिक एव मनोरजनात्मक क्षेत्र, बस तथा रेल यात्री टर्मिनल्स् तथा कार पार्किंग क्षेत्र । सभी मामलों में पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता को अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए ।
19.	24एफ	स्थानीय तथा क्षेत्रीय म्यूनिसिपल कार्यालय ; शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थान, सामाजिक एवं सास्कृतिक संस्थान, स्मारक तथा धार्मिक संस्थान ; स्थानीय म्यूनिसिपल तथा सामुदायिक सुविधाएं, जन सुविधाएं तथा इमारतें; रेडियो ट्रांसमीटर तथा वायरलैस स्टेशन्स ; श्मशानघाट व कब्रिस्तान । सभी मामलों में पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता का अनुमोदन अवश्य होना चाहिए ।

विनियम -17 के अनुसार अनुसूची-5
विशेष अपील के अंतर्गत अनुमेय प्रयोग

क्रम	प्रयोग क्षेत्र	सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अपील के अन्तर्गत अनुमति दिये जाने पर अनुमेय प्रयोग।
1	2	3
1.	1 से 3	मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तथा पूजा के अन्य स्थल, कारोबार संबंधी कार्यालय या गृह स्थित धंधे, परन्तु वे उसी रिहायशी इकाई में स्थित हो जिसका मालिक व कारोबारी आदमी या औरत हो या वे उसी स्थानीय बाजार में स्थित हों, वाणिज्यिक कार्यालय सर्विस प्रयोग के रूप में हों तथा पड़ौस के सदृश में खुदरा दुकानों के रूप में यदि वे स्थानीय बाजार या केन्द्रीकृत जगहों में या तैयार किये जाते समय क्षेत्रीय योजना में दर्शाये गये हों, बोर्डिंग हाऊस, गैस्ट हाऊस, होस्टल्स तथा लोडिंग हाऊसिंग एंड मोटैल्स, (बिल्डिंग स्टेण्डर्डस रेगूलेशन्स, 1977 द्वारा शामिल होते हैं, अस्पताल, स्नेटोरिया – जो कि किसी संक्रात्मक रोगों या मानसिक रोगियों से संबंधित न हों, भूखंड का

1	2	3
		पटाव व पिछवाड़ा इस प्रकार का न हो कि समीपवर्ती रिहायशी क्षेत्रों को कोई व्यवधान होता हो, कालेज तथा अनुसंधान संस्थान जहां बिक्री की जाने वाली वस्तुओं या सामग्रियों का उत्पादन न होता हो तथा कोई शोर न पैदा हो और भवन का कोई भाग भूखंड रेखा से 50 फुट से कम दूरी पर स्थित न हो, म्यूनिसिपल, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कार्यालय, अवाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु मुर्गी या पशु–फार्म बनाना ––बशर्ते वह जगह जहां कि पक्षियों या पशुओं को रखा गया है, किसी रिहायश या सम्पत्ति से 50 फुट दूर हो, स्थल के विकासार्थ कंकड़, मिट्टी रेत या पत्थर को हटाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि वहां पानी खड़ा हो जाए या किसी प्रकार का शोर उत्पन्न हो, बस डिपों, रेलवे यात्री स्टेशन्स एवं माल–भाड़े के अड्डे, सड़कों पर पैट्रोल प्रदायो स्टेशन या 100 फुट या इससे ऊपर का मार्गाधिकार सर्विसिज एवं भण्डारगृह प्रांगण, टैक्सी, स्कूटर स्टेण्डस, घरेलू उद्योग (सूची परिशिष्ट "ए" पर प्रस्तुत)
2.	4 से 6 आर–75 आर–100 आर–125	आर–25 से आर–60 प्रयोग क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुमेय हैं।
3.	7 से 8 आर–150 आर–200	आर–75 से आर–125 क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुमेय हैं।
4.	9 आर–250	आर 200 प्रयोग क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुमेय हैं।
5.	10ए–1	पूजा आदि के स्थल, स्कूल; पुस्तकालय, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भवन, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जो लाभार्थ नहीं चलाये जा रहे हों ; भंडारगृह, फार्म उत्पादों की प्रोपर्टी पर जहां कि वे उत्पन्न किये जाते हैं, से प्रेषण एवं बिक्री; फार्म मशीनरी की सर्विसिंग तथा मरम्मत तथा कृषिजनित पदार्थों की बिक्री; जन–सुविधाएं व इमारतें।
6.	11ए–2	विपणन केन्द्रों में स्थित खुदरा दुकानें और सर्विस संबंधी प्रयोग मिल्क चिलिंग स्टेशन्स तथा पाशच्युराइजेशन प्लान्टस, कुटीर उद्योग एवं अन्य ऐसे हल्के उद्योग जो कृषिजनित हैं, ग्रामीण कालेज, बोर्डिंग हाउसिज़ व होस्टल्स, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं जो लघु प्रायोगिक संयत्र द्वारा उत्पादित को छोड़कर बिक्री को जाने वाली वस्तुओं या सामग्रियों के उत्पादनार्थ प्रयुक्त न किये जा रहे हों तथा उनके द्वारा शोर पैदा न होता हो और इमारत का कोई भाग किसी रिहायश या समीपवर्ती परिसर या किसी सम्पत्ति सीमा रेखा या सड़क से 100 फुट की हद में न आता हो 8 फुट की गहराई तक खुदाई सामग्री, पत्थर खुदाई बस अथवा रेल यात्री तथा माल भाड़े के अड्डे, विमानों के उतरने के लिए मैदानी क्षेत्र, तथा उनके आवश्यक सम्बद्ध कारक, सुविधाएं व इमारतें, सैन्य उद्देश्यार्थ अपेक्षित क्षेत्र, वायरलेस सम्प्रेषण एवं मौसम केन्द्र, मेटेलस।
7.	12–सी–1	सामाजिक एवं कल्याण संस्थाएं पैट्रोल फिलिंग स्टेशन्स कोयला, लकड़ी या टिम्बर यार्ड्स, सर्विस गैरिजज शोर अथवा हानि रहित तथा हल्के उत्पादन वाले उद्योग जहां उर्जा हो या न हो 4 से अधिक व्यक्ति नियोजित हो तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अहाते में ही खुदरा रूप में विक्रय किया जाता हो, टैक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड, बस टर्मिनल, सभी प्रयोगों हेतु पार्किंग आवश्यकता अवश्य अनुमोदित होनी चाहिए।
8	13–सी–2	सी–1 जोन में विशेष अपील के अंतर्गत अनुमत समस्त प्रयोग। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र और छपाई प्रैस। विपणन केंद्रों की व्यापक योजनाओं या क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी अनुमत किया जाए; हल्के विनिर्माण, शोर रहित या हानि रहित सर्विस इन्डस्ट्रीज जहां ऊर्जा चालित या रहित अवस्था में 10 से अनधिक कर्मचारी नियोजित न हो; जंक–यार्ड्स, पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता–सभी उद्देश्यों हेतु अवश्य प्रदान की जाएं।
9.	14सी–3	ट्रक टर्मिनल तथा पार्किंग; स्कूल क्लिनिक्स, सामाजिक एंव सांस्कृतिक संस्थान, मनोरंजनात्मक उपयोग, भंडारगृह तथा मांस एवं मछली की मार्किट। सभी प्रयोगों हेतु पार्किंग, लोडिंग, व अनलोडिंग क्षेत्र संबंधी आवश्यकता का प्रावधान अवश्य किया जाए।
10.	15एम–1	बस एवं ट्रक टर्मिनल्स रेल यात्रा व माल भाड़े के अड्डे, पैट्रोल फिलिंग स्टेशन्स, टैक्सी तथा स्कूटर स्टेण्ड जंक यार्डस, निगरानी एवं देखरेख करने वाले कर्मचारियों हेतु रिहायश, कर्मचारियों हेतु कैन्टीन तथा मनोरंजन– सुविधाएं।
11.	16 एस–2	एम–1 प्रयोग क्षेत्र के अनुरूप परन्तु एफ. ए. आर. तथा कवरेज इसके बाद में दिये अनुसार भिन्न है।
12.	17 एम–3	निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित केवल उन्हीं उद्योग को अनुमत किया जाएगा जो किसी प्रकार शोर उत्पन्न नहीं करते। कर्मचारियों हेतु कैन्टीन, मनोविनोद सुविधाएं तथा आवास सुविधा का प्रावधान, परन्तु साइट पर प्रति एकड़ 25 व्यक्तियों से अधिक का घनत्व न हो।
13.	18 :एम––4	एम–4 जोन में उल्लिखित सभी प्रयोग अनुमत है। अनुसूची में उल्लिखित सभी उद्योग बशर्ते उद्योग के संचालित होते समय उत्पन्न धुआं, गंध, धूप तथा शोर के संबंध में मानक निर्धारित हो।
14.	20 : एम–6	शून्य
15.	21 : डब्ल्यू –	नष्ट होने लायक तथा ज्वलनशील सामग्रियां रखे जाने वाले गोदाम, सुरक्षा कर्मचारियों हेतु रिहायश पार्किंग, लोडिंग एवं अनलोडिंग आवश्यकताओं का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।
16.	22 :जी.	शून्य
17.	23:पी	बाह्य रंगमच, सिनेमा–चलित रेस्तरां, खाद्य वस्तु विक्रय केन्द्र, जन सुविधाएं तथा म्यूनिसिपल सुविधाएं, मनोरंजन से स्पष्टत: संबंधित प्रयोग जिनसे शोर या खतरा उत्पन्न न होता हो। निगरानी कर्मचारियों हेतु रिहायश, पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए।
18.	24:एफ	मुख्य प्रयोग से संबंधित रिहायश एवं अन्य आनुषंगिक प्रयोग तथा उनसे किसी भी प्रकार से कोई शोर या खतरा उत्पन्न न होता हो।

(अनुसूची 5 का परिशिष्ट "ए")

रिहायशी क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों की सूची :

श्रेणी "ए" (वे व्यवसाय जिनके लिए पावरलोड की स्वीकृति नहीं दी जाएगी) :—

1. अगरबत्ती तथा अन्य उत्पाद
2. कैलिको तथा टैक्सटाइल प्रिंटिंग
3. बेंत-बांस उत्पाद
4. क्ले-मोडलिंग
5. नारियल एवं अन्य फाइबर उत्पाद
6. जरी, जरदोजी
7. पत्थर नक्काशी
8. तस्वीरों की फ्रेमिंग
9. पिथवर्क, पियेट विनिर्माण
10. छाता जोड़ने का काम
11. मोमबत्तियां
12. बाटिक छपाई
13. दरी व कारपेट बुनाई
14. खादी व हैंडलूम
15. घड़ियों व घंटों की मरम्मत
16. खाने वाले तेलों के अलावा तेलों से साबुन उत्पादन
17. ग्रामीण पोटरी उद्योग (व्यवसाय, बिना पावर लोड के चलाया जाता हो)।
18. स्टोव पिनें तथा सेफ्टी पिनें।

श्रेणी "बी" (वे व्यवसाय जिनके लिए 1 कि. वा. की पावर लोड की स्वीकृत दी जानी अपेक्षित है) :—

19. जेवरात कार्य
20. निम्नलिखित का विनिर्माण :—
    (1) ब्लैंको केक्स
    (2) ब्रुश
    (3) क्रेआन्स
    (4) आईसक्रीम तथा मिष्ठान, जैम, जैलीज; तथा
    (5) जैम, जैलीज तथा फल परीक्षण
    (6) नैरो फेब्रिक्स तथा लाख के कार्य की सामग्री
    (7) वाद्ययंत्र तथा उनकी मरम्मत
    (8) जड़ाऊ चर्म वस्तुएं जैसे पर्स, हैंड-बैग
    (9) हल्के इलैक्ट्रोनिक्स।
21. बुक-बाइंडिंग सहित पेपर स्टेशनरी संबंधी वस्तुएं
22. टेलरिंग
23. धागा गोले व कॉटन फिलिंग्स
24. लकड़ी की नक्काशी तथा कलात्मक काठ की वस्तुएं
25. सेवई तथा मैकरोनी
26. इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं को जोड़ना तथा मरम्मत करना
27. हाथी दांत नक्काशी
28. कार्ड बोर्ड बक्से
29. प्लास्टिक एवं पी. वी. सी. उत्पाद
30. खिलौने तथा गुड़ियां
31. पपियर मशीन
32. तांबे व पीतल कला वस्तुएं
33. लाख के उत्पाद
34. फीता, रस्सा तथा सूतली बनाना
35. बढ़ईगिरी
36. खेलकूद सामग्री
37. चमड़े के फुटवीयर
38. इलैक्ट्रिकल गैजेट्स को जोड़ना व मरम्मत करना
39. ऊन के गोले तथा लच्छी बनाना
40. चमड़ा तथा रैक्सीन से वस्तु निर्माण
41. सुगन्धित एवं शृंगारिक वस्तुएं
42. सिलाई मशीनों को जोड़ना/मरम्मत करना
43. सर्जरी पट्टी की रोलिंग तथा कटिंग
44. फाउन्टेन पेन तथा बाल पेन
45. होजरी
46. लौहारगिरी — (बशर्ते व्यवसाय भट्टी के प्रयोग के बिना एक ड्रिल मशीन, एक ग्राइन्डर तथा एक चार फुटी लेद मशीन की सहायता से एक कि. वा. से कम ऊर्जा खपत करते हुए चलाया जा रहा हो)।
47. कन्टेक्ट लैन्सिज निर्माण कार्य
48. ब्लाक बनाने तथा फोटो एनलार्जिंग
49. एक कि. वा. से फोटो सैटिंग
50. लकड़ी/कार्ड बोर्ड/ज्यूलरी बोर्ड बशर्ते अग्नि शमन विभाग से अनापत्ती प्रमाण-पत्र लिया जाए।
51. फोटो स्टेट तथा साइक्लोस्टालिंग
52. कैनवास बैग तथा बिस्तर बंद
53. बड़ियां तथा पापड़ तैयार करना
54. मशीन से ऊन की बुनाई
55. कशीदाकारी।

श्रेणी "सी" :

56. ग्राम्य तेल-घानी संबंधी व्यवसाय।

[सं. एफ. 16 (134)/73- एम. पी.]

एम. पी. जैन, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 1986

S.O. 161.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby, makes the following regulations under Clause (f) of the said Section.

CHAPTER I—GENERAL

1. Short title, application and commencement.—(1) These Regulations may be called Delhi Development Authority (Zoning) Regulations, 1983.

(2) These Regulations shall apply to the whole of the Union Territory of Delhi.

(3) These Regulations shall come into force immediately on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

(b) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.

(c) "Capital Value" means the value of land, structure and machinery allowing depreciation on the date of sanctioned Master Plan.

(d) "Commercial" means that which relates to Commerce.

(e) "Competent Authority" means the Delhi Development Authority.

(f) "District Centre" means district centre as shown in any of the plans and includes a sub-district centre.

(g) "Floor Space per worker" means the resultant after dividing the total production floor space in square metres by the total registered industrial empolyment.

(h) "Improvements to buildings" means the improvements as mentioned in Schedule III.

(i) "Industrial" means that which relates to Industry.

(j) "Non-conforming use" means the use of land or building not in conformity with the Master Plan and or the Zonal Development Plan for a zone.

(k) "Noxious industry" means such industry which may be dangerous to life, or injurious to health or property caused by fumes, effluent or smoke or by producing or storing inflammable material.

(l) "Nuisance industry" means such industry which may cause injury, danger, annoyance or offence to the scene or sight, smell or hearing or disturbance to rest or sleep.

(m) "Registered employment" means the number of workers registered with the Act under which the industry is functioning.

(n) "Residential" means that which relates to residence.

(o) "Use zones" means designation of the various uses as per Schedule I.

2. The terms not defined here expressly shall have the same meaning as defined or explained in the Master Plan.

CHAPTER II

3. Uses to be allowed by sanctioning authorities in built-up areas.—In built up areas, the sanctioning authority may allow uses permitted in a use zone until Zonal Development Plans are prepared:

4. Uses allowed by the sanctioning authorities to be incorporated in the Z.D.P.—When the Zonal Development Plan to a built-up area is prepared, the uses allowed by the sanctioning authorities be incorporated in the land-use proposals.

CHAPTER III

Shifting of non-conforming uses and conversion of certain uses :—

5. Industrial Non-conforming uses (Noxious Industries).—Any person who may have, immediately before the operation of plan, been using any land or building for running noxious industry shall shift that industry within three years to any conforming area or stop non-conforming use on the expiry of the said period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the said land or the building in that zone for "noxious industry" for such additional time as the authority may allow :—

(a) in accordance with Schedule II in case the capital value exceeds one lac rupees ;

(b) in any other case on charging non-conforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar nature of the noxious industry.

6. Industries not noxious but cause nuisance.—Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building for running a nuisance industry shall shift that industry within four years to any conforming area earmarked in the plan or shall stop the non-conforming use, on the expiry of such period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the land or building in that zone for the nuisance industry for additional time as the authority may allow :—

(1) In accordance with schedule II upto a maximum of ten years on a sliding scale if—

(a) the industry referred to in the Regulation has higher capital value ;

(b) the registered employment of industry is more ; and

(c) the industry referred to in the regulation has more floor space per worker.

(2) in any other case on charging non-conforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar circumstances of the nuisance industry.

7. Non-nuisance Industry.—Any person who may have, immediately before the operation of any plan, been using any land or building for running a non-nuisance industry shall shift that industry within six years to any conforming area earmarked in the plan or shall stop the non-conforming use on the expiry of the said period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the land or building in that zone for a non-nuisance industry for such additional time as the authority may allow :—

(1) in accordance with schedule II for a period upto twenty years on a sliding scale if :—

(a) the industry referred to in the regulation has higher capital value ;

(b) the registered employment of the industry is more ; and

(c) in any other case on charging non-conforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar circumstances of the industry.

8. Residential use in industrial area.—Residential non-conformity use and its conversion.

Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building for a non-conforming use for residential purpose in an industrial use zone, may continue to use the same for a period of ten years and on expiry thereof shall shift the non-conforming use to any conforming area earmarked in the plan.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use such land or building in that zone for such non-conforming use even beyond the said period of ten years if that person has obtained approval of the authority in respect of the layout plan and the superstrucure being put to non-conforming use.

9. Residential use in commercial areas.—Any person who may have, immediately before operation of the plan, been using any land or building for non-conforming use for residential purpose in a commercial zone may continue to use the same for a period of ten years and on expiry thereof shall shift non-conforming use to any conforming area earmarked in the plan.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use such land or building in that zone for such non-conforming use even beyond the said period of ten years if—

(a) Such person has obtained approval of the Authority in respect of the layout plan and the superstructure being put up to non-conforming use ;

(b) the authority, for reasons to be recorded in writing, allow such person the residential use to continue on first and higher floors of building in that zone.

10. Residential use in public recreational areas.—Any person who may have, immediately before operation of the plan, been using any land or building for non-conforming use for residential purpose in public recreational use zone may continue to use that land or building in case such land or building is situated in any village which was in existence on 1st September, 1962 and in all other cases only upto a period of ten years or such extended period as the Authority may keeping in view the peculiar circumstances of the case allow.

11. Commercial use in Industrial areas.—Any person may continue to use any land or building in industrial use zone for commercial purposes :—

(a) for a period of ten years after obtaining approval for conversion of the uses of such land or building to commercial use and the approval of the layout plan and structure thereon from the Authority ; and

(b) in any other case on such terms and conditions as the Authority may prescribe.

12. Commercial use in residential areas.—Any person may continue to use any land or building in a residential use zone for commercial purpose—

(a) for a period of ten years provided the land is earmarked as local commercial area in the Zonal Development Plan of that zone ; and

(b) in any other case on such terms and conditions as the authority may prescribe.

13. Commercial use in Public & semi-public areas including recreational areas.—Any person may continue to use any land or building in public or semi-public use zone including recreational zone for commercial purpose—

(a) for a period of ten years provided the land has been earmarked as local commercial area under the zonal development plan of that zone ; and

(b) in any other case on such terms and conditions as the Authority may prescribe.

14. Improvements and alterations in non-conforming areas.—Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building not in conformity with the Master Plan or the Zonal Development Plan of that area intends to make improvements or alterations in the machinery that may have been installed on such land or building may be permitted to do so provided such improvements or alterations are covered by the items mentioned in schedule III to these Regulations.

15. Temporary permits.—Any land or building may be permitted on an application in written and for reasons to be recorded in writing temporary with a time limit to be used for a purpose other than the use stipulated in the plan like tents for workers to live while constructing an industrial estate or while an area is underdeveloped and the property owner wishes to continue agriculture or in underdeveloped areas to make temporary use of the land in some other way than shown in the plan.

16. Use permitted.—It shall be lawful to continue to use any land or building in a zone provided it has been earmarked for any of the uses showing as permitted in that zone in Schedule IV attached hereto.

17. Use permitted if allowed by competent Authority after special appeal.—It shall be lawful to continue to use any land or building in a zone which has been expressly permitted to be used for any purpose, mentioned in Schedule IV hereto, by the Competent Authority after special appeal.

SCHEDULE I—AS PER REGULATION I (O)

		USE ZONE
1.	R-25	Residential
2.	R-50	Residential
3.	R-60	Residential
4.	R-75	Residential
5.	R-100	Residential
6.	R-125	Residential
7.	R-150	Residential
8.	R-200	Residential

9. R-250	Residential
10. A-1	Agricultural Green Belt
11. A-2	Rural
12. C-1	Retail Shopping.
13. C-2	General Business and Commercial (Central and sub-central business districts, business districts, distt. centres).
14. C-3	Wholesale
15. M-1	Flatted factory
16. M-2	Work-cum-Industrial Centre.
17. M-3	Special Industry
18. M-4	Light Industry and Service Industry.
19. M-5	Extensive Manufacturing
20. M-6	Extractive Industries, mining brick kilns stone crushing etc.
21. W	Warehousing, storate & depots.
22. C	Govt. & Semi-Govt. offices
23. P.	Recreation
24. F	Public & semi-public facilities.

SCHEDULE II AS PER REGULATIONS 5 TO 7 :
Time Schedule for non-conforming uses

Industrial Uses :

Conditions for Moratorium	Naxious Industries	Nuisance Industries	Non-nuisance Industries
	No. of yrs.	No. of yrs.	No. of yrs.
1	2	3	4
Industries with no. of registered employees 1 to 19 with production floor space per worker 50 sq. ft. and below and capital value less than one lakh	3	4	6
No. of registered employees between 20 to 99 (addl. years)	..	1	2
No. of registered employees 100 and above (additional years)	..	1	2
Production floor space per worker between 51 to 100 sq. ft. (Addl. years)	..	2	2
Production floor space per worker of over 100 sq. ft. (additional years)	..	1	2
Capital value between one and five lakhs (addl. years)	1	1	2
Capital Value above five l lakhs (addl. years)	1	1	4
Maximum no. of years	5	10	20

Note 1. Time is given on each count listed in the table and is cumulative in the order given in table.

2. The employment noted in table is for industry using power. For industry not using power the employment is to be taken as double.

SCHEDULE III AS PER REGULATION 14 :

Improvements to building and Machinery which may be allowed :

1. Repairs, replacement, modernisation or reform in any manner to improve productivity, efficiency and economy of the existing power plant and workshops and other auxiliary departments connected with the carrying on of the activities of the existing equipment.
2. Any re-organisation, alteration, or repairs of building that house such plant and equipment.
3. Alteration, re-organisation, extension and addition to the existing office buildings, residential house, amenities, gates, tanks, plateforms, wells, roads drains and other structures in order to maintain and improve the efficiency, productivity and economy of the existing manufacturing activities.
4. Repairs, alteration, or rebuilding of godowns on a industrial plot stocking raw-materials, machinery parts and spares, finished products building materials etc.

SCHEDULE IV AS PER REGULATION 16

Sl. No.	Use Zone	Uses Permitted
1	2	3
1.	1 to 3 R-25, R-50 R-60	Residences, nurseries, kindergartens and schools, clinics, social and cultural institutions with adequate parking facilities public utilities and buildings except service and storage yards non-commercial farms, agricultural, gardens, nurseries and green houses and neighbourhood, recreational uses including clubs and other semi-public recreational uses acessory uses, clearly incidental to residential use (except retail shops and service uses) which will not create a nuisance or hazard.
2.	4 to 6 R-75, R-100 R-125	All uses permitted in R-25 to R-60 use zones.
3.	7 to 8 R-150, R-200	All uses permitted in R-75 use zones.
4.	9 : R-250	All uses permitted in R-200 use zones.
5.	10 A-1	Agricultural horticulture orchard and vegetable farms having minimum size of farm plot 1 hectare poultry, dairy and other live stock farm and their accessory buildings and uses within the plot area limitation of minimum 2 hectare plot uses specifically shown or stated in the land use plan, like urban villages. Brick kilns and removal of clay upto 8 ft. depth beyond a distance of half a mile from the urbanisable limits of 1981.

1	2	3
6.	11 A-2	All uses permitted in Agricultural Green Belt use Zones.
7.	12 C-1	Retail shops, business and professional offices service uses like barbers and tailor, laundry and dry cleaners shops etc., restaurants and entertainment places residences social and welfare institution provided they are located in first and higher floors, clinics meat fish and fruit markets roofed storage for legitimate retail business, public and semi-public recreational uses public utilities and building, Parking area requirements for all uses must be approved.
8.	13 C-2	All uses permitted in C-1 use zone also hostels and boarding houses, guest houses and hotels, colleges, schools, research institutions, service garages, warehousing and covered storage local and central government offices. Parking area requirements for all uses must be approved.
9.	14 C-3	Wholesale and retail shops, storage for whole-sale uses except when specifically prohibited. business offices restaurants and residences provided they are located in first and higher floor, public utilities and building parking, loading and unloading requirements must be approved for all uses.
10.	15 M-1	Industries conforming to performance standards as given in illustrative list which could not cause excessive injurious or obnoxious noise, viberation, smoke gas fumes, odour, dust, effluent or other objectionable conditions and employing not more than 20 workers with power or 40 without power, covered storage for industry. Public utilities and building parking, loading and unloading requirements must be approved for all uses.
11.	16 M-2	Same as in M-1 use zone.
12.	17 M-3	Same as in M-1 use zone.
13.	18 M-4	All industries permitted in M-1, M-2, and M-3 use zones and other given in the list of industries and employing not more than 50 workers with power and 100 without power, service industries, warehousing and storage; public utilities and building and agricultural use in existing agricultural land until the area is required for development. Parking, loading and unloading area requirements must be approved for all uses.
14.	19 M-5	All uses permitted in M-4 use zone.
15.	20 M-6	Removal of gravel, earth, sand etc. extraction of minerals, with any conditions imposed by competent authority; agricultural and uses incidental to agriculture.
16.	21 W	Warehousing, storage and depot for non-parishable and non-inflamable commodities and incidental use. Parking loading and unloading area requirements must be approved for uses.
17.	22 G.	Local, state and central government offices and use for defence purposes research institutions; social and cultural institutions bus and railway passenger terminals, public utility and building, local municipal facilities, uses incidental to government offices and for their use parking requirements must be approved.
18.	23. P.	All public and semi-public recreational uses including parks, playgrounds, park ways and boulevards; special recreation areas and educational and recreational areas; bus and railway passenger terminals and Car parking area. Parking area requirement must be approved in all cases.
19.	24. F.	Local and zonal municipal officers; educational and research institutions, social and cultural institutions, monument and religious institutions; local municipal and community facilities, public utilities and building; radio transmitter and wireless stations; cremation ground and cemeteries. Parking area requirements must be approved for all uses.

SCHEDULE V AS PER REGULATION 17 :

Uses permissible after special appeal.

Sl. No.	Use Zone	Use Permissible if allowed by competent authority after special appeal.
2		3
1.	1 to 3	Temples, Mosques, churches and other places of worship; professional office or home occupations; when situated in the same dwelling as the one occupied by the professional man or women or when located in local shopping centre; commercial offices service uses and retail shops of a neighbourhood character when located in local shopping centres or in concentrated locations or as shown in the zonal plan when prepared; boarding houses, guest houses, hostels, and lodging houses governed by the Hotels, Boarding Houses, Guest Houses, Hostels, Lodging houses and Motels (Building Standards) Regulations 1977, hospitals and sanitoria not treating contagious diseases or mental patients; provided the set back and coverage of plots are such as not to constitute nuisance to residential area; college and research institutions not to be operated for the production of goods or other materials or sale provided there is no nuisance created and no part of the building is located less than 50 ft. from any plot line; municipal estate, and central government offices, raising of poultry or cattle for non-commercial uses provided that no bird or animal is housed closer than 50 ft. of a dwelling or a property line; removal of gravel clay sand or stone for development of site which will not result in the stagnation of water or cause other nuisance, bus depots, railway passenger and freight stations; petrol filling stations in roads or 100 feet right of way and above; services and storage yard, taxi and scooter stands; household industries (list attached Appendix 'A').
2.	4 to 6 R-75, R-100, R-125	All uses permissible in R 25 to R-60 use zones.
3.	7 to 8 R-150, R-200	All uses permissible in R-75 to R-125 uses zones.
4.	9 R-250	All uses permissible in R-200 use zones.
5.	10 A-1	Places of worship etc. schools; Libraries and educational and cultural buildings parks and other public and semi-public recreational use not conducted for profit; storage, processing and sale of farm products on the property where produce; the servicing and repair of farm machinery and the sale of agricultural supplies; public utility and buildings.
6.	11 A-2	Retail shops and service uses to be located in shopping centres; milk chilling stations and pasturisation plants, cottage industry and such light industry which use agricultural produce. Colleges, Rural boarding houses and hostels scientific and industrial research laboratories not to be operated for the production of goods or other materials for sale except as may be produced by a small pilot plant provided there is no nuisance caused and no part of the structure is placed closed than 100 feet from any dwelling or an adjoining premises of from any property line or road, excavation materials up to 8 feet depth; stone quarrying bus, or railway passenger and freight stations landing fields for planes and their necessary appurtenances, utilities and buildings, area needed for Defence purposes, wireless transmitting and weather stations motels.
7.	12 C-1	Social and welfare institutions, petrol filling stations, coal, wood or timber yards, service garages; light manufcaturing without nuisance or hazard and employing not more than 4 persons with or without power provided the goods manufactured are sold on the premises in retail; taxi and scooter stand, bus terminal. Parking area requirements for all uses must be approved.

1	2	3
8.	13 C-2	All uses allowed with special appeal in C-1 zone. In addition, newspaper and printing presses, the following may also be allowed in specific areas under detailed plans or zonal plans of the shopping centre; light manufacturing and service industries without nuisance or hazard and not employing more than 10 persons with or without power junk yards parking area requirements for all uses must be provided.
9.	14 C-3	Truck terminal and parking schools, clinics and social cultural institutions recreational uses, storage markets and dealing with meat and fish. Parking loading and unloading area requirements must be provided for all uses.
10.	15 M-1	Bus and truck terminal, railway passenger and freight terminals, petrol filling stations taxi and scooter stands, junk yards, dwelling for watch and ward staff, canteen and recreation facilities for the employees.
11.	16 M-2	Same as in M-1 use zone except that FAR and coverage etc. are different as given later on.
12.	17 M-3	Only such industries as given in the illustrative list that do not create nuisance of any type will be allowed, along with canteens, recreation clubs and residence to employees provided the density is not more than 25 persons per acre on the site.
13.	18 M-4	All uses allowed with special in M-4 zone. All industries mentioned in schedule subject to standard stipulated on smoke, odour, fumes and noise produced in the working of the industry.
14.	20 M-6	Nil.
15.	21 W	Warehousing of perishable and inflammable commodities. Dwellings for watch and ward staff. Parking, loading and unloading requirements must be provided.
16.	22 G	Nil.
17.	23 P	Outdoor theatres and drive-in-cinemas restaurants and selling of eatables public utility and municipal facilities uses clearly incidental to recreational use which will not create nuisance or hazard. Dwelling for watch and ward staff parking area requirements must be provided.
18.	24 F	Residence and other uses incidental to main use and in no way causing any nuisance or hazard.

(Appendix 'A' to Schedule V)

LIST OF HOUSEHOLD INDUSTRIES IN RESIDENTIAL AREA

Category 'A'

(Trades for which no power load would be sanctioned)

1. Agarbati & other products.
2. Calido & Textile Printing.
3. Cane Bamboo Products.
4. Clay Modelling.
5. Coir & other fire products.
6. Zari Zardozi.
7. Stone Engraving.
8. Framing of pictures.
9. Pithwork Mfg. of Pith-hate.
10. Umbrella Assembly.
11. Candles.
12. Batik Work.
13. Dari & Carpet weaving.
14. Khadi & Handloom.
15. Repair of watches & clocks.
16. Mfg. of soap with non-edible oil.
17. Village pottary (trade is run without using power load) industry.
18. Stove pins and safety pins.

Category 'B'

(Trades for which power load upto 1 KV be considered for sanction)

19. Jewellery work.
20. Mfg. of :—
    (i) Blanco Cakes.
    (ii) Brushes.
    (iii) Crayons.
    (iv) Ice Cream and Confectionary, Jam & Jellies.
    (v) Jam, Jellies & fruit preserves.
    (vi) Narrow Fabrics & Lac-work material.

(vii) Musical Instruments ind. repairs.

(viii) Ornamental leather-goods such as purses, hand bags.

(ix) Small Electronics.

21. Paper stationery items including book-binding.
22. Tailoring.
23. Thread balls & cotton-fillings.
24. Wood carving & Artistic-wood wares.
25. Vermicalli & Macaroni.
26. Assembly & Repairing of Electronic items.
27. Ivory carving.
28. Card Board Boxes.
29. Plastic & PVC Products.
30. Toys & Dolls.
31. Papier Machine.
32. Copper & Brass Artware.
33. Lac Products.
34. Cordage, Rope & Twine Making.
35. Carpentary.
36. Sports goods.
37. Leather Footwear.
38. Assembly & Repairs of Electrical Gadgets.
39. Wool Balling and Lachee Making.
40. Leather & Raxian Made-ups.
41. Perfumery & Cosmetics.
42. Assembly Repair of Sewing Machines.
43. Surgical Bandage rolling|cutting.
44. Fountain pens and ball pens.
45. Hosiery.
46. Blacksmith (provided the trade is run without the use of Bhatti and with the help of one drill machine, one grinder and one four ft. lathe machine altogether consuming power less than one KV).
47. Contact lenses Mfg.
48. Block making & photo enlarging.
49. Photo setting with 1 K.V.
50. Wooden|card board jewellery board subject to NOC from fire Deptt.
51. Photostat & Cyclostyling.
52. Canvas bags & holds-alls.
53. Preparation of Vadi & Papad.
54. Wool Knitting with machine.
55. Embroidery.

Category 'C'

56. Trade of village oil ghani.

[No. F. 16(134)|73-M.P.]

M. P. JAIN, Secy.

Delhi Development Authority.

MGIPRRND—VII—1 DDA/85—24-1-86—.120

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 1986/माघ 15, 1907
No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, FEB. 4, 1986/MAGHA 15, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1986

का. आ. 40(अ) :—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 52 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय सम्पदाओं के मामले में 1957 के अधिनियम सं. 61 की धारा 49 की उप धारा (1) के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति देने की शक्ति का प्रयोग इसके निदेशक (आवास) द्वारा भी किया जा सकेगा । दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 49 (1) के अंतर्गत शक्तियों का

यह प्रत्यायोजन दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 49(1) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों को पहले प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के अतिरिक्त है ।

[यू. सी. 11-ए (60)/83 पार्ट-I]
एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1986

S.O. 40(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Development Authority hereby directs that its power to give previous sanction under Sub-section (1) of Section 49 of the Act No. 61 of 1957 may also be exercised by its Director (Housing) in respect of Housing Estates of D.D.A. That this delegation of powers under Section 49(1) of Delhi Development Act is in addition to the Delegation of Powers already conferred under Section 49(1) of Delhi Development Act on other officers of Delhi Development Authority.

[U.C. 11-A(60)/83. Pt. I]
M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

S.O. No. 40(E) 4.2.1986

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i) में
24.2.86 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 21 फरवरी, 1986

सा०का०नि०सं० केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का सं० 61) की धारा 31 ग की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (त्र ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

संक्षिप्त नाम 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (अपील का प्ररूप) नियम, 1986 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं: 2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "अधिनियम" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है।

(2) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(3) "अपील अधिकरण" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 347 क के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है।

(4) "स्थानीय प्राधिकरण" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली नगर निगम या पंजाब म्युनिसिपल अधिनियम, 1911 के अधीन गठित नई दिल्ली नगर पालिका समिति या छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 13 के अधीन गठित दिल्ली छावनी बोर्ड अभिप्रेत है।

3. अपील अधिकरण को अपील इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप "अ" में की जाएगी।

4. अपील के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे

.....2/-

FORM "A"

(See rule 3)

BEFORE SHRI _____ APPELLANT TRIBUNAL

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY.

.....

Shri _____ S/o Sh. _____

resident of _____

.....Appellant

Versus

Delhi Development Authority/local authority concerned.

.....Respondent

Appeal against order dated _____

Passed by Shri _____

(Designation of the Office) under clause _____ of sub-section (1) of section 31-C of the Delhi Development Act, 1957.

Sir,

The appellant submits as under :-

1. That on _____ (date), Shri _____ has passed an order under section _____

2. That the appellant is aggrieved by the said order _____ on the following grounds :-

(i) .....

(ii) .....

etc. .....

3. That the appellant claims relief in the following manner

.....

4. That the fee of Rs.100/- deposited vide receipt No. dated _____

Date _____

Place _____

.....
(Signature of the applicant)

(To be published in part II Section 3(i) of the Gazette of India)
Extraordinary
on 24.2.86

Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)

...

New Delhi, dated the 21st Feb.86.

G.S.R.No._____ In exercise of the powers conferred by clause (ja) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act 1957 (No.61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Sealing of Development) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(i) "Act" means the Delhi Development Act 1957;

(ii) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under section 3 of the Act ;

(iii) "the competent authority" means the competent authority as defined in the "Explanation" to section 31-D of the Act.

3. Order of sealing and its service - The order of sealing a development shall be made inwriting and shall be served upon the owner or the person at whose instance the development has been commenced or is being carried out or has been completed in the manner provided under section 43 of the Act.

.....2/-

4. Manner of sealing unauthorised development - The sealing under sub-section (1) of section 31 A of the Act shall be made in the following manner, namely:-

(i) affixing the office seal on outer door or opening of the development after all other outlets and inlets to the development have been properly bolted, locked, or encircled with rope, wire or wire-mesh;

(ii) where doors and windows have not been fixed to the development or where the development is of such a nature that it cannot be encircled with rope, wire or wire-mesh in that case such development shall be covered by wooden planks, iron or cement sheets and office seal affixed in a manner that no person can enter into or upon the development without tampering the office seal; or

(iii) where any development is found locked, the lock may be broken open or any door, gate or any other barrier caused to be opened and an inventory of the articles found in the premises shall be taken in the presence of two witnesses, before sealing the development in the manner aforesaid.

5. No sealing under these rules shall be made before sun rise and after sun set.

6. The seal of the Authority or the Competent Authority shall be kept in the safe custody of the officer appointed in this behalf by the Authority or the Competent Authority as the case may be.

(R. L. PARDEEP)
Joint Secretary to the Government of India.

F. No. K-11011/2/84-DDIIB(Vol.II)

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY PART IV)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI
(LOCAL SELF GOVT. DEPARTMENT)
VIKAS BHAWAN: NEW DELHI

No.F.1/3?/77-LSG/Vol.III/Policy 10.2.86

The following notification No.U-13021/10/84-Delhi (1) dated 4th February, 1986 of the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, is hereby published for general information:

No.U-13021/10/84-Delhi (I)
Government of India
Ministry of Home Affairs,

New Delhi 4th February 1986

NOTIFICATION

S.O. ________ In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act 1984 (42 of 1984) the Central Government hereby appoints the 18th day of February, 1986 as the date on which the provisions of sections 2,3,6 to 9 (both inclusive) on the said Act shall come into force.

(No. U-13021/10/84-Delhi (I)

Sd/-
(I.P. GUPTA)
ADDITIONAL SECRETARY TO THE GOVT.OF INDIA

By order

(S.M.S. CHAUDHARY)
JOINT SECRETARY (LSG)
DELHI ADMINISTRATION DELHI.

Compared
3/7

No.F.1/32/77/LSG/Vol.III/Policy/689 10.2.86

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Additional Secretary to the Govt. of India Ministry of Home Affairs, New Delhi.
2. The Secretary to the Govt. of India M/o Law and Justice New Delhi
3. The Secretary (Home) Delhi Admn. Delhi
4. The Secretary (Law & Judicial) Delhi Admn. Delhi
5. The Administrator, New Delhi Municipal Committee New Delhi.
6. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi Town Hall Delhi.
7. The Vice Chairman, Delhi Development Authority Vikas Minar New Delhi.
8. Secretary to Lt. Governor Delhi
9. PS to the Chief Secretary Delhi Admn. Delhi
10. PS to Chief Executive Councillor, Delhi.
11. The Deputy Secretary (Public Relations) Delhi Admn. Delhi alongwith Hindi and English Version (in duplicate) for publication and supplying 50 copies of Gazette for official use.

(S.M.S. CHAUDHARY)
JOINT SECRETARY (LSG)
DELHI ADMINISTRATION DELHI.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F. 2(24)/86-MC Date: 29.7.86

Copy forwarded to all the Heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Asstt. Secretary. 31/7/86

Compound
3/7

(दिल्ली असाधारण राजपत्र के चतुर्दीय भाग में प्रकाशनार्थ)

दिल्ली प्रशासन: दिल्ली

(स्थानीय स्वशासन विभाग)

संख्या फा. 1/32/77/स्था.स्व.दि./नीति दिनांक: 10 फरवरी, 1986

निम्न अधिसूचना संख्यायू 13021/10/84- दिल्ली (1) दिनांक 4.2.86 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

संख्या यू 13021/10/84-दिल्ली(1)

भारत सरकार,

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 4फरवरी 1986

अधिसूचना

==========

का0फा0 दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 42) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा 10 फरवरी, 1986 निर्धारित करती है जिस तारीख से कथित अधिनियम की धारा 2, 3, 6 से 9 (दोनों शामिल हैं) के उपबंध लागू होगें।

(सं0यू-13021/10/84- दिल्ली(1))

हस्ता/-

(आई.पी.गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

आदेश

(एस0एम0एस0चौधरी)

संयुक्त सचिव (स्थानीय स्वशासन विभाग)

Compared
3017

संख्या फा0 1/32/77/स्था0शा0वि0/नीति/650 दिनांक 10 फरवरी 1986

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।

2- सचिव, भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय(विधायी विभाग) नई दिल्ली ।

3- सचिव, (गृह) दिल्ली प्रशासन : दिल्ली ।

4- सचिव, विधि एवं न्याय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली ।

5- प्रशासक, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली ।

6- आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ।

7- उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

8- उपराज्यपाल महोदय के निजी सचिव, दिल्ली ।

9- मुख्य सचिव महोदय के निजि सचिव, दिल्ली ।

10- मुख्य कार्यकारी पार्षद के निजि सचिव, दिल्ली ।

11- उप सचिव(जन सम्पर्क) दिल्ली प्रशासन दिल्ली को अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित 2 प्रतिलिपियां राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 50 प्रतियां इस प्रशासन को सरकारी प्रयोग के लिए ।

(एस0एम0एस0 चौधरी)
संयुक्त सचिव(स्थानीय स्वशासन विभाग)
दिल्ली प्रशासन , दिल्ली ।

Compared
[illegible]
2/7

TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY, PART IV

DELHI ADMINISTRATION: DELHI
LOCAL SELF GOVET. DPTT.
VIKAS BHAWAN, NEW DELHI.

No.F.1/32/77-LSG/Vol.III/Policy. 10.2.86

The following Notification No. U-13021/10/84-Delhi (II) dated 4th February, 1986 of the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, is hereby published for general information:-

No.U.13021/10/84-Delhi (II)
Government of India
Ministry of Home Affairs,

New Delhi the 4th Feb. 1986

NOTIFICATION

S.O.____________. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Punjab Municipal (New Delhi Amendment) Act 1984 (39 of 1984) the Central Government hereby appoints the 10th day of February, 1986 as the date on which the provisions of section 2, 10, 11, 12 14 and 15 of the said Act shall come into force.

(No.U-13021/10/84-Delhi (II)

Sd/-
(I.P. GUPTA)
ADDITIONAL SECRETARY TO THE GOVT. OF INDI

By order,

(S.M.S.CHAUDHARY)
JOINT SECRETARY (LSG)
DELHI ADMINISTRATION DELHI.

Compared
[illegible]
3/7

No.F.1/32/77-LSG/Vol.III/Policy/650 10.2.86

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Additional Secretary to the Govt. of India Ministry of Home Affairs, New Delhi.
2. The Secretary to the Govt. of India M/O Law and Justice New Delhi.
3. The Secretary (Home) Delhi Admn. Delhi
4. The Secretary (Law & Judicial) Delhi Admn. Delhi
5. The Administrator, New Delhi Municipal Committee New Delhi.
6. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi Town Hall Delhi
7. The Vice Chairman Delhi Development Authority Vikas Minar New Delhi
8. Secretart to Lt. Governor Delhi
9. PS to the Chief Secretary Delhi Admn. Delhi
10. PS to Chief Executive Councillor Delhi
11. The Deputy Secretary (Public Relations) Delhi Admn. Delhi alongwith Hindi and English version (in duplicate) for publication and supplying 50 copies of Gazette for official use.

Sd/-
(S.M.S.CHAUDHARY)
JOINT SECRETARY (LSG)
DELHI ADMNISTRATION DELHI.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F.2(14)/86-MC Date: 29.7.86

Copy forwarded to all the Heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Asstt. Secretary.

दिल्ली प्रशासन: दिल्ली

(स्थानीय स्वशासन विभाग)

संख्या फा. 1/32/77/स्था.स्व.वि./नीति   दिनांक 10 फरवरी, 1986.

निम्न अधिसूचना संख्या यू-13021/10/84-दिल्ली (1) दिनांक 4.2.86 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है ।

सं0 यू-13021/10/84-दिल्ली(1)

भारत सरकार,

गृह मंत्रालय,

नई दिल्ली, दिनांक 4.2.86

अधिसूचना

का0आ0 पंजाब नगर पालिका (नई दिल्ली संशोधन) अधिनियम 1984 (1984 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा 10 फरवरी, 1986 निर्धारित करती है जिस तारीख से कथित अधिनियम की धारा 2, 10 से 12, 14 और 15 के उपबंध लागू होंगे ।

(सं0 यू-13021/10/84-दिल्ली (1))

ह0/-

(आई.पी. गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

आदेश से,

(एस.एम.एस. चौधरी)

संयुक्त सचिव (स्थानीय स्वशासन विभाग)

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

क्रमशः.........2

संख्या फा० 1/32/77 स्था०स्व०शा०/नीति/650 दिनांक 10 फरवरी, 1985

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव, भारतसरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) नई दिल्ली।
3. सचिव, (गृह) दिल्ली प्रशासन: दिल्ली।
4. सचिव, विधि एवं न्याय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली।
5. प्रशासक, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली।
6. आयुक्त दिल्ली नगर निगम, दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
8. उपराज्यपाल महोदय के निजी सचिव, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव महोदय के निजी सचिव, दिल्ली।
10. मुख्य कार्यकारी पार्षद के निजी सचिव, दिल्ली।
11. उप सचिव (जन सम्पर्क) दिल्ली प्रशासन दिल्ली को अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित 2 प्रतिलिपियां राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 50 प्रतियां इस प्रशासन को सरकारी प्रयोग के लिए।

(एस.एम.एस चौधरी)
संयुक्त सचिव (स्थानीय स्वशासन विभाग)
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

Compared
[illegible]
3/7

BY SPECIAL MESSENGER
MOST IMMEDIATE

No.K-11011/2/84-DDIIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)
.....

Nirman Bhavan, New Delhi-11001

Dated the 21st February, 1986.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
NEW DELHI.

Subject: Notification of rules under Delhi Development Act in part II section 3(i) of the Gazette of India extraordinary.

.....

Sir,

I enclose two notifications, both bearing No.K-11011/2/84-DDIIB, both dated 21.2.1986 (English & Hindi versions). The same may please be published in the Extra-ordinary issue of Gazette of India on 24.2.1986 (and not earlier) as they are required to be enforced from that date.

Yours faithfully,

sd/-

(R.L.PARDEEP)

Joint Secretary to the Government of India

Compared
3/7

Copy to:-

1. The parliament Library, New Delhi along with 15 copies of the Notification.

2. Lok-Sabha Secretariet New Delhi along with a copy of each of the Notification.

3. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi along with a copy of each of the Notification.

4. The Ministry of Law(Legislative Department), New Delhi along with 10 copies of the Notification.

5. The Secretary (L&B), Delhi Admn., N.Delhi along with two copies each of the two notification for necessary action.

6. The Vice-Chairman, DDA, New Delhi with a copy of each of the two notification.

7. The Secretary, DDA, New Delhi alongwith 10 copies each of the two notifications.

8. The Chief Legal Advisor, DDA with a copy of each of the two notifications.

9. The Commissioner Lands, DDA New Delhi with a copy of the two notifications for necessary action.

10. The ministry of Home Affairs, New Delhi with reference to their endst.No.U-13021/10/84-Delhi(D.I) dated 11.2.86

sd/-
(H.L.BHATIA)
Desk Officer.

Delhi Development Authority
Meeting Cell

No. F.2(14)/86-MC Dated: 29.7.86

Copy forwarded to all the heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Compared
[illegible]

ASSTT. SECRETARY 31/7/86

Published in Part II Section 3 (1) of the Gazette of India Extraordinary on 24.2.86.

Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)

New Delhi, Dated the 21st Feb., 86.

G.S.R. No. In exercise of the powers conferred by clause (jb) of sub-section (2) of section 56 read with sub-section (3) of section 31-C of the Delhi Development Act 1957 (No. 61 of 1957), the Central Government makes the following rules, namely:-

1. Short title (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Form of Appeal) Rules 1986.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions In these rules unless the context otherwise requires,

(1) "Act" means the Delhi Development Act 1957;

(2) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under section 3 of the Act;

(3) "Appellate Tribunal" means Appellate Tribunal constituted under section 347 A of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 and deemed as such under section 31-B of the Act;

(4) "local authority" means the Municipal Corporation of Delhi constituted under Section 3 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 (66 of 1957) or the New Delhi Municipal Committee constituted under the Punjab Municipal Act 1911 or Delhi Cantonment Board constituted under section 13 of the Cantonment Act, 1924.

3. An appeal to the Appellate Tribunal shall be made in Form 'A' annexed to these rules.

4. The appeal shall be accompanied by:

i. a certified copy of the order appealed against.

ii. statement of the value of the subject matter of the appeal.

iii. documents along with a list thereof on which the appellant wishes to place reliance during the course of the hearing before the Appellate Tribunal.

...2/-

5. The appellant shall deposit a sum of Rs.100/- on account of fees in the office of the Tribunal and attach a copy of the receipt alongwith the appeal.

F.No.K-11011/2/84-DDIIB
(Vol.II)

(R.L. PARDEEP)
Joint Secretary to the Govt. of India.

FORM "A"

(See rule 3)

BEFORE SHRI _____ APPELANT TRIBUNAL

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY.

... Shri _____ S/o Sh. _____

resident of _____

.....Appellant

Versus

Delhi Development Authority/local authority concerned.

.....Respondent

Appeal against order dated _____

Passed by Shri _____

(Designation of the Office) under clause

_____ of sub-section (1) of section

31-C of the Delhi Development Act, 1957.

Sir,

The appellant submits as under:-

1. That on _____ (date), Shri _____

has passed an orddr under section _____

2. That the appellant is aggrieved by the said order _____

_____ on the following grounds:-

i. .....

ii. .....

etc. .....

3. That the appellant claims relief in the following manner

.....

.....

4. That the fee of Rs.100/- deposited vide receipt no.

Dated _____

Date _____

Place _____

.....

(Signature of the applicant)

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(i) OF THE GAZETTE OF INDIA)
EXTRAORDINARY
ON 24.2.86

Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)
.....

New Delhi, dated the 21st Feb.86.

G.S.R.No_____ In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act 1957 (No.61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Sealing of Development) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions In these rules, unless the context otherwise requires,

(i) "Act" means the Delhi Development Act 1957:

(ii) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under section 3 of the Act:

(iii) "the competent authority" means the competent authority as defined in the "Explanation" to section 31-D of the Act.

3. Order of sealing and its service - The order of sealing a development shall be made inwriting and shall be served upon the owner or the person at whose instance the development has been commenced or is being carried out or has been completed in the manner provided under section 43 of the Act.

—

.....2/-

4. Manner of sealing unauthorised development - The sealing under sub-section (1) of section 31Aofthe Act shall be made in the following manner, namely:-

(i) Affixing the office seal on outer door or opening of the development after all other outlets and inlets to the development have been properly bolted, locked, or encircled with rope, wire or wire-mesh;

(ii) Where doors and windows have not been fixed to the development or where the development is of such a nature that it cannot be encircled with rope, wire or wire-mesh in that case such development shall be covered by wooden planks, iron or cement sheets and office seal affixed in a manner that no person can enter into or upon the development without tampering the officer seal; or

(iii) Where any development is found locked, the lock may be broken open or any door, gate or any other barrier caused to be opened and an inventory of the articles found in the premises shall be taken in the presence of two witnesses, before sealing the development in the manner aforesaid.

5. No sealing under these rules shall be made before sun-rise and after sun set.

6. The seal of the Authority or the Competent Authority shall be kept in the safe custody of the officer appointed in this behalf by the Authority or the Competent Authority as the case may be.

(R.L.PAPDREP)
JOINT SECRETARY TO THE GOVERMENT OF INDIA.

F.No.K-11011/2/84-DDIIB(Vol.II)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i) में
24-2-86 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 21 फरवरी, 1986

सा0का0नि0सं0 केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का सं0 61) की धारा 31 ग की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (त्र खा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

संक्षिप्त नाम । (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (अपील का प्रारूप) नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें ।

परिभाषाएं 2. इन नियमों मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) "अधिनियम" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है ।

(2) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

(3) "अपील अधिकरण " से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 347 क के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ।

(4) "स्थानीय प्राधिकरण" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली नगर निगम या पंजाब म्युनिसिपल अधिनियम, 1911 के अधीन गठित नई दिल्ली नगर पालिका समिति या छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 13 के अधीन गठित दिल्ली छावनी बोर्ड अभिप्रेत है ।

3. अपील अधिकरण को अपील इन नियमो से उपाबद्ध प्ररूप "अ" में की जाएगी ।

4. अपील के साथ निम्नलिखित संलग्न होगे ।

(i) उस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(ii) अपील को विषय वस्तु के मूल्य का विवरण ।

(iii) दस्तावेज उनकी एक सूची सहित जिनका अपीलार्थी अपील अधिकरण के समक्ष सुनवाई के दौरान अवलंब लेना चाहता है ।

5. अपीलार्थी फीस के मद्दे 100 रूपए की रकम अधिकरण के कार्यालय में जमा करेगा और उस रसीद की एक प्रति अपील के साथ संलग्न करेगा ।

(आर. एल. प्रदीप)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फाईल सं0 के 11011/2/84 -डी.डी.आई.आई.वी.

.....

प्ररूप "अ"

(नियम 3 देखिए)

श्री_____

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अपील प्राधिकरण के समक्ष

श्री_____पुत्र श्री_____

_____जो_____का निवासी है

बनाम अपीलार्थी

दिल्ली विकास प्राधिकरण/सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण

प्रतिवादी

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 31 ग की उपधारा (1) के खण्ड_____के अधीन श्री_____

(अधिकारी का पदाभिधान)

द्वारा पारित तारीख_____के आदेश के विरुद्ध अपील ।

महोदय,

अपीलार्थी निवेदन करता है:-

1. यह कि तारीख_____के श्री_____ने धारा _____के अधीन एक आदेश पारित किया है ।

2. यह कि अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों पर उक्त आदेश से व्यथित है ।

(1)_____

(2)

आदि.....

3. यह कि अपीलार्थी निम्नलिखित रीति से अनुतोष का दावा करता है

_____

4. यह कि रसीद सं0 तारीख

धारा 100/- रुपये की फीस जमा की गई

तारीख.....

स्थान..... .....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(i) में
24-2-86 को प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 1986

सा.का.नि. सं.

केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 61) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (त्र क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकास का सीलबन्द) नियम, 1986 हैं ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें ।

2. परिभाषाएं:- इन नियमो मे जब तक कि संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) "अधिनियम" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है,

(ii) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(iii) "सक्षम प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 31-घ के "स्पष्टीकरण" मे यथा परिभाषित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ।

3. सीलबन्द का आदेश और उसकी तामील

विकास कार्य को सीलबंद करने का आदेश लिखित रूप मे किया जाएगा और उसकी तामील स्वामी या ऐसे व्यक्ति पर जिसकी प्रेरणा से विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है या पूरा किया गया है, अधिनियम की धारा 43 के अधीन उपबंधित रीति मे की जाएगी ।

4. अप्राधिकृत विकास कार्य के सीलबन्द करने की रीति -

(1) अधिनियम की धारा 31 क की उपधारा (1) के अधीन सील बन्द निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात:-

विकास कार्य के अन्य सभी बाहर जाने के मार्ग और अन्दर

आने के मार्गों को उचित रूप से बंद करने, ताला लगाने या रस्सी, तार या तार जाल से घेर देने के पश्चात् विकास कार्य के बाहरी द्वार पर प्राधिकारिक मुद्रा लगाकर,

(ii) जहां दरवाजे और खिड़कियां विकास कार्य में नहीं लगाई गई हैं, या जहां विकास कार्य इस प्रकार का है कि उसे रस्सी, तार, तार जाल से नहीं घेरा जा सकता है, वहां ऐसी दशा में ऐसे विकास कार्य को लकड़ी के तख्तों, लोहा या सीमेंट की चदरों से ढका जाएगा और प्राधिकारिक मुद्रा इस रीति से लगाई जाएगी कि और व्यक्ति प्राधिकारिक मुद्रा को बिगाड़े बिना विकास कार्य के अन्दर या अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता है या

(iii) जहां किसी विकास कार्य में ताला लगा पाया जाता है, वहां ताला तोड़कर खोला जा सकेगा या किसी अन्य दरवाजे, द्वार या किसी अन्य रोध को खुलवाया जा सकेगा और पूर्वोक्त रीति से विकास कार्य को सीलबन्द करने से पूर्व दो साक्ष्यों की उपस्थिति में परिसर में पाए गए सामान की एक तालिका बना ली जाएगी ।

5. इन नियमों के अधीन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात् कोई सीलबन्द नहीं की जाएगी ।

6. प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी की मुद्रा, यथास्थिति प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाएगी ।

फाईल सं0 के-. 11011/2/84-डी.आई.आई.बी.

(आर.एल.परदेशी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

.....

BY SPECIAL MESSENGER
MOST IMMEDIATE

No.K-11011/2/84-DDIIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)

NEW DELHI DATED THE 21.2.1986

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Ring Road,
NEW DELHI.

Subject: Enforcement of the Delhi Development (Amendment) Act, 1984-Issue of Notification in Part II Section 3(ii) of the Gazette of India Extra-ordinary.

.....

Sir,

I enclose a notification No.K-110011/2/84-DDIIB, dated 21.2.1986 (both English and Hindi versions) on the above subject. The same may please be published in the Extra-ordinary issue of Gazette of India on 21.2.86 as the provisions of the aforesaid Act are being enforced with effect from 24th February, 1986.

Yours faithfully,

sd/-

(R.L.PARDEEP)

Joint Secretary to the Government of India.

Compared
3/17

Copy to:-

1. The parliament Library, New Delhi along with 15 copies of the Notification.

2. Lok-Sabha Secretariet New Delhi along with a copy of each of the Notification.

3. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi along with a copy of each of the Notification.

4. The Ministry of Law (Legislative Department), New Delhi along with 10 copies of the Notification.

5. The Secretary (L&B), Delhi Admn., N.Delhi along with two copies each of the two notification for necessary action.

6. The Vice-Chairman, DDA, New Delhi with a copy of each of the two notification.

7. The Secretary, DDA, New Delhi alongwith 10 copies each of the two notifications.

8. The Chief Legal Advisor, DDA with a copy of each of the two notifications.

9. The Commissioner Lands, DDA New Delhi with a copy of the two notifications for necessary action.

10. The ministry of Home Affairs, New Delhi with referance to their endst.No.U-13021/10/84-Delhi (D.I) dated 11.2.86

sd/-
(H.L.BHATIA)
Desk Officer.

Delhi Development Authority
Meeting Cell

No. F.2(14)/86-MC Dated: 29.7.86

Copy forwarded to all the heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Compared
[illegible]

ASSTT. SECRETARY [illegible signature]

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY ON 21.2.86.

.....

Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)

.....

New Delhi, dated the 21st Feb'86

N O T I F I C A T I O N

S.O._____ In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Delhi Development (Amendment) Act, 1984 (Act 38 of 1984), the Central Government hereby appoints Twenty fourth day of February, 1986, as the date on which the provisions of section 4, clause (c) of section 5 and sections 6, 10 and 11 of the said Act shall come into force.

F.No.K-11011/2/84-DDIIB(Vol.II)

(R.L.PARDEEP)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii) में
21.2.86 को प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

....

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 1986.

अधिसूचना

का.आ.

केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम 1984 (1984 का 38वां नियम) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 फरवरी, 1986 को उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध की धारा 4, धारा 5 का खण्ड (ग) और 6, 10 और 11 को प्रवृत्त होंगे, नियम करती है ।

फाइल सं0 के-11011/2/84-डी डी ii बी (जिल्द ii)

(आर.एल.प्रदीप)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

.....

CONFIDENTIAL

No.K-16017/31(7)/84-Coord.
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya0

New Delhi dated the 24th feb. 86

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT: Composition of the Group of Ministers to review public sector enterprises, export promotion, import substitutions, etc.

In continuation of the Ministry's Office Memorandum of even number dated the 10th December 85 a copy of Cabinet Secretariat's O.M. No.47/1/10/85- dated the 26th November 1985 is sent herewith for information and guidance.

Hindi version is also enclosed.

-Sd/-
(O.P. WASUJA)
SECTION OFFICER.

TO

1. PS to HM/PS to Minister of State.
2. PS to, Secretary
3. All Joint Secretaries/Directors/Deputy Secretaries (by name)
4. Heads of All Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F.2(14)/86-MC Date: 29.7.86

Copy forwarded to all the Heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Asstt. Secretary

No. 47/1/10/85

GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)

New Delhi 26 November 1985

Subject: Composition of the group of Ministers to review public sector enterprises, export promotion import substitutions, etc.

In supersession of this Secretariat Memo No.11/2/1/85-Cab. dated 16th October, 1985 on the above subject, the undersigned is directed to say that it has been decided with the approval of the Prime Minister that the composition of the Group of Ministers to review public sector enterprises, export promotion, import substitutions, etc. shall be as under:

1. Shri Vishwanath Pratap Singh — Chairman
   Minister of Finance
2. Shri Arjun Singh
   Minister of Commerce
3. Sh. K.C. Panth
   Minister of Steel and Mines
4. Sh. Narayan Datt Tiwari
   Minister of Industry
5. Shri Vasant Sathe
   Minister of Energy
6. Dr. Manmohan Singh
   Deputy Chairman
   Planning Commission

Sd/-
(H.R. GOEL)
for Cabinet Secretary
Tel. 3015802

Sh. Vishwanath Pratap Singh, Minister of Fiance
Sh. Arjun Singh Minister of Commerce
Sh. K.C. Panth Minister of Steel and Mines
Shri Narayan Datt Tiwari Minister of Industry
Shri Vasant Sathe Minister of Energy
Dr. Manmohan Singh Deputy Chairman, Planning Commission

CONFIDENTIAL

Confirmed
30/7

Copy forwarded for information to:

Secretary to the Prime Minister
Additional Secretary to the Prime Minister
(Smt. Otima Bordia)
Additional Secretary to the Prime Minister
(Sh. M.S. Ahluwalia)

Sd/-
(H.R. GOEL)
Deputy Secretary
Tel: 3015802

Copy also forwarded to all Secretaries to
the Government of India for information

Sd/-
(H.R. GOEL)
DEPUTY SECRETARY
TEL: 3015802

CONFIDENTIAL

Sh. Ramesh Chandra
Secretary
Ministry of Urban Development
10, Krishna Menon Marg (3017476)

Compliment
3/7

नं० 47/1/10/86
भारत सरकार
मंत्री मण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1986
5 अग्रहायण, 1907

विषय:- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापनों आदि की संवीक्षा करने हेतु मंत्रियों के ग्रुप का गठन ।

उपर्युक्त विषय पर इस सचिवालय के 16 अक्तूबर, 1985 के ज्ञापन सं० 11/2/85 मंत्री के अधिक्रमण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधान मंत्री की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापनों आदि की संवीक्षा हेतु मंत्रियों के ग्रुप का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

1. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ...अध्यक्ष
   वित्त मंत्री
2. श्री अर्जुन सिंह
   वाणिज्य मंत्री
3. श्री के०सी० पन्त
   इस्पात और खान मंत्री
4. श्री नारायण दत्त तिवारी
   उद्योग मंत्री
5. श्री वसंत साठे
   ऊर्जा मंत्री
6. डा० मनमोहन सिंह
   उपाध्यक्ष, योजना आयोग

ह०/-

(हरिराम गोयल)
कृते मंत्रिमण्डल सचिव
दूरभाष: 3015802

सेवा में,

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वित्त मंत्री
श्री अर्जुन सिंह, वाणिज्य मंत्री
श्री के॰सी॰पन्त, इस्पात और खान मंत्री
श्री नारायण दत्त तिवारी, उद्योग मंत्री
श्री वसंत साठे, ऊर्जा मंत्री
डा० मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष, योजना आयोग

गोपनीय

"रवि"

170 प्रतियां

Compared

.....2/-

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE)

LAND & BUILDING DEPTT. DELHI ADMINISTRATION: DELHI

N O T I F I C A T I O N

Dated the 4th March 86

No.F.16(77)/85-L&B:-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of Delhi Development Act, 1957(61 of 1957) read with notification of the Government of India in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development No. 18011(28)/67-UD dated the 14th February, 1969, the Administrator of the Union Territory of Delhi, hereby de-notifies the development area No.106 (declared as development area) vide notification No.16/65/70-L&B dated 27.11.1970.

S C H E D U L E

Development area No.	zone No.	Description of the Development area.
106	Part of zone A-9	North :Bahadur Garh Road East :Qutab Road South :Sadar Bazar Road. West : Rui Mandi Road.

By order.

(G.C.PILLAI)
UNDER SECRETARY(LAND ACQUISTION)
LAND & BUILDING DEPARTMENT
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

No.F.16(77)/85-L&B/7522-39 Dated the 4th Marth,'86

Copy forwarded to :-

1. Secretary to the Govt.of India, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Vice-Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Minar, New Delhi.
3. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Delhi.
4. Commissioner(Lands), Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
5. Engineer Member, Delhi Development Authority, Vikas Minar New Delhi.
6. Town Planner, Municipal Corporation of Delhi, Old Hindu College Building, Kashmere Gate, Delhi.
7. Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, New Delhi.
8. Secretary to Lt.Governor/C.E.C./E.Cs., Delhi.
9. Under Secretary(LSG), Delhi Administration, New Delhi.
10. Asstt.Housing Commissioner(Cord), L&B Deptt., New Delhi.
11. Chief Engineer, D.D.A., New Delhi.
12. Tehsildar (L&B), Vikas Bhawan, New Delhi.
13. P.S.to Chief Secretary, Delhi.
14. Supdt.(LA), Land & Building Department, Vikas Bhawan, New Delhi.

(G.C.PILLAI)
UNDER SECRETARY(LAND ACQUISITION)
LAND & BUILDING DEPARTMENT
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F.2(14)/86-MC Date: 29.7.86

Copy forwarded to all the Heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Asstt. Secretary. 31/7/86

Compared
[illegible]
4/7

No. 26(25)/20-Point/82-83
DELHI ADMINISTRATION: DELHI
PLANNING DEPARTMENT

5-Sham Nath Marg: Delhi
Dated 19th March, 1986.

N O T I F I C A T I O N

In partial modification of this office 'Notification' of even number dated the 25th March, 1985, the Lt. Governor Delhi is pleased to nominate S/Shri Babu Ram Solanki & Hari Ram Khatri Member Metropolitan Council as a member of the State Level Committee for implementation of New-20-Point Programme in the Union Territory of Delhi. The name of the late Sh. Lalit Maken and Shri Jagdish Tytler are hereby deleted.

(M.C. VERMA)
SECRETARY PLANNING.

No.26(25)/20-Point/82-83 Dated the 19th March, 1986.

Copy forwarded to:

1. Secretary to the Lt. Governor Delhi
2. The Secretary to the Chief Executive Councillor/ Executive Councillor (Development)/Executive Councillor (Health) / Executive Councillor (Education)
3. All Members.
4. All Secretaries/Heads of Departments, Delhi Admn. Delhi.
5. Commissioner, MCD Town Hall Delhi
6. All Jt. Secretaries/Dy. Secretaries/Under Secretaries, Delhi Administration Delhi
7. Vice Chairman, DDA Vikas Minar, New Delhi.
8. General Manager DESU Shakti Sadan New Delhi.
9. Dy. Commissioner WS & SDW Link House-New Delhi
10. Administrator (NDMC) Town Hall New Delhi.
11. Chairman DSIDC Connaught Place New Delhi
12. Managing Director (DTDC) 18-A Shopping cum office complex Defence Colony New Delhi.
13. Managing Director (DFC) Connaught Place New Delhi
14. Managing Director Delhi State Civil Supplies Corporation Delhi.

15. Managing Director Delhi Schedule Caste Financial & Development Corporation Old Sectt Delhi

16. Chairman Delhi State Mineral Development Corporation Mohan Singh Palace, Connaught Place New Delhi.

17. Commissioner (Slum) DDA Jhandewalan New Delhi.

(M.C. VERMA)
SECRETARY PLANNING

NO. 26(25)/20-Point/82-83 Dated the 19th March 86

Copy forwarded for information to :

1. The Joint Secretary (UT) to the Govt of India Ministry of Home Affairs, New Delhi

2. The Joint Secretary (State Plan) Planning Commission Yojana Bhawan New Delhi

3. The Adviser (20-Point Programme) Ministry of Programme Implementation, Yojana Bhavan, New Delhi.

(M.C. VERMA)
SECRETARY PLANNING.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

No.F2(14)/86.MC Dated: 29.7.86

copy forwarded to all the Heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Asstt. Secretary.

CONFIDENTIAL

No.O.17035/57(1)/84-Coor.
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)

.....

New Delhi, dated the 10th April, 1986

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT: Barring of business dealingsin non-statutory shpere with certain firms by the Government of India-Instructions of the Deptt. of Supply.

.....

The undersigned is directed to forward herewith copies of the Deptt.of Supply Office Memoranda No.13/17/83-Vig. dated 20.2.86, 13/9/83-Vig. dated 24.2.86, 13.4.83-Vig. dated 24.2.86, C-36011/15/84-Vig. (DOS) dated 26.2.86 and C-36011/7/84-Vig.dated 26.2.86 for information and necessary action.

Sd/-
(O.P.WASUJA)
Section Officer

Encl: as stated.

To

1. Directorate General of Works, CPWD, (Shri G.S.Rao, DG)
2. Directorate of Printing, New Delhi (Shri M.J. Singh, Dir.)
3. NBCC Ltd., Lodhi Estate, New Delhi (Shri S.C.Kapoor, Chairman-Cum-Managing Dir.
4. Hindustan Prefab Ltd., (Brig.V.Wadhwan, Chairman-cum-Managing Director.
5. DDA, Vikas Minar, New Delhi (shri M.P.Jain, Secretary).
6. Controller of Stationery, 3, Church Lane, Calcutta-700001. (Sh.P.N.Saxena, Controller)
7. Deptt.of Publications, Civil Lines, Delhi (Shri S.N.Chakraborty, Controller).

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MEETING CELL)

No.F.2(14)/86-MC

Dt. 29.7.86

Copy forwarded to all the Heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Compared

ASSTT. SECRETARY 31/7/86

Copy of O.M.No.13/17/83-Vig. dated 20.2.86 from Department Of Supply.

....

The undersigned is directed to say that Government of India have decided to ban business dealings, in the non-statutory sphere, with M/s Frontier Timber Products, Post Box No.29, Digboi, Assam-a Parternship concern (details of partnership will follow), for a period of three years w.e.f. 20th February, 1986.

sd/-
(R.DORAISWAMI)
Under Secretary to the Govt.of India

....

Copy to O.M.No.13/9/83-Vig.dated 24.2.86 from Department of Supply.

....

The undersigned is directed to say the Government of India have decided to ban business dealings, in the non-statutory sphere, with Plastic Extrusions and Moulders, 16/26-A, Civil Lines, Kanpur-Proprietor Shri Radhey Shyam Sareogi-for a period of three years from the date of issue of this O.M.

sd/-
(R.DORAISWAMI)
Under Secretary to the Govt. of India

Copy to O.M.No.13/4/83-Vig dated 24.2.86 from Department of Supply.

....

The undersigned is directed to say that the Government of India have decided to ban business dealings in the non-statutory sphere with M/s Model Plastic Company, 59/52, Birhana Road, Kanpur -208001(U.P.)-a partnership concern-and the partners of the firm, as indicated below for a period of three years from the date of issue of this O.M.:

	Partners of firm	Address
1.	Shri Vishwanath Saraggi S/o Shri Rattan Lal Sareogi	59/52, Birhana Road, Kanpur-208001.(U.P)
2.	Shri D.K.Saraogi S/o Shri Rattan Lal Saraogi	59/52 Birhana Road Kanpur-208001.(U.P)

Compared
3/7

sd/-
(R.DORAISWAMI)
Under Secretary to the Govt.of India.

Copy of O.M.No.C-36011/15/84-Vig(DOS), dated 26th February, 1986 from Department of Supply.

.....

The undersigned is directed to say that Government of India have decided to ban business dealings, in the non-statutory sphere, with Rituraj Industries, 16 Laxmibai Nagar Industrial Estate, Indore-452006-Proprietor Shri V.K.Tongia (resident of 16, Laxmibai Nagar, Industrial Estate, Indore 452006) for a period of five years from the date of issue of this Office Memorandum.

sd/-

(R.DORAISWAMI)

Under Secretary to the Govt.of India

Copy of O.M. .No C-36011/7/84-Vig dated 26th February from Department of Supply.

.....

The undersigned is directed to say that Government of India have decided to ban business dealings, in the non-statutory sphere , with S.K.Chemicals,Sahebganj, Gorakhpur Proprietor SHri S.K.Aggarwal (Works: D-20. Govt Industrial Estate, Gorakhpur) for a period of one year from the date of issue of this office Memorandum.

Surendra Kumar Aggarwal resident of Ismailpur, Distt.Gorakhpur)

sd/-

(R.DORAISWAMI)

Under Secretary to the Govt.of India

Compared
and
Sent

(TO BE PUBLISHEDIN PART IV OF DELHI GAZETTE)

LAND & BUILDING DEPARTMENT: DELHI ADMINISTRATION: DELHI

CORRIGENDUM

Dated the 8th July 86.

No.F.16(2)/22/76-MP/L&B:- In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Notification of the Government of India in the Ministry of Health Family Planning & Urban Development No.18011(28)/67-UD dated 14th February, 1969, the Administrator of Union Territory of Delhi hereby makes the following additions/ amendments to the Land & Building Department, Delhi Administration, Delhi Corrigendum's No.F.16(2)/22/76/MP/L&B dated 10.9.81 for declaring additional area of 0.52 hect. as 'Development Area' of the Authority so as to form part of existing development Area No.73 and the boundaries of the said area of 0.52 hect. are as under:-

Development area no.	Zone	Description of Development Area	Area in Hect.
1	2	3	4
73	E-9	North: Existing Drain (New) West: Existing Drain parallel to Master Plan Road No.57 East & South: Existing Drain (Old)	0.52

With the declaration of the above said additional area as part of Development Area No.73 the total area of the Development Area No.73 shall become 291.276 Acres or 117.876 Hects (approx) with its amended boundaries as under:

NORTH: EXISTING DRAIN (NEW)
WEST: EXISTING DRAIN PARALLEL TO MASTER PLAN ROAD NO.57
EAST & SOUTH: MASTER PLAN ROAD NO. 58

By order
Sd/-
(A.S.AWASTHI)
JOINT SECRETARY (LAND&BUILDING)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

Compared
KM
30/7

No.F.16(2)/22/76-MP/L&B1179-94 Dated the 8th July 1986

Copy forwarded to:

1. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Urban Development Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Minar New Delhi.
3. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi Town Hall, Delhi.
4. Engineer Member Delhi Development Authority, Vikas Minar New Delhi.
5. Town Planner, Municipal Corporation of Delhi Old Hindu College Building, Kashmere Gate, Delhi.
6. Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar New Delhi
7. Secretary to Lt. Governor Delhi.
8. Secretary to Chief Executive Councillor Delhi.
9. Secretary to Executive Councillor (Revenue) Delhi
10. Private Secretary to Chief Secretary, Delhi Administration Delhi
11. Under Secretary (Coord) Delhi Administration, Delhi
12. Under Secretary (LSG) Vikas Bhawan, New Delhi.
13. Chief Engineer, Delhi Development Authority, New Delhi.
14. Tehsildar (L&B) Vikas Bhawan, NewDelhi.
15. Executive Officer, (DA) Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA New Delhi.

Sd/-
(A.S. AWASTHI)
JOINT SECRETARY (LAND & BUILDING)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

No. F.2(14)/86.MC Dated: 29-7-86

Copy forwarded to all the Heads of the Departments for information and necessary action action at their end.

Compared
[illegible]
2/7

Asstt. Secretary. [illegible]

A-42011/16/86-Coord.
Government of India,
Ministry of Urban Development

Dated: 16th Oct.,1986.

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Correct description of the Government in the contracts made on behalf of the Government of India.

.-.-.-.

The undersigned is directed to send herewith a copy of Ministry of Law and Justice (Deptt. of Legal Affairs) O.M. No.4501/86-Adv.'A' dated 12.8.86, for information and necessary action.

Sd/-
(RAJAN S. LALA)
Section Officer

To.

1. All attached/subordinate offices.
2. Autonomous & Statutory Bodies/Public Sector Undertakings etc.
3. The Chief Controller of Accounts, Nirman Bhawan.
4. US(A) in the Sectt.

.-.-.-.

OFFICE OF THE CHIEF LEGAL ADVISER
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

No.PS/CLA/Circular/86 Dated:31st Oct.86.

2368/Adv
7/11/86

The undersigned is directed to circulate herewith a copy of the Ministry of Urban Development office Memorandum No.A-42011/16/86-Coord. dated 16.10.1986 alongwith a copy of Ministry of Law and Justice (Deptt. of Legal Affairs) O.M. No.4501/86-Adv.'A' dated 12.8.86 for information and necessary action.

1058.9
6.11.86

31/X/86
(BHAVNESH DHINGRA)
Private Secretary

To

1. All Heads of Departments.
2. All Sr. Law Officers.

Copy of Ministry of Law and Justice (Deptt. of Legal Affairs) D.O. No.4501/86-Adv.'A' dated 12th August, 1986.

It has been noticed that no uniform practice is being followed by the different Ministries/ Departments while describing the Government in contracts made on behalf of the Government of India. At times, the Government is described in such contracts by such different expressions as "the Government of India" "The Republic of India" "the Union of India" "the Republic of India acting by its President" or "the Union of India acting by its President" or "the Union of India represented by the Government of India acting by the President of India" or some such similar expressions and this causes difficulties in practice.

2. In view of the constitutional provisions contained in Article 299(1) read with Article 53(1), 77(1), 292 etc., it is considered that the correct discription of the Government in the contracts made on behalf of the Government of India should be "The President of India" as the Head of the Union of India; otherwise the contracts are liable to be held void and ineffective in law. Such contracts cannot be ratified subsequently.

3. Section 3 of the Indian Stamp Act, 1899 deals with instruments chargeable with duty. Clause (1) to the proviso to the said section provides that no duty shall be chargeable in respect of any instrument executed by, or on behalf of, or in favour of, the Government in cases where, but for this exemption, the Government would be liable to pay the duty chargeable on such instrument. It is, therefore, advisable to include a clause at the end of the contract made on behalf of the Government of India as under:-

> "The stamp duty, if any, chargeable on this contract under the laws of India shall be borne and paid by the Government."

This in effect means that no stamp duty shall be chargeable on the contract.

4. In view of the above, it should be ensured that the correct description of the Government of India in the contracts made on behalf of the Govt. should be "The President of India" and such contracts must be executed on behalf of the President by a person authorised for that purpose under Article 299(1) of the Constitution. It is also

.....2/-

suggested that in such contracts, a clause to the following effect may be inserted in cases where the stamp duty is payable by the Government:-

> "The stamp duty, if any, chargeable on this contract under the laws of India shall be borne and paid by the Govt."

In such an event, no stamp duty shall be chargeable on the contract.

5. Contracts referred to above may be by way of agreements, sale deeds, mortgages, guarantees etc. and appropriate description may be given in the contract as required.

6. Contracts to be hereafter entered into on behalf of the Government of India should be made and executed strictly in accordance with the observations made above.

7. This is for information and guidance of all Ministries/Departments of the Government of India.

8. This issues with the approval of the Law Minister.

.-.-.-.

No. A-14012/5/85-Coord
Government of India
Ministry of Urban Development

Dated:- 27th Oct. 1986

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- CCS(Conduct) Rules,1964-Transactions of property coming within the purview of Rule 18(2) & (3)-Forms for obtaining permission/giving intimation.

The undersigned is directed to forward herewith a copy of O.M.No. 11013/11/85-Estt.(A) dt. 23rd June,1986 for information and necessary action.

Sd/-
(RAJAN S.LALA)
Section Officer

1. All Attached & Subordinate Officers
2. Chief Controller of Accounts
3. All Divisions/Desks/Section in the Sectt.
4. All Under Secy. in the Sectt.

Copy of Ministry of Personnel, public Grievances and Pensions Deptt. of Personnel & Training O.M.No.11013/11/85-Estt.(A) dated 23rd June,1986.

The undersigned is directed to say that in accordance with the provisions of sub-rule(2) of Rule 18 of the CCS(Conduct) Rules,1964, all Government servants coming within the purview of these Rules are required to make a report to the prescribed authority before entering into any transaction of immovable property in their own name or in the name of a member of family. If the transaction is with a person having any official dealings with the Govt. servant the Govt. servant is required to obtain prior sanction of the prescribed authority. Sub-rule(3), ibid provides that all Govt. Servants should give an intimation to the prescribed authority within one month of entering into any transaction of movable property, the value of which exceeds the monetary limits prescribed in that Rule. Incase any such transaction is with a person having official dealing with the Govt. servant, prior sanction of the prescribed authority is necessary.

2. The question of streamlining the procedure for obtaining prior sanction or making a report about the transactions of property by Govt. servants has been considered and it has been decided that all requests for obtaining prior sanction and making intimation about transactions in immovable and movable p roperty may be made in the enclosed standard Forms I and II respectively, devised for this purpose. These forms contain the basic information required by the prescribed authority in all cases for considering a request for grant of permission or taking note of an intimation given by the Govt. Servant. The prescribed authority concerned, if it so desires, may seek any additional information/clarification about the transaction entered into by the Govt. servant, depending upon the facts and circumstances of the case.

Contd....2/-

3. The applications for obtaining sanction or making prior intimation regarding construction of a house will continue to be made in the form prescribed vide this departments O.M.No.11013/5/75-Estt.(A) dated 20th June,1975.

4. Ministry of Agriculature and Cooperation etc. are requested to circulate these forms among all the authorities under their control, who are required to deal with the requests for grant of permission and receive intimations about transactions of property.

Form for giving prior intimation or seeking previous sanction under Rule 18(2) of the CCS(Conduct) Rules,1964 for transaction in respect of immovable property.

1. Name and Designation
2. Scale of pay & present pay.
3. Purpose of application sanction for transaction/ prior intimation of transaction.
4. Whether property is being acquired or disposed of
5. Probable date of acquisition/disposal of property.
6. Mode of acquisition/disposal.
7. (a) Full details about location viz. Municipal No. street/village, Taluk ,district and state in which situated.
   (b) Description of the property, in the case of cultivable land, dry or irrigated land.
   (c) Whether freehold or leasehold.
   (d) Whether the applicat's interested in the property is in full or part. (In case of partial interests, the extent of such interest must be indicated).
   (e) In case the transaction is not exclusively in the name of the Government servant, particulars of ownership and share of each member.
8. Sale/purchase price of the property. (Market value in the case of gifts)
9. In cases of acquisition, source or sources from which financed/proposed to be financed:-*
10. In the case of disposal of property was requisite sanction/intimation obtained/given for its acquisition (A copy of the sanction/acknowledgement should be attached)
11. (a) Name and address of the party with whom transaction is proposed to be made.

*(a) Personal savings

(b) Other sources giving details

Contd.....3/-

(b) Is the party related to the applicant? if so, state the relationship.

(c) Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future?

(d) How was the transaction arranged? (Whether through any statutory body or a private agency through advertisement or through friends and relatives. Full particulars to be given.)

12. In case of acquisition by gift, whether sanction is also required under Rule 13 of the CCS(Conduct)Rules,1964.

13. Any other relevant fact which the applicant may like to mention.

....

DECLARATION

I,...hereby declare that the particulars given above are true. I request that I may be given permission to acquire/dispose of property as described above from/to the party whose name is mentioned in item 11 above.

OR

I,...hereby intimated the proposed acquisition/disposal of property by me as detailed above. I declare that the particulars given above are true.

Station: Signature:

Date: Designation:

-.-

Note: 1. In the above form, different portions may be used according to requirements.

2. Where previous sanction is asked for, the application should be submitted at least 30 days before the proposed date of the transaction.

....

Contd,.......4 /-

FORM-II

Form of giving intimation for seeking previous sanction under Rule 18(3) of the CCS(Conduct)Rules,1964 for transaction in respect of movable property.

---

1. Name of the Government servant.

2. Scale of pay and present pay.

3. Purpose of application-sanction for transaction/intimation of transaction.

4. Whether property is being acquired or disposed of.

5. (a) Probable date of acquisition or disposal of property.

   (b) If the property is already acquired/disposed of -Actual date of transaction.

6. (a) Description of the property (e.g. Car/Scooter/Motor Cycle/Refrigerator/ Radio/Radiogram/Jewellery/Loans/ insurance policies etc.)

   (b) Make, model (and also registration No. in case of vehicle-(s), where necessary.

7. Mode of acquisition/disposal(Purchase/sale gift, mortagage, lease or otherwise.

8. Sale/purchase price of the property (Market-value in the case of gifts)

9. In case of acquisition, source or source; from which financed/proposed to be financed:-
   (a) Personal savings
   (b) Other sources giving details.

10. In the case of disposal of property was requisite sanction/intimation obtained/given for acquisition (a copy of the sanction/acknowledgement should be attached)

11. (a) Name and address of the party with whome transaction is proposed to bemade/has been made.

    (b) Is the party related to the applicant? If so, state the relationship.

    (c) Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future?

Contd....5/-

(d) Nature of official dealings with the party.

(e) How was the transaction arranged? (whether through any statutory body or a private agency through advertisements or through friends and relatives. Full particulars to be given)

12. In the case of acquisition by gifts, whether sanction is also required under Rule 13 of the CCS(Conduct) Rules, 1964.

13. Any other relevant fact which the applicant may like to mention.

....

DECLARATION

I,....................................hereby declare that the particulars given above are ture. I request that I may be given permission to acquired/dispose of property as described above from/to the party whose name is mentioned in item 11 above.

OR

I,...hereby intimate the acquisition/disposal of property by me as detailed above. I declare that the particulars given above are ture.

Station:- Signature:

Date: Designation:

-.-

Note:- 1. In the above form, different portions may be used according to requirement.

2. Where previous sanction is asked for, the application should be submitted at least 30 days before the proposed date of the transaction.

....

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(CONFIDENTIAL BRANCH)

No:- F.7(12)/86-CC Dated:- 5-11-86

Copy forwarded to:-

1. All Departmental Heads.
2. All Sectional Heads with the request to bring it to the notice of their subordinates for necessary action.

/a.k/

(Y.D. Bankata)
Director(Personnel)

NO.A-42011/10/85.Coord(Pt)
Government of India
Ministry of Urban Development
****

Dated: the 13th Oct., 1986.

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT: Supply of Mayur Jugs to Staff Car Drivers-Ban reg.

.....

The undersigned is directed to forward herewith a copy of OM No.F3(12)-E.II(A)/86 dated 4th Sept., 1986 from Ministry of Finance(Deptt. of Expenditure) for information and necessary action.

Sd/-
(RAJAN S. LALA)
Section Officer

To

1. All Attached & Subordinate Offices
2. Principal Accounts Office
3. Admn.III Section
4. US(A).

....

Copy of OM No.F.3(12)-E.II(A)/86 dated 4th Sept., 1986 from Deptt. of Expenditure.

....

Of late it has come to the notice of this Ministry that the Mayur Jugs have been provided to Staff Car Drivers by some Departments. The Mayur Jugs are quite expensive and should not be provided.

However, the Head of Office may at his discretion provide flask type(Thermos) to the Drivers where found necessary.

This issues with the approval of Joint Secy. (Personnel).

Sd/-
(D.THAGESWARAN)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

File No.F2(14)/86-MC/ Dated: the 12th Nov., 1986.

Copy forwarded to all the Heads of the Deptt. for information and necessary action at their end.

ASSTT. SECY.(MC).
12.11.86

संख्या एफ•3§12§-संस्था• 11§क§/86

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली 4 सितम्बर, 1986

कार्यालय ज्ञापन

हाल ही में इस मंत्रालय के ध्यान में यह आया है कि कुछ विभागों में स्टाफ कार ड्राइवरों को मयूर जग प्रदान किए गऐ हैं जग काफी महंगे हैं और प्रदान नहीं किए जाने चाहिऐं।

तथापि कार्यालयाध्यक्ष अपनी इच्छानुसार जहाँ आवश्यक समझे ड्राइवरों को फ्लास्क किस्म के §थर्मस§ प्रदान कर सकते हैं।

यह संयुक्त सचिव§कार्मिक§ के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह०

§डी•ध्यानेश्वरन§
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग मानकीकृत सूची ह के अनुसार।

•• ••••

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II SECTION 3(ii)

No.K-13011/18/84-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahri Vikas Mantralaya)

New Delhi-110011 dated 28.10.86

NOTIFICATION

WHEREAS certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with notice no. F.20(6)/84-MP dated 19.9.86 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within theity days from the date of the said notice

AND WHEREAS no objections or suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notifications in the Gazette of India, Namely:

MODIFICATIONS:

"The land use of an area measuring about 2648.18 sq. yds. falling in Zone D-3 and bounded by Educational Institution (Law Institute) towards its North, residential (Government Bunglows) towards South and East and Public Utility (Electric sub station) towards West is changed from 'Public and semi Public facilities (Dhobi Ghat and Electric sub station sites) and circulation 'to' Governmental use' (Lawyers' Chamber)".

sd/-
(H.K. GHOSH)
DESK OFFICER
TEL: 3017478

To

The Manager
Government of India Press
Mayapuri Ring Road
NEW DELHI 110055.

Copy to:

1. The Secretary Delhi Development Authority Vikas Minar New Delhi (with 20 spare copies) with reference to their letter no. F.20(6)/84-MP/15357/DC&B dated 21.x.86 with the request that officer concerned in the Authority may carry out the consequential modifications in the Master Plan for Delhi, copies thereof may be supplied to the NDMC/MCD and other concerned authorities and publicity may be given through press.

It is also requested that modification indicated in this Notification may please be incorporated in the draft Zonal Development Plan for the area and revised copies of the Zonal Development plan be also sent to the Central Government in due course.

2. The Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi

3. The Secretary, L&B Department, Delhi Administration, Vikas Bhawan, New Delhi

4. The Chief Planner T&CPO IP Estate New Delhi

5. The L&DO Nirman Bhawan, New Delhi

6. The Member Secretary NDMC Town Hall New Delhi

7. The commissioner, Municipal Corporation of Delhi Town Hall Delhi

8. The Director (L) M/O Urban Development New Delhi

9. The Information Officer M/O Urban Development Shahtri Bhavan New Delhi

1. Secretary, Delhi Urban Arts Commission New Delhi

2. Guard File

1. Change of Land Use file

-Sd/-
(H.K. GHOSH)
DESK OFFICER
TEL: 3017478

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

F.2(14)86-MC Dt.31.10.86

Copy forwarded to all the Heads of the Departments for information and necessary action at their end.

Assistant Secretary

भारत के राजपत्र के भाग-2 खण्ड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ

सं0 के-13011/18/94-डी डी.ए

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

...

नई दिल्ली, दिनांक 20.10.06

अधिसूचना

यत: केन्द्रीय सरकार का नीचे लिखे क्षेत्रों के बारे में दिल्ली की बृहत योजना में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 19.9.06 को नोटिस संख्या एफ 20(6)/04 एम.पी. के साथ प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव मांगे गए थे ।

2. और यत: उक्त संशोधन के बारे में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अत: अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दिल्ली की बृहत योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन:-

"जोन डी-13 के अन्तर्गत आने वाले लगभग 2648.18 वर्ग गज क्षेत्रफल का भूमि उपयोग" सरकारी और अर्धसरकारी सुविधाओं" (धोबी घाट और विद्युत सब स्टेशन (स्थल) और "परिचालन" से "सरकारी उपयोग" (वकीलों का चैम्बर) में बदला जाता है, जो उत्तर की ओर शैक्षणिक संस्था (विविध संस्थान), दक्षिण और पूर्व की ओर रिहायशी (सरकारी बंगले) और पश्चिम की ओर सार्वजनिक उपयोगिता (विद्युत सब-स्टेशन) से घिरा है ।"

ह0/-

(एच.के.घोष)
डस्क अधिकारी
दूरभाष : 3017478

सेवा में,
प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली - 110055

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को उनके दिनांक 21.10.86 पत्र संख्या एफ-20(6)/84 एम.पी./15357/डी सी एण्ड बी के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्राधिकरण संबंधित अधिकारी दिल्ली की वृहत योजना में अनुवर्ती संशोधन कर लें उसकी प्रतिलिपि नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेजी जाए तथा इसका समाचार पत्रों द्वारा प्रचार किया जाए ।

यह भी अनुरोध है कि अधिसूचना में उल्लिखित संशोधन को क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप में शामिल किया जाए तथा क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप की संशोधित प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भी यथा समय भेजी जाए ।

2. मुख्य सचिव; दिल्ली प्रशासन दिल्ली ।
3. सचिव, भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य आयोजक नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली
5. भूमि तथा विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
6. सदस्य सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका, टाउन हाल, दिल्ली ।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली ।
8. निदेशक (भूमि) शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
9. सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली ।
11. गार्ड फाइल ।
12. भू उपयोग परिवर्तन फाइल ।

ह0/-

(एच.के.घोष)
डेस्क अधिकारी
फोन नं0 3017478.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 1986/अग्रहायण 3, 1908
No. 483] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 24, 1986/AGRAHAYANA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली 20 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 857(अ). दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल को उक्त सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. 18011(28)/67 यू. डी. दिनांक 14-2-69

के अनुसार प्रत्यायोजित की गयी, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल सहर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद में मुख्य वास्तुविद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थान पर मुख्य योजनाकार टी. सी. पी. ओ. को मनोनीत करते हैं।

[एफ2(6)/85 एम. सी.]
एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 20th November, 1986

NOTIFICATION

S.O. 857 (E) :—In exercise of the powers of the Central Government vested in it under Clause (b) of Sub-Section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) and delegated to him under sub-section (2) of Section 52 of the said Act by that Government vide Notification No. 18011 (28)/67-UD dated 14-2-1969, the Administrator/Lt. Governor of the Union Territory of Delhi is pleased to nominate the Chief Planner, TCPO in place of the Chief Architect, CPWD on the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F 2 (6)/85-MC.]
M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 1987/माघ 2, 1908
No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 1987/MAGHA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली प्रशासन : दिल्ली

(भूमि व भवन विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

अधिसूचना

का. आ. 32(अ):—स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और शहरी विकास (स्वास्थ्य एवं शहरी विकास विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 18011 (28)/67-शहरी विकास, दिनांक 14 फरवरी, 1969 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की अधिनियम संख्या 61)

की धारा 4(1) के उपबन्धों के अनुसरण में प्रशासक दिनांक 1-1-1987 (एफ. एन.) से अगले आदेशों तक कुमारी जनक जुनेजा, आई. ए. एस. (संघ राज्य क्षेत्र) को दिल्ली विकास प्राधिकरण में सचिव के रूप में (प्रतिनियुक्ति पर) नियुक्त करते हैं।

[सं. एफ. 12(62)/86/प्लान/मू. व भ.]

एन. दिवाकर, संयुक्त सचिव (भूमि व भवन)

DELHI ADMINISTRATION : DELHI

(Land and Building Department)

New Delhi, the 21st January, 1987

NOTIFICATION

SO. 32(E).—In pursuance of the Provisions of Section 4(1) of the Delhi Development Act, 1957 (Act No. 61 of 1957) read with Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Department of Health and UD) Notification No. 18011(28)/67-UD dated 14th February, 1969, the Administrator is pleased to appoint Miss Janak Juneja, IAS(UT) on deputation to DDA as Secretary, Delhi Development Authority w.e.f. 1-1-1987 (FN) till further orders.

[No. F. 12(62)/86/Plan-L&B]

N. DIWAKAR, Jt. Secy. (L&B)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB-SECTION(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Internal Security
(Rehabilitation Division)

Jaisalmer House, Mansingh Road,
New Delhi, dated the 6th February,87.

N O T I F I C A T I O N

S.O. .....In exercise of the powers conferred by Sub-Section (I) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954(44 of 1954), the Central Government hereby appoints Assistant Settlement Commissioner, Engineer Officer and Administrative Officer in the Land and Development Office under Ministry of Urban Development as Managing Officers for the purpose of performing in addition to their own duties as Assistant Settlement Commissioner, Engineer Officer and Administrative Officer, the functions of a Managing Officer by or under the aforesaid Act in respect of issue of lease or conveyance deeds of Government built properties in Delhi and New Delhi and conversion of lease-deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties in Delhi and New Delhi forming a part of the Compensation Pool.

This supersedes Notification No.4(42)/83-SS.II(A), dated the 17th April, 1986.

Sd/-
(M.ASLAM)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

No.4(42)/83-SS.II

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road,
New Delhi.

(A copy of the Notification in Hindi is enclosed).

Copy to :-

1. The Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. The Director (Lands), Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
3. Land and Development Officer, Nirman Bhawan, New Delhi.
4. The Deputy Land and Development Officer(II), Land and Development Office, Nirman Bhawan, New Delhi, with reference to his letter No.Admn.14(13)/197/81, dated 3.2.1987. (With 20 spare copies).
5. The Assistant Settlement Commissioner/ Engineer Officer/ Administrative Officer, Land and Development Office, Nirman Bhawan, New Delhi.

Copy also to :-

1. The Vice-Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi.
2. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Chandni Chowk, Delhi.
3. The Secretary, New Delhi Municipal Committee, Palika Bhawan, Sansad Marg, New Delhi.
4. The Parliament Library, Parliament House Annexe, New Delhi.
5. The Secretary General, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House Annexe, New Delhi.
6. The Secretary, Lok Sabha Secretariat, Parliament House New Delhi.
7. The Ministry of Law, Legislative Department, Shastri Bhawan, New Delhi.

Copy also forwarded to:-

1. Settlement Commissioner, Settlement Wing, Jaisalmer House, New Delhi (with 5 spare copies)
2. Sr. PA to AS (J)/JS(S)/CSC.
3. SS.I Section
4. AD.IV Section, Ministry of Home Affairs, North Bloack, New Delhi.
5. Notification folder.

Sd/-
DEPUTY SECRETARY

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

F.2(14)/86-MC. Dated: 10.3.87.

Copy forwarded to all the Heads of the Deptt. for information and necessary action at their end.

Asstt. Secretary(MC)

S.O. No. 5(E) dt. 6.1.87

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 1987/पौष 16, 1908
No. 5] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 1987/PAUSA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1986

सार्वजनिक सूचना

का.आ. 5(अ).—निम्नलिखित संशोधन सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/जोनल योजना में करने का प्रस्ताव है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति या उसके संबंध में सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति या

100

सुझाव इस नोटिस के जारी होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में सचिव, दिल्ली विकास प्राधीकरण, विकास सदन, बी ब्लाक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने या सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

संशोधन :

"लगभग 0.44 हेक्ट. (1 एकड़) क्षेत्र, जो जोन एफ. 3 में महरौली रोड़ के साथ लगता है और जो अनुमोदित जोनल योजना/विकास योजना में आंशिक रूप से (0.08 हेक्ट.) हरित के लिए और आंशिक रूप से (0.36 हेक्ट.) सरकारी और अर्द्ध-सरकारी (स्कूल) के लिए निर्दिष्ट है और जो उत्तर में हरित क्षेत्र, पूर्व में शैक्षणिक उपयोग, दक्षिण में 9 मीटर चौड़ी सड़क तथा पश्चिम में 60 मीटर मार्गाधिकार को महरौली रोड़ से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को "व्यावसायिक" (स्थानीय खरीददारी उपयोग) में बदलने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों को उप-निदेशक, मुख्य योजना विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

[एफ. 3(123)/83 एम. पी.]

एम. पी. जैन, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 30th December, 1986

PUBLIC NOTICE

S.O. 5(E).—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Plan for Delhi, hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block I.N.A., New Delhi, within a period on thirty days from the date of issue of the notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring about 0.44 ha. (1 acre) abutting Mehrauli Road in Zone F-3, earmarked in the approved Zonal Plan|Development Plan, party (0.08 ha.) for green and party (0.36 ha.) for "Public and Semi-Public Facilities" (School) and bounded by green area in the North, educational use in the East, 9 Mt. wide road in the Souh and 60 Mt. R|W road Mehrauli Road in West is proposed to be changed to 'Commercial" (local shopping use)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Dy. Director, Master Plan, Vikas Minar, 6th Floor, I. P. Estate, New Delhi, on all working days within the period referred to above.

[No. F3(123)|83-MP.]

M. P. JAIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RNIG ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987

(To be published in Part I Section 2 of the Gazette of India Extra-ordinary)

No.K.14011/6/87-UD-II
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)

New Delhi, dated 16th April, 1987.

N O T I F I C A T I O N

In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), read with rule 4 of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Works and Housing notification No.K.14011/25/84-NCR dated the 27th March, 1986, published in the Gazette of India Part I-Section2, dated the 28th March, 1986, namely:-

For serial number 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"21. Shri K.K. Bhatnagar, I.A.S. (RJ:62)
Member Secretary".

Sd/-
(R.L. Pardeep)
Jt.Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.

Copy to:-

1. All the members of the N.C.R. Planning Board
2. All Ministries/Departments of Govt. of India
3. Sh. Om Kumar, Vice-Chairman, DDA.

(Pran Nath)
Desk Officer

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

F.2(14)86-MC Dated 25.5.1987

Copy forwarded to all the Heads of Department for information and necessary action at their end.

(B.K. Sharma)
Asstt. Secretary

No.I-24011/2/87-WSU
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)

New Delhi,
Dated 5th May, 1987.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Record Management - Micro filming of records - instructions issued by Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances.

A copy of the O.M. No.24013/5/87-O&M dated 10.4.1987 received from the Department of Administrative Reforms & Public Grievances on the above subject is circulated to all Sections/Divisions in the Ministry and all Attached/Subordinate offices. The concerned Administrative Sections/Divisions may take appropriate action as desired therein.

Sd/-
(K.M. Sarda)
Senior Analyst (WS)

To

1. All Sections/Divisions in the Ministry.
2. All Attached/Subordinate Offices.

Copy for information also to:-

1. All Directors/Deputy Secretaries/Under Secretaries in the Ministry.
2. P.S. to Secy.,
3. P.S. to Adl.Secy. & Adviser (Engg.),
4. P.S. to all JSs

Sd/-
(K.M. Sarda)
Senior Analyst (WS)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

F.2(14)86-MC Dated 25.5.1987

Copy forwarded to all the Heads of Department for information and necessary action at their end.

(S.K. Sharma)
Asstt. Secretary

No.21013/5/87-O&M
Department of Administrative Reforms and Public Grievances
(Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Vibhag)

Sardar Patel Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi-110001, dated 10th April, 1987

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Records Management - Micro-filming of records - instructions regarding.

The undersigned is directed to say that in a meeting held under the Chairmanship of the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions with Secretary, Department of Company Affairs, to review follow up action on the P.M.'s broadcast the following decision inter alia was taken :-

> "The question of micro-filming of records was discussed and it was clarified that the Ministry of Law had advised that the Evidence Act would require amendment to treat micro-film of a document as a primary evidence and that consultation with States for this purpose would be necessary. The Minister of State said that this should be expedited. He also suggested that independently of the proposal to amend the Evidence Act, micro-filming of the records should be started. Only micro-films need be kept in Offices in metropolitan and other big cities while the original records may be kept in buildings situated outside the cities. This would help in relieving pressure on valuable accommodation in prime areas."

As the above decision is applicable to all the Ministries/Departments, it is circulated to them for taking action as considered appropriate.

As for amending the Evidence Act to treat micro-film of a document as primary evidence so as to facilitate destruction of original documents after micro-filming, this Department in pursuing the matter with Ministry of Law.

Sd/-
(V. Balasubramanian)
Deputy Secy. to the Govt. of India
Tele: 312369

All Ministries/Departments

F.No.A.42011/10/85-Coord
Government of India
Ministry of Urban Development

New Delhi dated the 10.3.1987

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- (1) Statehood for Migoram and Arunachal Pradesh.

(2) Entrustment of statutory powers and functions of the Central Government to the Government of new State of Mizoram-issue of directions under Article 258 (1) of the Constitution.

Copies of each of the Office Memorandum No. (1) 12013/72/86 SR dated 16.2.87 and (2) 7/1/87-Judl. dated 17.2.87 received from Ministry of Home Affairs is sent herewith for information and strict compliance.

Sd/-
(K.C.MISHRA)
SECTION OFFICER

To

1. All Attached/Subordinate Offices/Public Sector Undertakings/Statutory and Autonomous Bodies/ Pr. Accounts Office.
2. All Divisions/Desks/Administration Sections in the Secretariat.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

F2(14)/86-MC

Dated : 27.5.87

Copy forwarded to all the heads of Deptt. for necessary action at then end.

Asstt. Secretary. 5/6/87

Copy of M/Home Affairs' O.M.No.12013/2/86-SR dated 16.2.87

As the Ministry of Finance, etc. are aware, the Union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh are to become fullfledged States under the State of Mizoram Act, 1986 and the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 on the "Appointed day" i.e. such day as may be appointed by the Central Government for the purposes of those Acts. This Ministry has appointed the 20th February, 1987 as the appointed day for both those Acts. vide notifications Nos. S.O.72(E) and S.O.74(E), dated 12.2.1987 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated 11.2.87. Therefore, with effect from 20th February, 1987, the new States of Mizoram and Arunachal Pradesh will come into being.

2. The Ministry of Finance etc., are requested to take note of these changes in dealing with the new States.

-.-.-.-.-.-.-

Copy of M/Home Affairs' O.M.No.7/1/87-Judl.dated 17.2.87

As the Ministry of Finance, etc. are aware, the Union territory of Mizoram will become a full-fledged State on the 20th February, 1987 which has been notified by this Ministry as the "appointed day" under the State of Mizoram Act, 1986. As from that date, the Government of Mizoram will automatically be competent to exercise the powers and functions of a "State Government "or"Government" and the powers and functions exercisable by a State Government as the "appropriate Government", under a Central Act and the Rules made thereunder. The Government of the new State cannot, however, exercise any powers and functions of the Central Government under Central Acts unless they are suitably empowered by notification under article 258 (1) of the Constitution.

2. The Ministry of Finance, etc., may, therefore, immediately examine the Acts and Rules with which they are concerned and if they consider it necessary to entrust any powers and functions of the Central Government thereunder to the Government of the new State of Mizoram or to their officers they may take necessary action to issue the necessary notifications under article 258(1) of the Constitution, after consulting their Associate Finance, where necessary and law Ministry.

3. It may please be noted that article 258 (1) of the Constitution provides that powers and functions of the Central Government may be entrusted either conditionally or unconditionally

to a State Government or to its officers only with the consent of the State Government concerned. It will, therefore, be necessary to consult the State Government concerned before entrusting any functions to them or to their officers.

4. This Ministry (Judicial Section) may please be kept informed of the action taken in this behalf.

Sd/- D.N. Sharma
Director.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

No. F.2(14)86-MC

Dated: 5.6.1987

NOTIFICATION

At present the various Circles, Divisions in Engineering Wing in DDA, are given Roman numbers. Some of the divisions were initially started for the Housing, Development, Rehabilitation, Commercial Projects, Resettlement or Asian Games. Inspite of the fact that the divisions are now carrying out all together different works compared to those which they were originally handling, the designation of the divisions continued causing some anamolies. The roman numbers are also very cumbersumeand causing confusion amongst some people. It is also not possible to understand the location of these divisions and its activities from a knowledge of the designation of the divisions.

To streamline the matters, it is decided to simplify and redesignate them with purpose and meaning. Given below are the present designations and names of the various Civil and Electrical Divisions, Civil Circles, Electrical Circles and SEs (Planning) and also their new designations.

CIVIL DIVISIONS

Sl.No.	Present Designation	New Designation
1.	2.	3.
	EAST ZONE	
1.	Housing Division XIV	Eastern Division - 1
2.	Housing Division XV	Eastern Division - 2
3.	Housing Division XVIII	Eastern Division - 3
4.	Housing Division XIX	Eastern Division - 4
5.	Housing Division XX	Eastern Division - 5
6.	Development Division VII	Eastern Division - 6
7.	Development Division VIII	Eastern Division - 7
8.	Development Division IX	Eastern Division - 8
9.	Development Division XI	Eastern Division - 9
10.	Development Division X	Eastern Division - 10
11.	Housing Division XXII	Eastern Division - 11
12.	Housing Division XXIII	Eastern Division - 12
13.	Housing Division XXXI	Eastern Division - 13
14.	Indoor Stadium Division	Eastern Division - 14

ROHINI

15.	Rohini Project Division I	Rohini Project Division - 1
16.	Rohini Project Division II	Rohini Project Division - 2
17.	Rohini Project Division III	Rohini Project Division - 3
18.	Rohini Project Division IV	Rohini Project Division - 4
19.	Rohini Project Division V	Rohini Project Division - 5
20.	Rohini Project Division VI	Rohini Project Division - 6
21.	Housing Division XII	Rohini Project Division - 7
22.	Housing Division XVII	Rohini Project Division - 8
23.	Housing Division XXXVII	Rohini Project Division - 9

SOUTH WEST ZONE

24.	Housing Division I	South Western Division - 1
25.	Housing Division VIII	South Western Division - 2
26.	Housing Division XVI	South Western Division - 3
27.	Housing Division XXI	South Western Division - 4
28.	Commercial Project Divn. III	South Western Division - 5
29.	Housing Division II	South Western Division - 6
30.	Housing Division X	South Western Division - 7
31.	Housing Division XI	South Western Division - 8
32.	Housing Division XXIV	South Western Division - 9
33.	New Division	South Western Division - 10

NORTH ZONE

34.	Construction Division I	Northern Division - 1
35.	Construction Division VI	Northern Division - 2
36.	Construction Division VII	Northern Division - 3
37.	Resettlement Division II	Northern Division - 4
38.	Housing Division XXV	Northern Division - 5
39.	Development Division I	Northern Division - 6
40.	Development Division II	Northern Division - 7
41.	Development Division V	Northern Division - 8
42.	Housing Division XXVI	Northern Division - 9
43.	Asian Games Village II	Northern Division - 10
44.	Housing Division V	Northern Division - 11
45.	Housing Division XXVII	Northern Division - 12
	Resettlement Division I	To be closed.

SOUTH EAST ZONE

46.	Commercial Project Division II	South Eastern Division - 1
47.	Commercial Project Division IV	South Eastern Division - 2
48.	Commercial Project Division V	South Eastern Division - 3
49.	Commercial Project DivisionVIII	South Eastern Division-4
50.	Construction Division II	South Eastern Division -5

51. Arrear Division (AGV)	South Eastern Division - 6
52. Urban Village Division I	South Eastern Division - 7
53. Housing Division VI	South Eastern Division - 8
54. Housing Division XXXV	South Eastern Division - 9
55. Asian Games Village I	South Eastern Division - 10
56. Commercial Project Divn.VII	South Eastern Division - 11
57. New Division.	South Eastern Division - 12
WEST ZONE	
58. Urban Village Division II	Western Division - 1
59. Development Division IV	Western Division - 2
60. Housing Division XIII	Western Division - 3
61. Housing Division XXIX	Western Division - 4
62. Construction Divn. III	Western Division - 5
63. Housing Division XXXIV	Western Division - 6
64. Development Division VI	Western Division - 7
65. Housing Division VII	Western Division - 8
66. Housing Division IX	Western Division - 9
67. Housing Division IV	Western Division - 10
68. Housing Division XXX	Western Division - 11
69. Housing Division XXVIII	Western Division - 12
70. Housing Division XXXII	Western Division - 13
71. Housing Division XXXIII	Western Division - 14
72. Commercial Project Divn. I	Western Division - 15
Commercial Project Divn.VI	To be closed.

ELECTRICAL DIVISION

1. Electrical Division I	Electrical Division - 1
2. Electrical Division II	Electrical Division - 2
3. Electrical Division III	Electrical Division - 3
4. Electrical Division IV	Electrical Division - 4
5. Electrical Division V	Electrical Division - 5
6. Electrical Division VI	Electrical Division - 6
7. Electrical Division VII	Electrical Division - 7
8. Electrical Division VIII	Electrical Division - 8
9. Electrical Division IX	Electrical Division - 9
10. Electrical Division X	Electrical Division - 10
11. Electrical Division XI	Electrical Division - 11

CIRCLES

1. Circle I	Civil Circle - 1
2. Circle II	Civil Circle - 2
3. Circle III	Civil Circle - 3
4. Circle IV	Civil Circle - 4
5. Circle V	Civil Circle - 5
6. Circle VI	Civil Circle - 6
7. Circle VII	Civil Circle - 7

8. Cicle VIII	Civil Circle - 8
9. New Circle (Old Directorat of MM).	Civil Circle - 9
10. Circle X	Civil Circle - 10
11. Circle XI	Civil Circle - 11
12. Circle XII	Civil Circle - 12
13. Circle XIII	Civil Circle - 13
14. Circle XIV	Civil Circle - 14
15. Circle XV	Civil Circle - 15
16. Circle XVI	Civil Circle - 16
17. Circle XVII	Civil Circle - 17
18. Electrical Circle I	Electrical Circle - 1
19. Electrical Circle II	Electrical Circle - 2
20. Electrical Circle III	Electrical Circle - 3
21. S.E. (P) I	Planning Circle - 1
22. S.E. (P) II	Planning Circle - 2
23. S.E. (P) III	Planning Circle - 3
24. S.E. (P) IV	Planning Circle - 4

These designations will be used from Ist June, 1987. Necessary changes may be brought out after suitable intimation in the contracts and also the postal address of the various officials.

Secretary. 17/6/87
D.A

1. All Heads of Offices mentioned above.
2. Finance Member.
3. Engineer Member.
4. OSD to Vice- Chairman.
5. Commissioner (Housing).
6. Commissioner (Land).
7. Chief Architect.
8. All hief Engineers.
9. C.A.O.
10. C.V.O.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

No.F.2(14)/86-M.C. Dated: 1.7.1987.

CORRIGENDUM

In partial modification of Notification No. F.2(14)/86-M.C. dated 5.6.1987 the name of the Divisions indicated at Sl.No. 58 and Sl. No. 60 in the aforesaid notification may be read as under:-

(i) The name of the Division mentioned at Sl.No. 58 may be read as "Urban Village Division No.II" instead of "Urban Village Division No.I".

(ii) The name of the Division mentioned at Sl.No.60 be read as "Housing Division No. XIII" instead of "Housing Division No. XII".

(JANAK JUNEJA)
SECRETARY

1. All the Heads of the Department/Branch Officers, D.D.A.
2. Finance Member.
3. Engineer Member.
4. O.S.D. to Vice-Chairman.
5. Commissioner (Housing).
6. Commissioner (Lands).
7. Chief Architect.
8. All Chief Engineers.
9. C.A.O.
10. C.V.O.

NATIONAL COOPERATIVE HOUSING FEDERATION OF INDIA

M-5, Magnum House - I,
Karampura Community Centre,
New Delhi - 110 015.

NCHF/86-87/1(9)/1669
25th May, 1987

To

All Member Federations, NCHF
All Board of Directors, NCHF
All National Level Federations

Shri Om Kumar, Vice-Chairman,
D.D.A., New Delhi.

Dear Sir,

We wish to inform you that Shri M.L. Khurana who was working as Executive Officer has taken over as the Managing Director of the National Cooperative Housing Feddration of India w.e.f. 25th May, 1987.

All the D.O. letters and confidential letters meant for Executive Officer should be addressed to Shri M.L.Khurana, Managing Director, National Cooperative Housing Federation of India, M-5, Magnum House-I, Karampura Community Centre, New Delhi.

Yours faithfully,

Sd/-

(R.P. SINGH)
Office Suptdt.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F. 2(14)/86-MC

Dated: 15 July 87

Copy forwarded to all the heads of deptt. for information and necessary action at their end.

(B.K. SHARMA)
Assistant Secretary

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES
(DELHI ADMN.) CPO BUILDING, KASHMERE GATE
DELHI

No. F. 2(153)/86/DI/M&Q/5181 Dated the 19.6.87

O R D E R

In supersession of all previous orders on the subject and in exercise of the powers vested in me under Rule 2(b) of the Delhi Minor Mineral Rules, 1969 (as amended from time to time), Shri Ramesh Tiwari, Addl. Distt. Magistrate is hereby authorised with immediate effect to exercise all powers of the Collector under the said Rules, subject to the supervision and control of the undersigned.

Sd/-

(ASHOK PRADHAN)
COLLECTOR OF MINES &
COMMISSIONER OF INDUSTRIES

No. F. 2(153)/86/M&Q/5182-5218 Dated the 19.6.87

Copy for information to:-

1. Chairman-cum-Managing Director/General Manager, Delhi State Mineral Dev. Corpn., Mohan Singh Place, New Delhi.
2. All A.D.Ms. Office of the Dy. Commissioner, Delhi.
3. Vice-Chairman, D.D.A., Vikas Minar, I.P.Estate, New Delhi.
4. Commissioner, M.C.D., Town Hall, Delhi.
5. Administrator, N.D.M.C., New Delhi.
6. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
7. P.S. to Chief Secretary, Delhi.
8. Jt. Secretary(Services), Delhi Admn., Delhi.
9. Secretary(Law & Judicial), Delhi Admn., Delhi.
10. Secretary to CEC, Delhi.
11. All Secretaries to Executive Councillors, Delhi.
12. Secretary(Co-ordination), Delhi Admn., Delhi.
13. Officer Concerned.
14. Director, Mines Safety, Govt. of India, Ministry of Labour Room No.303-305, CGO Complex, Hapur Road, Ghaziabad(UP).
15. All. Jt. Director of Industries, Delhi.
16. Public Relation Deptt., Old Sectt., Delhi with the request to publish the same in the Delhi Gazette.
17. P.A. to C.I.

Sd/-

(ASHOK PRADHAN)
COLLECTOR OF MINES &
COMMISSIONER OF INDUSTRIES

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F. 2(14)/86-MC Dated: 15-7-87

Copy forwarded to all the heads of deptt. for information and necessary action at their end.

(B.K. SHARMA)
Assistant Secretary

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI : LAND & BUILDING DEPARTMENT

Dated: the 8th June, 1987.

CORRIGENDUM

No.F16(1)/86-L&B:- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 12 of the Delhi Development Act, 1957, (61 of 1957) read with Notification of the Govt. of India in the Ministry of Health, Family Planning & Urban Development No.18011(28)/67-UD dated 14.2.1969, the Administrator of Union Territory of Delhi, is pleased to make additions/amendments to the Land & Building Department, Delhi Administration, Delhi's Notification No.F16(1)/86-L&B dated 28.11.1986 for declaring the area as described in the schedule below to be 'Development Area'for the purpose of said Act:-

SCHEDULE

Development Area No.	Area in Hect.	Description
171	About 3550 hects. instead of 2000 hects.	North West : Najafgarh Road North East : Pankha Road South East : Rewari Railway line. South West : Main Oil Pipe Line.

With the declaration of the above said area, the whole land previously falling in Development Area No.150 now comes under Development Area No.171 with effect from 28.11.86. However, the action taken under Development Area No.150 prior to 28.11.1986 shall remain valid for all purposes and thereafter it shall be known as Development Area No.171 with effect from the date of its notification.

By order,

Sd/-

(SMT. NEERU SINGH)
JOINT SECRETARY(LAND & BUILDING)
DELHI ADMINISTRATION:DELHI.

No.F16(1)/86-L&B/21935-949 dated the 8.6.87.

Copy forwarded to:-

1. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Vice-Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
3. Executive Officer(DA), Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
4. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Delhi.
5. Engineer Member, Delhi Development Authority, Vikas Minar, New Delhi.
6. Town Planner, Municipal Corporation of Delhi, Old Hindu College Building, Kashmere Gate, Delhi.
7. Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
8. Secretary to Lt.Governor, Delhi.
9. Secretary to Chief Executive Councillor, Delhi.
10. Secretary to Executive Councillor(Revenue), Delhi.
11. PS to Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi.
12. Under Secretary(Corrd), Delhi Administration, Delhi.
13. Under Secretary(LSG), Vikas Bhawan, New Delhi.
14. Chief Engineer, Delhi Development Authority, Vikas Kuteer, New Delhi.
15. Tehsildar(L&B), Vikas Bhawan, New Delhi.

Sd/-
(MRS. NEERU SINGH)
JOINT SECRETARY(LAND & BUILDING)
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

Typed by Sd/-

Compared by Sd/-

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

F2(14)86-MC

Dated: 20.7.87

Copy forwarded to all the heads of Department for necessary action at their end.

(B.K.Sharma)
Asstt. Secretary.

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE)

LAND & BUILDING DEPARTMENT : DELHI ADMINISTRATION: DELHI

NOTIFICATION

Dated: the 22June, 1987.

No.F.16(1)/87-L&B:- In exercise of powers conferred by Sub-Section(i) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with notification of the Govt. of India in the Ministry of Health, Family Planning & Urban Development No.18011(28)/67-UD dated 14th Februmry, 1969 the Administrator of the Union Territory of Delhi hereby de-notified the following 55 Urban villages declared as 'Development Area'.

SCHEDULE

S.No.	Name of the Urban villages.	S.No.	Name of the Urban villages.
1.	Asalatpur	19.	Khirki
2.	Badli	20.	Katwaria Sarai
3.	Ber Sarai	21.	Krishan Garh
4.	Basant Goan	22.	Khyala
5.	Basai Darapur	23.	Karkar Duma
6.	Gazi Pur	24.	Kachipur
7.	Dhirpur	25.	Khureji Khas
8.	Hauz Khas	26.	Lado Sarai
9.	Hari Nagar Ashram	27.	Mashih Garh
10.	Humayunpur	28.	Mehrauli
11.	Hasanpur	29.	Masoodpur
12.	Jwala Heri	30.	Mangolpur Kalan
13.	Jhilmil Tahirpur	31.	Madipur
14.	Kotla Mubarakpur	32.	Naharpur
15.	Khampur	33.	Naraina
16.	Khichripur	34.	Nangloi Sayad
17.	Kalu Sarai	35.	Okhla
18.	Kotla	36.	Mangolpur Khurd.

Contd...2/-

S.No.	Name of the Urban Village.
37.	Pitam Pura
38.	Posangi Pur
39.	Rampura
40.	Nangloi Jalab
41.	Sarai Julliana
42.	Shahpur Jat
43.	Shadipur
44.	Tughlakabad
45.	Wazirpur
46.	Mangolpuri
47.	Begumpur
48.	Bodhela
49.	Garhi Piran
50.	Khizrabad
51.	Khakurpur
52.	Sahipur
53.	Tekhand
54.	Tatarpur
55.	Masjid Moth.

By order.

Sd/-
(MRS NEERU SINGH)
JOINT SECRETARY(LAND & BUILDING)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

No.F16(1)/87-L&B/23559-74 Dated the 22nd June, 1987.

Copy forwarded to:-

1. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Vice-Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
3. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Delhi.
4. Commissioner(Lands), Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
5. Engineer Member, Delhi Development Authority, Vikas Minar, New Delhi.
6. Town Planner, MCD, Old Hindu College Building, Kashmere Gate, Delhi.
7. Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
8. Secretary to Lt.Governor/C.E.C./E.Cs., Delhi.
9. Under Secretary (LSG), Delhi Administration, Vikas Bhawan, New Delhi.
10. Asstt.Housing Commissioner(Cord.), L&B Deptt., New Delhi.
11. Chief Engineer, Delhi Development Authority, New Delhi
12. Tehsildar(L&B), Vikas Bhawan, New Delhi.
13. PS to Chief Secretary, Delhi.

Sd/-
(MRS. NEERU SINGH)
JOINT SECRETARY (LAND & BUILDING)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

F2(14)86-MC Dt. 20.7.87

Copy forwarded to all the heads of Department for necessary action at their end.

(B.K.Sharma)
Asstt.Secretary.

From:
The Advertisement Manager,
THE INDIAN EXPRESS,
Post Box No. 7126
B. S. Zaffar Marg,
NEW DELHI

TO The Secretary,
DDA, Vikas Sadan
'B' Block, INA
N. Delhi - 23

CERTIFICATE OF INSERTION

Certified that your advertisement as per cutting enclosed has been published in our Indian Express, Delhi dated

दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, नई दिल्ली
केन्द्रीय डायरी कक्ष
काउन्टर
24 AUG 1987
क्रम संख्या .....

Advertisement Manager

PUBLIC NOTICES

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

No. F. 20(5)/87-MP Dated 22.8.87

PUBLIC NOTICE

THE following modification which the Central, Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION:

"The land use of an area, measuring about 36.27 ha. falling in zone E-13 (Part) Mandawali-Fazalpur and bounded by marginal bund to river Yamuna in the South-West and New Railway line to Ghaziabad in the North-West and 45 mtrs. (150') wide Master Plan Road in the North and 60 mtrs. (200') arterial road in the North-East and 90 mtrs. (300') wide National Highway bye-pass in the South-East of the river Yamuna, is proposed to be changed from 'Industrial use' to 'Residential use'."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Dy. Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

Sd/-
(JANAK JUNEJA)
SECRETARY
Delhi Development Authority
Vikas Sadan
'B' Block, I.N.A.,
NEW DELHI.
Dated the 22.8.87

C-7953/87

No.O-11012/10/86-LD
GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(LANDS DIVISION)

....

New Delhi, dt. the 28th June, 1988.

To

Shri V.D.Tiwari,
Chief Engineer (CZ),
Central Public Works Department,
R.K.Puram,
NEW DELHI.

Sub: Payment of compensation/enhanced compensation for acquisition of land.

Sir,

I am directed to invite attention to this Ministry's communications mentioned below and to request that no payments should be made to the parties concerned until further instructions from this Ministry:-

Sl. No.	No. and date of the Communication	Subject	Amount of Payment-Rs.
1.	O-11012/10/86-LD dt.2.3.1988	LAC No.398/72-RFA No.48/78 Sh.Karan Singh Vs.UOI-Award No.883 of LAC-Enhancement of compensation awarded by Delhi High Court.	42,358.99
2.	O-11012/10/86-LD dt.2.3.1988	LAC No.398/72-RFA No.48/78 Sh.Karan Singh Vs.UOI Award No. 883 Village Mohd.Pur, Munirka-Enhancement of compensation awarded by Addl.Distt.Judge, Delhi.	23,464.13
3.	O-11012/10/86-LD dt.25.4.88	LAC No.61/67 RFA No. 390/70 Sh.F.M. Kawalramani Vs.UOI Award No.853 Village Hauz Khas:	16,218.84

.....2/-

4. O-11012/10/86-LD Dt. 21.6.88.	LAC No.373/74,RFA No.213/78 Sh.Ram Sahai Vs. UOI Award No.883,Village Mohdpur Munirka,	6,35,108.17
5. O-11012/10/86-LD Dt. 20.6.88.	LAC No.161/84 Shri P.N.Singh,Vs. UOI Award No.8/80,Village Mehrauli.	1,15,364.79

Yours Faithfully,

Sd/-
(D.P.SINGH)
Director(Lands)

Copy for information and such action as may be considered necessary to:-

1. Director of Audit, CW & M,New Delhi.
2. Finance Division(Lands Unit),Min. of UD.
3. Lt. Governor,Delhi Admn., Delhi.
4. CA,CPWD,Nirman Bhawan,New Delhi.
5. Secretary,DDA,New Delhi.
6. PS to UDM/Secretary/JS(H).
7. Executive Engineer, construction Divn.No.I,CPWD, I.P.Estate,New Delhi.
8. Spare copies (15)

Sd/-
(R.Vishwanathan)
Desk Officer(Lands)
Tele:3017325

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Meeting Cell)

F.No.2(6)88-M.C. Dated: 18.7.88.

Copy to all the Head of depptt. of DDA Office.

Meeting Asstt 18/7/88

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3(ii)

No. K-13011/9/87-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahari Vikas Mantralaya)

New Delhi, dated the 20 th June, 1988.

NOTIFICATION

WHEREAS certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F.3(54)84-MP dated the 4th April, 1987 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received with regard to the said modification, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan;

NOW, THEREFORE; in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notificationin the Gazette of India.

MODIFICATION:

"The land use of an area measuring about 3043 sq.mts. (3645 sq.yds.) known as plot No. 1 (old plot No. 3) Factory Road, falling in zone F-4 (Development plan for Yusuf Sarai area west of Qutab Road, South Delhi) bounded by areas earmarked for 'Governmental use' (Office) towards north, south, west and an approach road (existing adjoining Safdarjang Hospital) in the east is changed from "Governmental use" (Offices) to "Residential use".

(K.V.S. Warier)
Desk Officer

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi. (With Hindi Version)

Copy to:

1. The Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi (with 20 spare copies) with reference to their letter no. F.3(54)84-MP dated 28th Dec., 1987 with the request that consequential modifications may be carried out in the Master Plan for Delhi and copies thereof may be supplied to the NDMC/Municipal Corporation of Delhi/Town and Country Planning Organisation/ Delhi Urban Art Commission and other concerned authorities and publicity may be given through press. It is also requested that modifications indicated in this Notification may be incorporated in the Zonal Development Plan for the area and revised copies of the Zonal Development Plan be also sent to the Central Government in due course.
2. The Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi.
3. The Secretary, Land and Building Department, Delhi Administration, New Delhi.
4. The Chief Planner, Town & Country Planning Organisation I.P. Estate, New Delhi.
5. The Land & Development Officer, Nirman Bhawan, New Delhi.
6. The Member Secretary, New Delhi Municipal Committee, New Delhi.
7. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Delhi.
8. The Director(L), Ministry of Works and Housing, N.Delhi.
9. The Information Officer, Ministry of Works & Housing, New Delhi.
10. The Director General (Works), CPWD, New Delhi.
11. The Secretary, Delhi Urban Art Commission, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi.
12. Guard File.
13. Change of Land Use File.
14. Lands Division, Ministry of Urban Development, N.Delhi.

(K.V.S. Warier)
Desk Officer

भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

सं० के-13011/9/87-डी.डी.II-ए

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20, जून, 1988.

अधिसूचना

यत: निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली के लिए वृहत योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61 वां) के धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 4.4.1987 के नोटिस संख्या एफ०-31541/84-एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) में अपेक्षित आक्षेप सुझाव उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यत: उक्त संशोधनों के बारे में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, तो केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली की वृहद् योजना और क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन : "जोन एफ०-4 (कुतब रोड दक्षिणी दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र की यूसुफ सराय हेतु विकास योजना) में लगभग 3043 वर्ग मी० (3645 वर्ग गज) क्षेत्रफल, जिसे प्लाट सं० 1 (पुराना प्लाट सं० 31, फैक्टरी रोड के नाम से जाना जाता है और जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर सरकारी उपयोग (कार्यालय) के लिए निर्धारित क्षेत्र और पूर्व में पहुंच मार्ग (सफदरजंग अस्पताल के साथ लगते हुए) से घिरा है, का भूमि उपयोग

"सरकारी उपयोग" (कार्यालयों) से "रिहायशी" उपयोग में बदला जाना प्रस्तावित है । "

(के.वी.एस. वारियर)
डेस्क अधिकारी

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को उनके दिनांक 28.12.87 के पत्र सं0 3(54)/87-एम.पी. के संदर्भ में । अनुरोध है कि दिल्ली की वृहत योजना में अनुवर्ती संशोधन करने की कृपा करें और उनकी प्रतिलिपियां नई दिल्ली नगर पालिका/ दिल्ली नगर निगम/नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, दिल्ली नगर कला आयोग तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेजें तथा प्रैस के माध्यम से उनका प्रचार करें । यह भी अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में इस अधिसूचना में उल्लिखित संशोधन को समाविष्ट किया जाए तथा क्षेत्रीय विकास योजना की परिशोधित प्रतिलिपियां यथा समय केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएं ।
2. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
3. सचिव, भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. भूमि तथा विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
6. सदस्य सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली ।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ।

----3-----

8. निदेशक (भूमि), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
9. सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ।
11. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
12. गार्ड फाइल ।
13. भू उपयोग के परिवर्तन की फाइल ।
14. भूमि प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय ।

के. वी. एस. वारियर
(के.वी.एस. वारियर)
डेस्क अधिकारी

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE)
DELHI ADMINISTRATION : DELHI : LAND & BUILDING DEPARTMENT

No. F.16(1)/86-L & B/ Dated the 20th July 1988

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with notification of the Govt. of India in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development No. 18011(28)/67-4D dated 14.2.1969, the administrator of Union Territory of Delhi here by declares more areas in papan kala as described in the schedule given below to be "Development Areas" for the purpose of the said act:-

SCHEDULE

Dev. Area No.	Area in Hect.	Description
172	2098 Hect.	North East -Mathura-Jullunder Oil Pipeline North West -Nazafgarh Road South East -Rowari Line West -Nazafgarh Drain South -Bijwasan Road (including the village abadi area of five villages and Kakrola Dairy Colony).

The existing services in the village abadi areas and Kakrola Dairy Colony be continued to be maintained by the MCD while the agency to undertake the provision of the new services and the development in the abadi villages and the Dairy Colony will be decided by the Administrator at the appropriate time.

By Order

Sd/-
(SMT.NEERU SINGH)
JOINT SECRETARY(LAND & BUILDING)
DELHI ADMINISTRATION : DELHI.

No.F16(1)/86-L&B/25042 Dated the 20th July '88.

Copy forwarded to:-

1. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Vice-Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
3. Executive Officer(D.A), Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
4. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Delhi.
5. Engineer Member, Delhi Development Authority, Vikas Minar, New Delhi.
6. Town Planner, Municipal Corporation of Delhi, Old Hindu College Building, Kashmere Gate, Delhi.
7. Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi.
8. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
9. Secretary to Chief Executive Councillor, Delhi.
10. Secretary to Executive Councillor(Revenue), Delhi.
11. P.S to Chief Secretary, Delhi Administration, Delhi.
12. Under Secretary(Corrd), Delhi Administration, Delhi.
13. Under Secretary(LSG), Vikas Bhawan, New Delhi.
14. Chief Engineer, Delhi Development Authority, Vikas Kuteer, New Delhi.
15. Tehsildar (L&B), Vikas Bhawan, New Delhi.

Sd/-
(MRS. NEERU SINGH)
JOINT SECRETARY (LAND & BUILDING)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI

MEETING CELL: DD.

F2(6)88-M.C. Dated: 26.7.88.

Copy forwarded to all head of Deptt.

21.7.88
Asstt. Secretary
Meeting Cell

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3 SUB SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA.

No. K-11011/22/78/DDIA/IIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Shahri Vikas Mantralaya)
(Delhi Division)

New Delhi, dated the 9th December, 88.

NOTIFICATION

In excercise of the powers conferred by sub-section (I) read with clause (g) of sub-section(3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957, (61 of 1957) and in supersession of the Ministry of Urban Development the then Ministry of Works and Housing Notification No. K-11011/22/78/DDIA/IIB dated the 9th August, 1984, the Central Government hereby appoints Shri S.P. Singal, Director, Ministry of Urban Development as a Member of the Delhi Development Authority in place of Shri R.L. Pardeep, and makes the following further amendments in the Notification of the Govt. of India in the Ministry of Health No. 12-173/57-ISG dated the 30th December, 1957, namely:-

In the said Notification, in item 9, for the entry " Shri R.L.Pardeep" the following entry shall be substituted namely:-"Shri S.P. Singal".

(Rajinder Singh)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi (with Hindi version).

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

संख्या के-11011/22/78-डीडीए/IIबी
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9.12.1988.

अधिसूचना

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 के उपधारा (3) के खण्ड (ज) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा शहरी विकास मंत्रालय (तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्रालय) की दिनांक 9 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या के-11011/22/78/ डीडीए/IIबी के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक, श्री स० प० सिंगल को दिल्ली विकास प्राधिकरण में श्री आर० एल० प्रदीप के स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 30 दिसम्बर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-173/57-आई.एस.जी. में निम्नलिखित आगे और संशोधन करती है ; अर्थात :-

उपर्युक्त अधिसूचना में मद संख्या 9 पर प्रविष्टि "श्री आर० एल० प्रदीप" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये नामत :-
"श्री स० प० सिंगल" ।

डायरी सं. 1193 22-12-88

403-पी-मित्र 21-12-88

P/U in the file 22/XII

ASI.E

(राजिन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक, MA
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

— 2/-

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 1988/ज्येष्ठ 20, 1910
No. 303] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 1988/JYAISTHA 20, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1988

का० आ० 561 (अ).—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अंतर्गत श्री बलवान सिंह सोलंकी और श्री हरीचंद वर्मा को दिल्ली नगर निगम द्वारा पुनः निर्वाचित कर लिया गया है और श्री जनार्दन शर्मा को श्री आ० के० त्यागी के स्थान पर दिनांक 12-10-87 से निर्वाचित किया गया है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् में निगम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे।

[एफ. सं० एफ. 5(1)79-एम. सी. भाग-1]

जनक जुनेजा, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 1988

S.O. 561(E).—It is hereby notified that under clause (d) of Sub section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) S|Sh. Balwan Singh Solanki and Sh. Hari Chand Verma have been re-elected by the Municipal Corporation of Delhi and Sh. Janardan Sharma has been elected in place of Sh. R. K. Tyagi to serve as Corporation's representative on the Advisory Council of Delhi Development Authority w.e.f. 12-10-87.

[F. No. F. 5(1)79-MC. Pt. I]

JANAK JUNEJA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988

9348
28/3/89

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3 SUB SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

No. K-11011/22/78-DDIA/IIB/Vol.II.
Government of India
Ministry of Urban Development

New Delhi, dated the 2nd March, 1989.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby nominates Shri D.S.Meshram, Chief Planner, TCPO, as a member of the Delhi Development Authority in place of Shri E.F.N.Ribeiro and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health Notification No.12-173/57-LSG dated 30.12.57, namely:-

In the said Notification, in item 10-A for the entry "Shri E.F.N.Ribeiro" the following entry shall be substituted namely:- "Shri D.S.Meshram".

S.P. Singal
(S.P.SINGAL)
DIRECTOR(DD)

To
The Manager
Govt. of India Press
Mayapuri, Ring Road
New Delhi(with Hindi version).

Copy to:-

1. All Ministries of Government of India.
2. Shri Romesh Bhandari, LG, Raj Niwas, Delhi.
3. Shri K.S.Bains, VC,DDA,Vikas Sadan, New Delhi.
4. Shri V.S.Murthy,Engineer Member,DDA,Vikas Sadan,New Delhi.
5. Shri S.K.Mishra,Finance Member,DDA,Vikas Sadan,New Delhi.
6. Mrs.Adarsh Mishra,Secretary(L&B),Delhi Admn.,Vikas Bhawan, New Delhi.
7. Shri Ganga Dass,Commissioner,MCD,Town Hall,Delhi.
8. Shri Dharam Dutt,Administrator,NDMC,Town Hall,New Delhi.
9. Shri D.S.Meshram,Chief Planner,TCPO,Vikas Bhavan,New Delhi.
10. Ms.Janak Juneja,Secretary,DDA,Vikas Sadan,New Delhi.
11. Press Information officer,M/o Urban Development,Shastri Bhavan, New Delhi.

S.P. Singal
(S.P.SINGAL)
DIRECTOR(DD)

Contd ....2.

भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ ।

सं० के-11011/22/78-डी.डी.आई.-ए/II-बी/खण्ड-II

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

...

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 1989.

अधिसूचना

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (छ) द्वारा पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक श्री डी.एस.मेश्राम को श्री ई.एफ.एन. रेबिरो के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 30.12.57 की अधिसूचना सं० 12-173/57-एल.एस.जी. में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि "श्री ई.एफ.एन. रेबिरो" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाय नामत: "श्री डी.एस. मेश्राम"

(एस.पी. सिंघल)

निदेशक (डी.डी.)

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय ।
2. श्री रोमेश भण्डारी, उप-राज्यपाल, राज निवास, दिल्ली ।
3. श्री के.एस. बेन्स, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली ।

....2....

Ph: 232507
2518268
Kashmere Gate
Delhi-6

xxxxxxxxx

F.1(53)/87-ISBT/DDA/ 15330

9/3/89

H.S.Dogra,
General Manager(ISBT)

Shri S.P. Singal,
Director (Delhi Division),
Ministry of Urban Development,
Nirman Bhawan, New Delhi

Sub:- Draft Delhi Development Authority (Registration of Porters for ISBT) Rules, 1987

Sir,

I am directed to say that the Authority vide Resolution No. 147 dated the 12th December, 1988 has approved the draft Delhi Development Authority (Registration of Porters for ISBT) Rules, 1987. Two attested copies of the said rules are enclosed herewith.

2. As per Section-6 of the D.D.A. Act read with Clause (r) of Sub-Section-2 of Section-56, you are requested to kindly obtain approval of the Central Government for framing of the above said Rules and publish them in the official gazette.

Yours faithfully,

(H.S. Dogra)
General Manager(I.S.B.T.)

Encl as above

Copy to:-

1. O.S.D. to V.C., for kind information.
2. Secretary,DDA, for kind information.

(H.S. Dogra)
General Manager(I.S.B.T.)

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3(__)

No. K-13011/2/88-DDIIA/VA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

...

New Delhi, dated the

NOTIFICATION

WHEREAS certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F.20(12)/79-MP dated 13.11.82 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received with regard to the said proposed modification, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

"The land use of the area (Plot No. 115), measuring about 3.66 hect. (9.09 acres) falling in Zone D-9 (Central Vista Zone) bounded by 36.57 metres wide Pandit Pant Marg on the West, Lok Sabha Bhavan plot on the South East and 60.09 metres wide Talkatora Road on the east, is changed from 'Recreational' use ' to government & semi-government offices".

(Arjan Dev)
Desk Officer

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi. (With Hindi Version)

Copy to :-

1. The Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi (with 20 spare copies) with reference to their letter No. F.20(12)/79-MP/61 dated the 18th January, 1989 with the request that consequential modifications may be carried out in the Master Plan for Delhi and copies thereof may be supplied to the NDMC/Municipal Corporation of Delhi/Town and Country Planning Organisation/Delhi Urban Art Commission and other concerned authorities and publicity may be given through Press. It is also requested that modifications indicated in this Notification may be incorporated in the Zonal Development Plan for the area and revised copies of the Zonal Development Plan be also sent to the Central Government in due course.
2. The Chief Secretary, Delhi Admn., Delhi.
3. The Secretary, Land & Building Department, Delhi Admn., New Delhi.
4. The Chief Planner, Town & Country Planning Organisation I.P. Estate, New Delhi.
5. The Land & Development Officer, Nirman Bhawan, New Delhi.
6. The Member Secretary, New Delhi Municipal Committee, New Delhi.
7. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Delhi.
8. The Deputy Secretary (L), Min. of Urban Development, New Delhi.
9. The Information Officer, Ministry of Urban Development New Delhi.
10. The Director General (Works), CPWD, New Delhi.
11. The Secretary, Delhi Urban Art Commission, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi.
12. Guard File.
13. Change of land use file.
14. Lands Division, Ministry of Urban Development, New Delhi.

(Arjan Dev)
Desk Officer

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3(II) में प्रकाशनार्थ)

सं0 के-13011/7/87-डी.डी.IIए/IV ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अर्धावर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहत योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1987 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13.11.1982 के नोटिस संख्या एफ0 20(12)79 एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यतः उक्त प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहत योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :-

"लगभग 3.66 हैक्टेयर माप के क्षेत्र (9.09 एकड़ जोन डी-9 सेन्ट्रल वीस्टा जोन के अन्तर्गत है) जो पश्चिम में 36.57 मीटर चौड़े पंडित पंत मार्ग, दक्षिण पूर्व की ओर लोक सभा भूखण्ड और पूर्व में 6.09 मीटर चौड़े तालकटोरा मार्ग से घिरा है, का भूउपयोग" सरकारी कार्यालयों के मनोरंजनार्थ उपयोग में परिवर्तित कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)
(अर्जन देव)
डेस्क अधिकारी

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आइ.एन.ए., नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को उनके दिनांक 18.1.1989 के पत्र सं0 20(12)/79-एम.पी./6 के संदर्भ में (अनुरोध है कि दिल्ली की बृहत योजना में अनुवर्ती संशोधन करने की कृपा करें और उनकी प्रतिलिपियां नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम/नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, दिल्ली नगर कला आयोग तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेजें तथा प्रैस के माध्यम से उनका प्रचार करें। यह भी अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में इस अधिसूचना में उल्लिखित संशोधन को समाविष्ट किया जाए तथा क्षेत्रीय विकास योजना की परिशोधित प्रतिलिपियां यथा समय केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएं।
2. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
3. सचिव, भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली।
4. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. भूमि तथा विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. सदस्य सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली।
8. उप सचिव (भूमि), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
11. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाइल।
13. भू उपयोग के परिवर्तनार्थ की फाइल।
14. भूमि प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय।

अर्जन देव

(अर्जन देव)
डैस्क अधिकारी

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

सं0 के-13011/14/85-डी.डी.IIए/V ए

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

यत: निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिसूचित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहत योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 2.4.1988 के नोटिस संख्यो एफ.7(6)/82-एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे ।

और यत: उक्त प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहद् योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है ।

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद् योजना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन :-

"उत्तर में हवाई अड्डा (इंदिरा गांधी) (सम्पर्क मार्ग), दक्षिण में मरथल गांव और बिजवासन खसरा सं0 66,67/5, 68/2, पूर्व में अंसल प्रोपर्टी खसरा सं0 9,12,19, और 22 से घिरे और पश्चिम में रिवाड़ी जाने वाली रेलवे लाईन से घिरे लगभग 80 एकड़ क्षेत्र के भूमि उपयोग को "कृषि हरित पट्टी" से "भांडागार एवं भंडार" (पेट्रोलियम उत्पाद) में बदले जाने का प्रस्ताव है ।"

अर्जन देव

(अर्जन देव)
डेस्क अधिकारी

सेवा में;

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को उनके दिनांक 3.3.1989 के पत्र सं0 7(6)/82-एम.पी./237 के संदर्भ में (अनुरोध है कि दिल्ली की वृहद् योजना में अनुवर्ती संशोधन करने की कृपा करें और उनकी प्रतिलिपियां नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम/नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, दिल्ली नगर कला आयोग तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेजें तथा प्रेस के माध्यम से उनका प्रचार करें। यह भी अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में इस अधिसूचना में उल्लिखित संशोधन को समाविष्ट किया जाए तथा क्षेत्रीय विकास योजना की परिशोधित प्रतिलिपियां यथा समय केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएं।
2. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
3. सचिव, भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली।
4. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. भूमि तथा विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. सदस्य सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली।
8. डेप सचिव (भूमि), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
11. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाइल।
13. भू उपयोग के परिवर्तनार्थ की फाइल।
14. भूमि प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय।

अ.दे.

(अर्जन देव)
डेस्क अधिकारी

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3 (ii)

No. K-13011/14/85-DDIIA/VA
Government of India
Ministry of Urban Development

.....

New Delhi, dated the April, 89

NOTIFICATION

WHEREAS certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder were published with Notice No. F.7(6)/82-MP dated 2.4.88 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions, as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received with regard to the said proposed modification, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION

" The land use of an area, measuring about 80 acres bounded by Airport (I.G.) connecting road in the North, Village Bharthal and Bijwasan Khasra Nos. 66, 67/5, 68/2 in the South, Ansal Property Khasra No. 9, 12, 19 & 22 in the East and bounded by Railway line to Rewari in the West, is changed from "Agricultural green belt" to "Warehousing and Storage" (Petroleum products).

Arjan Dev

(Arjan Dev)
Desk Officer

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi (With Hindi Version)

...2/-

Copy to :-

1. The Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi (with 20 spare copies) with reference to their letter No. F.7(6)/82-MP/237 dated 3.3.89 with the request that consequential modifications may be carried out in the Master Plan for Delhi and copies thereof may be supplied to the NDMC/Municipal Corporation of Delhi/Town and Country Planning Organisation/Delhi Urban Art Commission and other concerned authorities and publicity may be given through Press. It is also requested that modifictions indicated in this Notification may be incorporated in the Zonal Development Plan for the area and revised copies of the Zonal Development Plan be also sent to the Central Government in due course.
2. The Chief Secretary, Delhi Admn., Delhi.
3. The Secretary, Land & Building Deptt., Delhi Admn. New Delhi.
4. The Chief Planer, Town & Country Planning Organisation, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Land & Development Officer, Nirman Bhawan, New Delhi.
6. The Member Secretary, New Delhi Muhicipal Committee, New Delhi.
7. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Delhi.
8. The Deputy Secretary (L), Ministry of Urban Development New Delhi.
9. The Information Officer, Ministry of Urban Development, New Delhi.
10. The Director General (Works), CPWD, New Delhi.
11. The Secretary, Delhi Urban Art Commission, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi.
12. Guard File.
13. Change of land use file.
14. Lands Division, Ministry of Urban Development, New Delhi.

(Arjan Dev)
Desk Officer

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

संख्या. के-13011/19/86-डी.डी.IIए/I/ए   नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 89

अधिसूचना

यह निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिवर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 13.8.88 के नोटिस संख्या 20(11) 86-एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-एकी उप-धारा (3) में अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीयविकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:-

"दक्षिण दिल्ली में मैदानगढ़ी गांव के निकट "कृषि/हरित पट्टी" के लिए निर्धारित क्षेत्र में से 100 एकड़-खसरा संख्या-571(26-16) 572 (20-0), 573(23-17) 574 (50-00), 575(29-11), 631(30-00) में से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय) में बदलने का प्रस्ताव है"।

(हस्ताक्षर)

(बी.सी. सिंघल)

डेस्क अधिकारी

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II
SECTION 3 (ii)

No.K-13011/19/86-DDIIA/VA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

...

New Delhi, dated the 31 July, 1989.

NOTIFICATION

WHEREAS certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with notice No.F.20(11)88-MP dated 13.8.88 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from date of the said notice;

WHEREAS no objections and suggestions have been received with regard to the said proposed modification;

WHEREAS the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION

"An area measuring 100 acres Khasra No[illegible]571(26-16) 572(120-0)573(23-17)574(150-00)575(129[illegible]631(30-00) out of the area earmarked for 'Agricultural Green Belt' near village Maidan Garhi in South Delhi, is changed to 'Public and Semi-public Facilities' (Indira Gandhi National Open University)".

(B.C. Shyngle)
Desk Officer

To
The Manager
Government of India Press,
Mayapuri Ring Road,
New Delhi. (With Hindi Version)

... 2/-

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एस.ए., नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को उनके दिनांक 3.3.89 के पत्र सं0 एफ-20 (11)/86-एम.पी./238 के संदर्भ में (अनुरोध है कि दिल्ली की मुख्य योजना में अनुवर्ती संशोधन करने की कृपा करें और उसकी प्रतिलिपियां नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, दिल्ली नगर कला आयोग तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेज तथा प्रेसमाध्यम से उचित प्रचार करें। यह भी अनुरोध है कि इस पत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में इस अधिसूचना में प्रस्तावित संशोधन को समाविष्ट किया जाए तथा क्षेत्रीय विकास योजना की परिशोधित प्रतिलिपियां यथा समय केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएं।
2. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन दिल्ली।
3. सचिव, भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन नई दिल्ली।
4. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. भूमि तथा विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. सदस्य सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली।
8. उप सचिव, (भूमि), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
11. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाइल।
13. भू-उपयोग के परिवर्तनार्थ की फाइल।
14. भूमि प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय।

डेस्क अधिकारी

Copy to :-

1. The Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi(with 20 spare copies) with reference to their letter No. F.20(11)/86-MP/238 dated 3.3.1989 with the request that consequential modifications may be carried out in the Master Plan for Delhi and copies thereof may be supplied to the NDMC/Municipal Corporation of Delhi/Town and Country Planning Organisation Delhi Urban Art Commission and other concerned authorities and publicity may be given through Press. It is also requested that modifications indicated in this Notification may be incorporated in the Zonal Development Plan for the area and revised copies of the Zonal Development Plan be also sent to the Central Government in due course.
2. The Chief Secretary, Delhi Admn., New Delhi.
3. The Secretary, Land & Building Deptt.Delhi Admn., New Delhi.
4. The Chief Planner, Town & Country Planning Organisation, I.P.Estate, New Delhi.
5. The Land & Development Officer, Nirman Bhavan, New Delhi.
6. The Member Secretary, New Delhi Municipal Committee, New Delhi.
7. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Delhi.
8. The Deputy Secretary(L), Min. of Urban Development, New Delhi.
9. The Director General (Works), C.P.W.D., New Delhi.
10. The Information Officer, Ministry of Urban Development, New Delhi.
11. The Secretary, Delhi Urban Art Commission, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi.
12. Guard File.
13. Change of land use file.
14. Lands Division, Ministry of Urban Development, New Delhi.

(B.C. Shyngle)
Desk Officer

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

संख्या. के-13011/19/86-डी.डी.IIए/I/ए   नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 89

अधिसूचना

यह निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिवर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 13.8.88 के नोटिस संख्या.20(11)86-एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-एकी उप-धारा (3) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीयविकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद्‌द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:-

"दक्षिण दिल्ली में मैदानगढ़ी गांव के निकट "कृषि/हरित पट्टी" के लिए निर्धारित क्षेत्र में से 100 एकड़-खसरा संख्या 571(26-16) 572 (20-0), 573(23-17)574 (50-00), 575(29-11), 631(30-00) में से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय) में बदलने का प्रस्ताव है"।

(बी.सी. सिंघल)
डेस्क अधिकारी

सेवा में,
प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

...2/

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II SECTION 3 (ii)

No.K-13011/19/86-DDIIA/VA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

...

New Delhi, dated the 31 July, 1989.

NOTIFICATION

WHEREAS certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with notice No.F.20(11)86-MP dated 13.8.88 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from date of the said notice;

WHEREAS no objections and suggestions have been received with regard to the said proposed modification;

WHEREAS the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development plan;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION

"An area measuring 100 acres Khasra Nos. 571(26-16) 572(120-0) 573(23-17) 574(150-00) 575(129-11) 631(30-00) out of the area earmarked for 'Agricultural Green Belt' near village Maidan Garhi in South Delhi, is changed to 'Public and Semi-public Facilities' (Indira Gandhi National Open University)".

(B.C. Shyngle)
Desk Officer

To
The Manager
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi. (With Hindi Version)

... 2/-

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को उनके दिनांक 3.3.89 के पत्र सं० एफ-20(11)/86-एम.पी./238 के संदर्भ में (अनुरोध है कि दिल्ली की वृहद योजना में अनुवर्ती संशोधन करने की कृपा करें और उनकी प्रतिलिपियां नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली नगर निगम, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, दिल्ली नगर कला आयोग तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेजें तथा प्रेस माध्यम से उनका प्रचार करें । यह भी अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना में इस अधिसूचना में उल्लिखित संशोधन को समाविष्ट किया जाए तथा क्षेत्रीय विकास योजना की परिशोधित प्रतिलिपियां यथा समय केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएं ।
2. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन दिल्ली ।
3. सचिव, भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन नई दिल्ली ।
4. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. भूमि तथा विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
6. सदस्य सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली ।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ।
8. उप सचिव, (भूमि), शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
9. सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ।
11. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।
12. गार्ड फाइल ।
13. भू-उपयोग के परिवर्तनार्थ की फाइल ।
14. भूमि प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय ।

(हस्ताक्षर) ( )

डेस्क अधिकारी

Copy to :-

1. The Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi(with 20 spare copies) with reference to their letter No. F.20(11)/86-MP/238 dated 3.3.1989 with the request that consequential modifications may be carried out in the Master Plan for Delhi and copies thereof may be supplied to the NDMC/Municipal Corporation of Delhi/Town and Country Planning Organisation Delhi Urban Art Commission and other concerned authorities and publicity may be given through Press. It is also requested that modifications indicated in this Notification may be incorporated in the Zonal Development Plan for the area and revised copies of the Zonal Development Plan be also sent to the Central Government in due course.
2. The Chief Secretary, Delhi Admn., New Delhi.
3. The Secretary, Land & Building Deptt.Delhi Admn., New Delhi.
4. The Chief Planner, Town & Country Planning Organisation, I.P.Estate, New Delhi.
5. The Land & Development Officer, Nirman Bhavan, New Delhi.
6. The Member Secretary, New Delhi Municipal Committee, New Delhi.
7. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Delhi.
8. The Deputy Secretary(L), Min. of Urban Development, New Delhi.
9. The Director General (Works) ,C.P.W.D., New Delhi.
10. The Information Officer, Ministry of Urban Development, New Delhi.
11. The Secretary, Delhi Urban Art Commission, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi.
12. Guard File.
13. Change of land use file.
14. Lands Division, Ministry of Urban Development, New Delhi.

(B.C. Shyngle)
Desk Officer

100 + 53 = 153